चिंतन

कश्मीर को आतंकमुक्त करने के तेज प्रयास हों

कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत को और कड़ा कदम उठाना होगा। करीब 9 वर्ष से जारी ऑपरेशन क्लीन के बावजूद घाटी आतंकमुक्त नहीं हो सका है। इसके और तेज प्रयास किया जाना चाहिए। यह तय है कि आतंकवाद के पीछे सीमा पार की ताकत है और वह वर्षों से इसी पैटर्न पर है, इसलिए भारत को अपनी रणनीति में सभी पहलुओं को शामिल करना होगा। सीमा पर के आतंकी ठिकानों पर भी कड़ा प्रहार करना होगा। बेशक यह कठिन और लंबा रास्ता है, पर भारतीय सुरक्षा बलों को कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। अभी वहां विधानसभा चुनाव हुए हैं, चुनी हुई नई सरकार अस्तित्व में आई है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यभार संभालते ही गांदरबल में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उमर गांदरबल से विधायक भी हैं। यह आतंकवादी हमले उमर सरकार के बनने और पाकिस्तान की ओर से भारत से वार्ता की पहल के संकेत आने के बाद हुए हैं। दस साल बाद हुए चुनाव के बाद आई नई सरकार के लिए प्रदेश को सुरक्षित बनाना चुनौती रहेगी। सीएम उमर ने आतंकवादी हमले को उग्रवादी हमले बता कर बड़ी घटना पर हल्की प्रतिक्रिया दी है, उमर को प्रतिक्रिया देने में शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। इससे गलत संदेश जाएगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में सात लोगों की मौत हुई है। धारा 370 के अधिकांश प्रावधान के हटने के बाद से कश्मीर में आतंकी हमले में बाहरी मजदूर व पर्यटक निशाने पर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी हमला का एक पैटर्न भी है, जब भी स्थिति बेहतर होने लगती है, आतंकी गुट हमला करते हैं। या फिर जब पाकिस्तान सरकार भारत के साथ मैत्री के रास्ते तलाशने लगती है, तब पाक में सक्रिय आतंकी गुट कश्मीर में आतंकी हमला करवाते हैं। अभी एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) की बैठक में हिस्सा लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे, इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, पर पाक व भारत की ओर से भाषणों में तल्खी से बचा गया और पाक पीएम शाहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इसके बाद पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की ओर से भारत से वार्ता की आकांक्षा संबंधी बातें कही गईं। पाक एस्टब्लिशमेंट यानी आईएसआई और फौज को कभी यह गंवारा नहीं होता कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल करे। यह स्थिति पाक के पूर्व पीएम लियाकत अली के समय से है। जब-जब पाकिस्तान की सरकार ने भारत से संबंध सुधारने की बात की, पाकिस्तान एस्टब्लिशमेंट ने आतंकी हमले के जरिये इसे डिरेल की। यह पाक एस्टब्लिशमेंट ही है, जिसके दबाव के चलते पाक के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा से बीच में वार्ता छोड़कर चले गए थे। पाक एस्आब्लिशमेंट किन विदेशी ताकतों के इशारे पर चलते हैं यह अब छिपी हुई नहीं है। पाक फौज भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनने के समय से भारत के खिलाफ दुश्मनी पाली हुई है और इस दुश्मनी के चलते अपने ही मुल्क पाक को आतंकवादी गुटों का पनाहगाह बना दिया, जिसका दंश अब पाक खुद झेल रहा है। भारत का स्टैंड साफ है, पाक पहले भारत के खिलाफ आतंकवाद बंद करे, फिर शांति वार्ता के लिए आएं। भारत सीमा पार आतंकी घुसपैठ व आतंकी हमले से पीड़ित है। भारत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब हल्लाबोल की जरूरत है। भारत को सीमा के अंदर व बाहर दोनों तरफ के आतंकी ठिकानों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। गांदरबल में कायराना आतंकी हमला निंदनीय है, शर्मनाक है, अस्वीकार्य है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ इतना कड़ा संदेश देना होगा कि किसी को भी भारत के खिलाफ सोचने में भी डर लगे।

जयंती
कृष्ण प्रताप सिंह

अदम गोंडवी: 'अपनों' पर भी चलाए तंजों के तीर

जनकवि अदम गोंडवी को (22 अक्टूबर, 1947-18 दिसम्बर, 2011) आमतौर पर इस बात के लिए याद किया जाता है कि वे जीवनभर दलित व वंचित तबकों की आवाज बने रहकर और बेबाक होकर सत्ताओं से उनके सवाल पूछते रहे। इसके लिए जरूरी हुआ तो अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने, मठ व गढ़ सब तोड़ने, यहां तक कि 'अपनों' को नाराज करने से भी परहेज नहीं किया। याद कीजिए, अपने वक्त में अ दम का सबसे बड़ा और सबसे तल्ख सवाल कौन-सा था? सौ में सत्तर आदमी जब देश में नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिये देश ये आजाद है? उनकी विशेषता यह कि वे इसे दूसरों से ही पूछकर नहीं रह गये थे, खुद से भी पूछा था और जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गये थे कि सौ में सत्तर आदमी इसलिए नाशाद हैं, क्योंकि जिस रामराज्य का वे सपना देख रहे थे, उसका वेश बदलकर किसी और आंगन में उतार लिया गया है। तब उन्होंने लिखा: काजू भुने पलेट में ह्विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। दरअसल, उनके कवि का बड़प्पन ही इसी बात में है कि उसने दारुण से दारुण परिस्थितियों में भी न अपने सवाल बदले, न ही उन्हें पूछने के अपने

उसूल से समझौता किया। कोई अपना उसके सपनों का 'दुश्मन' बनकर सामने आ खड़ा हुआ तो भी न हकलाया, न ही उसकी लप्पो-चप्पो पर उतरा। यही कारण है कि अदम की प्रश्नाकुलता ने चिराग तले का कतई कोई अंधेरा सृजित नहीं किया। इतना ही नहीं, जो महानुभाव उनकी बहुत इज्जत करते, अपनी सोहबत में रखते, उनकी दुर्दशा पर रहम करते, दया दिखाते और साथ खाते-पीते या उन्हें खिलाते-पिलाते थे, उनके 'अंधेरों' के प्रति भी नरम नहीं, बल्कि निर्मम रुख ही अपनाया। मिसाल के तौर पर, उत्तर प्रदेश के जिस गोंडा जिले में उनका घर था, उसके एक जिलाधिकारी उनके मित्र थे और यह सोचकर अपने स्याह-सफेद की परदेदारी कि बिना उन्हें अपने ड्राइंग रूम में बैठाते थे कि भले आदमी हैं वे, कवि तो हैं ही अदम ने उनके ड्राइंगरूम में जो कुछ भी देखा उसे बेबाकी से लिखा। उनके गांव के एक सरपंच ने, जिसका उन पर कई 'उपकारों' का दावा था, अपनी पहुंच का बेजा इस्तेमाल करके रामसुधी नाम की गांव की लाचार वृद्धा की झोपड़ी अपनी चौपाल में मिला ली, तो उन्होंने लिखा: बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, रमसुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। दरअसल, अदम के लिए अपनी शायरी में ईमानदार व जनोन्मुख होना शब्दों के चमत्कार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था और वे अपने शुरुआती दौर में ही सामंतों व सवर्णों को दलितों के कठिन जीवन का ताप महसूस कराने के उद्देश्य से 'चमारों की गली' शीर्षक लम्बी मर्मभेदी रचना लिखकर अपने 'बंधु-बांधवों' को दुश्मन बना चुके थे। बात अधूरी रह जाएगी, अगर 1986 के अदम के उस आगाज का जिक्र न किया जाये, जिसने उन्हें रातो-रात राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। दरअसल, उस साल प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के पचास साल पूरे हुए थे और लखनऊ में हो रहे उसके सम्मेलन में रात को आयोजित कवि सम्मेलन में स्मृतिशेष मुल्कराज आनंद, तांबा, नागार्जुन, त्रिलोचन और कैफी आजमी वगैरह के साथ कई दूसरी भारतीय व विदेशी भाषाओं के कवि भी उपस्थित थे। कवि सम्मेलन शुरू हुआ और संचालक ने परम्परा के अनुसार वरिष्ठों को पेश करने से पहले, स्थानीय कवियों को उपकृत करना शुरू किया तो अदम भी उन्हीं के बीच जा बैठे। वे स्थानीय नहीं थे, लेकिन उन्होंने संचालक से वादा करा लिया था कि वह उनका कविता पाठ करा देगा, लेकिन ऐन वक्त पर संचालक अपना वादा भूल गया और याद दिलाने पर झिड़ककर कह दिया कि अब वक्त कहां बचा? फिर उनको मौका दिया। अदम माइक पर पहुंचे तो किसी उद्दंड श्रोता को कहते सुना, 'लगता है कि अभी-अभी हल जोतकर आ रहा है!' दरअसल, नजाकत व नफासतपसन्द लखनऊ के लोग किसान अदम की कुर्ता-धोती व गमछे वाली देहाती वेशभूषा का मजाक उड़ाने पर उतर आए थे। अदम ने गजल सुनाई तो श्रोताओं की संवेदनाएं झंकृत हो उठीं। उसके बाद अदम साहित्य के आकाश में छाए तो आखिरी सांस तक छाए ही रहे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सियासत
उमेश चतुर्वेदी

क्या प्रशांत को जनसमर्थन मिलेगा

लोहिया और जयप्रकाश मानते थे कि सत्ता में दलों का बदलने की बजाय जरूरी है कि तंत्र में बदलाव लाना। फिलहाल प्रशांत तंत्र में ही बदलाव का दावा कर रहे हैं। इसी वजह से उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वे ऐसा तभी कर पाएंगे, जब उन्हें बिहार की जनता 2025 के विधानसभा चुनावों में उन्हें मजबूत समर्थन देगी। वे तंत्र तभी बदल पाएंगे, जब उनके पास पारंपरिक राजनेता नहीं होंगे, बल्कि राजनीति का सुचिंतन वाला नया खून उनके पास होगा। फिलहाल निर्णायक भूमिकाओं में जो दिख रहे हैं, वे पूर्व नौकरशाह हैं। नौकरशाह आम नेताओं की तरह जनता की परवाह ज्यादा करेंगे। सवाल यह है कि प्रशांत इस नजरिए से सोच भी रहे हैं या नहीं?

पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान तमाम रैलियों का गवाह रहा है, लेकिन इस मैदान में आधी सदी के अंतर पर हुई दो रैलियों में कम से कम बिहार की अवाम एक समानता देख रही है। पांच जून 1974 को 72 साल के बुजुर्ग जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा की सर्वशक्तिमान सत्ता को उखाड़ने की पूर्व पीठिका रच दी थी। इस बार इंदिरा की सत्ता उखाड़ने जैसा कोई लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन गांधी जयंती के अगले दिन तीन अक्टूबर को 47 साल के प्रशांत किशोर से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के जरिए जनसुराज की बयार बिहार की धरती पर बहा पाएंगे या फिर बदलाव की राजनीति का दावा करने वाले दूसरे लोगों की तरह वे भी पारंपरिक राजनीति का ही हिस्सा बन जाएंगे? वैसे बिहार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर से उम्मीद नहीं है, जैसी नाउम्मीदी पारंपरिक दलों से है।

बिहार की राजनीति के संदर्भ में प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी की पड़ताल करने से पहले एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वे बिहार की राजनीति में तीसरा स्तंभ भी बन पाएंगे? बिहार में यूं तो छोटे-बड़े कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन मोटे तौर पर राज्य की राजनीति दो खेमों में बंटी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की अगुआई वाले गठबंधन में तमाम तरह की वैचारिकी वाले कई दल शामिल हैं, जिनमें देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी तो है ही, वामपंथी दल भी हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा की अगुआई में नीतीश कुमार का जनता दल (यू), जीतनराम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल हैं। इस दो खेमे की राजनीति के बीच में यह सवाल उठना वाजिब है कि क्या प्रशांत किशोर इन दोनों गठबंधनों के बीच अपनी तीसरी राह बना पाएंगे? बिहार की राजनीति का जब भी संदर्भ आता है, गर्व भाव से उसे याद किया जाता है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बिहार के बेटे ने कुंवर सिंह ने जहां देश को नई दिशा दिखाई, स्वाधीनता संग्राम में जयप्रकाश नारायण ने भी नौजवानों को उसी अंदाज में जगा दिया था। इन्हीं जयप्रकाश को दूसरी आजादी के नायक का भी सम्मान हासिल है। बिहार की राजनीति का जब भी बखान होता है, तब इन ऐतिहासिक चरित्रों के हवाले से यह दावा जरूर किया जाता है कि बिहार की राजनीति भविष्य की राजनीति को प्रभावित करती है। इसे उलटबांसी ही कहा जा सकता है कि जिस बिहार की धरती का गौरवबोध वैशाली के गणतंत्र से भर उठता है, जिसे बुद्ध और महावीर की धरती का गौरव हासिल है, उसी बिहार की धरती आज के दौर में जातिवादी राजनीति में ही अपना आज का गौरव ढूंढने में गर्व महसूस करती है। बिहार की राजनीति को लेकर गर्वबोध से भरा रहने वाला समाज भी धरातली सोच में जातिवादी बोध को अलग नहीं कर पाता। फिर भी बिहार में एक वर्ग ऐसा भी है, जो बिहार के मौजूदा पिछड़ेपन से चिंतित रहता है। जिसे इस यह बात सालती है कि उसके राज्य के हर गांव की जवान आबादी का बड़ा हिस्सा दुनियाभर में दिहाड़ी मजदूर बनने को मजबूर है। इसी वर्ग

की उम्मीद बनकर प्रशांत किशोर उभरे हैं। प्रशांत किशोर से आस लगाए वर्ग को बिहार की दरिद्रता, बिहारी लोगों का राज्य के बाहर मिलने वाला अपमान सालता है। इसलिए वे चाहते हैं कि प्रशांत किशोर उभरें और राज्य की जाति-धर्म वाली राजनीति को बदलें। किसी भी नया काम करने वाले की समाज पहले हंसी उड़ाता है, इसके बावजूद अगर वह रुका नहीं तो उसे कुछ उपलब्धियां हासिल होने लगती हैं। इससे समाज के स्थापित प्रभु वर्ग को परेशानी होने लगती है। तो वह उन उपलब्धियों की अनदेखी करने लगता है। फिर भी व्यक्ति रुकता नहीं तो उसकी उपलब्धियों को वही समाज नोटिस लेने लगता है और आखिर में उसे सर आंखों पर बैठा लेता है। प्रशांत किशोर इस प्रक्रिया के दो चरणों को पार कर चुके हैं। अब उनकी उपलब्धियों का बिहारी राजनीतिक दल नोटिस लेने लगे हैं। हालांकि उन्हें बार-बार पांडेय बताकर जातिवादी त्रिशूल से उन्हें बेधने की राजनीतिक कोशिश भी हो रही है। उनके ब्राह्मण होने का प्रचार बार-बार आरजेडी की तरफ से हो रहा है। जिसका पूरा राजनीतिक वजूद ही मुस्लिम और यादव समीकरण पर टिका है।

प्रशांत किशोर ने दो साल तक लगातार बिहार की पदयात्रा की है। जनसुराज यात्रा के नाम से हुई इस यात्रा के जरिए उन्हें ज्यादातर उत्तरी बिहार को अपने कदमों तले नापा है। इसके जरिए उन्होंने अपना बड़ा समर्थक वर्ग तैयार किया है, जिसमें जाति और धर्म से इतर सोचने वाले युवाओं की अच्छी-खासी फौज है। तीन अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में इस वर्ग की उपस्थिति जह प्रशांत किशोर से आस लगाने का आधार उपलब्ध कराती है तो बिहार के दूसरे पारंपरिक दलों के लिए चिंत का सबब भी बनती है। राजनीतिक दल उससे ज्याद चिंतित होते हैं, जिनसे उनके पारंपरिक आधार वोट बैंक के छीजने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन प्रशां किशोर हर वर्ग के उन युवाओं के प्रेरणा केंद्र बनते दिख रहे हैं, जिनके लिए बिहार का बदलाव प्राथमिक लक्ष्य है जिन्हें यह बदलाव मेरिट पर होने की उम्मीद है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस जाति-धर्म की राजनीति स सचमुच दूर हैं? बिहार की राजनीति पिछली सदी के नब्ब के दशक से कमंडल और मंडल खेमे के बीच झूलती रह है। जाति और धर्म की अनदेखी करने का दावा करन वाले प्रशांत किशोर इससे आगे दलितवाद की ओर आग बढ़ते दिख रहे हैं। दिलचस्प यह है कि उनकी टीम म केजरीवाल की टीम जैसे पूर्व नौकरशाह और समाजसेव की भीड़ दिखती है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे देवेंद्र यादव, जदयू के पूर्व राज्यसभा सांस एवं पूर्व राजनयिक पवन वर्मा, पूर्व राजनयिक मनोज भारती प्रशांत किशोर के सहयोगी हैं। देवेंद्र यादव के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं तो पवन वर्मा को बाद के दिन में नीतीश ने भाव नहीं दिया। जिस तरह केजरीवाल क राजनीति से उन लोगों ने ज्यादा उम्मीद लगाई और साथ दिया, जिन्हें पारंपरिक दल तवज्जो नहीं देते थे, कुछ वैस ही हाल प्रशांत की नवेली पार्टी का भी दिख रहा है। ऐस में शक की गुंजाइश बढ़ जाती है कि प्रशांत भी ताकत पाकर कहीं अवसरवादी राजनीति की कॉपी ना बन जाएं

लोहिया और जयप्रकाश मानते थे कि सत्ता में दल का बदलने की बजाय जरूरी है कि तंत्र में बदलाव लाना। फिलहाल प्रशांत तंत्र में ही बदलाव का दावा क रहे हैं। इसी वजह से उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ी है लेकिन वे ऐसा तभी कर पाएंगे, जब उन्हें बिहार क जनता 2025 के विधानसभा चुनावों में उन्हें मजबूत समर्थन देगी। वे तंत्र तभी बदल पाएंगे, जब उनके पास पारंपरिक राजनेता नहीं होंगे, बल्कि राजनीति क सुचिंतन वाला नया खून उनके पास होगा। फिलहाल निर्णायक भूमिकाओं में जो दिख रहे हैं, वे पूर्व नौकरशाह हैं। नौकरशाहों को लेकर यह मानने में हर्ज नहीं है कि वे आम नेताओं की तरह जनता की परवाह ज्यादा करेंगे सवाल यह है कि प्रशांत किशोर इस नजरिए से सोच भी रहे हैं या नहीं?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

धन्वंतरि का ध्यान कर स्वास्थ्य के प्रति सचेष्ट रहें

संकलित
दर्शन

धन त्रयोदशी या धनतेरस पर्व की विशेषता यही है कि उस दिन आप यह मानें कि आप जो चाहते हैं, वह धन आपके पास है। केवल सोना-चांदी ही धन नहीं है, ज्ञान भी धन है। यह सबसे बड़ा धन है। आपको अपने ज्ञान को संजोना चाहिए और प्रचुरता का अनुभव करना चाहिए। जीवन में धन्यभागी अनुभव करना, कृतज्ञता का अनुभव करना सबसे बड़ा धन है, जिनमें कृतज्ञता का अभाव होता है, वे धनी नहीं होते हैं। स्वास्थ्य भी धन है। स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं, तो भौतिक धन का क्या उपयोग हो सकता है। धन त्रयोदशी देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि की जयंती भी है। कहा जाता है कि वह समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः धन त्रयोदशी पर धन्वंतरि का ध्यान कर अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेष्ट रहें। योग व ध्यान करें। आपके पास जो मानव शरीर है, यह भी तो ईश्वर का दिया बड़ा उपहार है। यह भी धन है। हमारी चेतना में ऐसा गुण है कि जो बीज आप बोते हैं, वही प्रकट होता है। यदि आप यह सोचें कि वर्तमान में मेरे पास पर्याप्त धन है, तब आप धन के पीछे पागल नहीं होते। जब आप सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन है, चेतना में धैर्य आता है, हिम्मत आती है। कहा गया है, उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः, जिसका अर्थ है, जो मेहनत करता है और शेर जैसा निर्भय होकर चलता है, लक्ष्मी भी उसी के पास आती हैं। धनतेरस के दिन अपनी चेतना से 'अभाव के भाव' को उखाड़ कर फेंक दीजिए। अपने मन से, 'मैं विपन्न हूं, मैं भिखारी हूं' ये सब बातें हटा दीजिए। शेर की तरह सम्मान के साथ चलिए।

क्या भगवान का अस्तित्व है?

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। तभी नाई ने कहा मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इसीलिए तुम मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो व्यक्ति ने पूछा। नाई ने कहा: बाहर जब तुम सड़क पर जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अगर भगवान होते, तो क्या इतने सारे लोग भूखे मरते? क्या इतने सारे लोग बीमार होते? व्यक्ति ने थोड़ा सोचा लेकिन वह वाद-विवाद नहीं करना चाहता था। नाई ने अपना काम खत्म किया और वह व्यक्ति नाई को पैसे देकर दुकान से बाहर आ गया। वह जैसे ही नाई की दुकान से निकला, उसने सड़क पर एक लम्बे-घने बालों वाले एक व्यक्ति को देखा जिसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और ऐसा लगता था शायद उसने कई महीनों तक अपने बाल नहीं कटवाए थे। वह व्यक्ति वापस मुड़कर नाई की दुकान में दुबारा घुसा और उसने नाई से कहा: क्या तुम्हें पता है? नाइयों का अस्तित्व नहीं होता। नाई ने कहा: तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? क्या तुम्हे मैं दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहां हूं और मैं एक नाई हूं। और मैंने अभी अभी तुम्हारे बाल काटे है। व्यक्ति ने कहा: नहीं! नाई नहीं होते हैं। अगर होते तो क्या बाहर उस व्यक्ति के जैसे कोई भी लम्बे बाल व बढ़ी हुई दाढ़ी वाला होता? नाई ने कहा: अगर वह व्यक्ति किसी नाई के पास बाल कटवाने जाएगा ही नहीं तो नाई कैसे उसके बाल काटेगा?

अंतर्मन

आज की पाती

न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटने का अर्थ

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सही कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जनता की अदालत है। हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति सामने आई है। इसमें आंखों से पट्टी को और उनके एक हाथ से तलवार हटाकर संविधान की किताब थमा दी है। इसका मतलब शायद यह है कि कानून सबको एक बराबर देखता है और न्यायालय में फैसले संविधान के अनुसार होते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि न्यायालय की देवी की नई मूर्ति स्थापित करने से देश के कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार होगा? क्या अब भी देश को उचित और समय पर न्याय मिलेगा? न्याय और कानून व्यवस्था सत्ताधारियों, राजनेताओं और पूंजीपतियों के हाथ से मुक्त होगी? इन विषयों पर गहन चिंतन की जरूरत है। - महेश शर्मा, महासमुंद

ट्रेंड

भारत ने साबित किया

भारत ने साबित किया है कि डिजिटल नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्य सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। हमने दिखाया है कि प्रौद्योगिकी समावेशन, पारदर्शिता और सशक्तिकरण का एक उपकरण है। 21वीं सदी को स्थिरता, स्थिरता और समाधान की आवश्यकता है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मलेरिया मुक्त हुआ मिस्र

बड़ी खुशखबरी: मिस्र मलेरिया मुक्त हो गया है। यह प्रमाणीकरण वास्तव में ऐतिहासिक है, और इस प्राचीन संकट से छुटकारा पाने के लिए मिस्र के लोगों और सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। मैं इस उपलब्धि पर मिस्र को बधाई देता हूं।
-डॉ टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

परिवारों के प्रति संवेदनाएं

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष

वृद्धि की जरूरत

भारत को अपनी अनुसंधान एवं विकास तीव्रता, पीएचडी कर्मचारियों की संख्या, पेटेंट और प्रकाशन में उल्लेखनीय वृद्धि की जरूरत है। अच्छा लगता बायो लिमिटेड प्रति अरब अमेरिकी डॉलर राजस्व प्रकाशन के मामले में भारतीय कंपनियों में पहले स्थान पर है।
-किरण मजूमदार शॉ, उद्योगपति

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

पाकिस्तान में 64 साल बाद हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिससे इस मंदिर के जर्जर होने के 64 साल बाद इसके जीर्णोद्धार का पहला चरण शुरू होगा। मीडिया में आई एक खबर में सोमवार को यह जानकारी दी गयी। 'डॉन न्यूज' की खबर के अनुसार, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की देखरेख करने वाली संघीय संस्था 'इवेक्यूई ट्रस्ट प्रोपर्टी बोर्ड' (ईटीपीबी) ने पंजाब में रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित नारोवाल शहर के जफरवाल नगर में बावली साहिब मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। यह मंदिर 1960 में जर्जर हो गया था। अभी नारोवाल जिले में कोई हिंदू मंदिर नहीं है जिससे हिंदू समुदाय को धार्मिक अनुष्ठान घर पर ही करने पड़ते हैं या उसके लिए सियालकोट और लाहौर के मंदिरों में जाना पड़ता है। पाक धर्मस्थान कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रतन लाल आर्या ने कहा कि बावली साहिब मंदिर पर ईटीपीबी के नियंत्रण के कारण वह जर्जर हो गया और नारोवाल में 1,453 से अधिक हिंदू पूजा स्थल से वंचित हो गए। पाकिस्तान के गठन के बाद नारोवाल जिले में 45 मंदिर थे लेकिन उनमें से सभी मरम्मत न होने के कारण जर्जर होते चले गए।

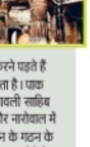

ऑफ बीट

एआई को मानवीय बनाना हमें अमानवीय बना सकता है

मनुष्य लंबे समय से गैर-मानवीय चीजों को मानवीय गुण प्रदान करते आए हैं। इस प्रवृत्ति को 'मानवीकरण' के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम चैटजीपीटी जैसे एआई उपकरणों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो 'सोचने' और 'महसूस करने' वाले प्रतीत होते हैं। कानूनी मुद्दों से बचने के लिए, कंपनी बताती है कि 'रेप्लिका' संवेदनशील नहीं है और केवल लाखों उपयोगकर्ताओं की बातचीत के माध्यम से सीखता है। वहीं, कुछ एआई कंपनियां खुले तौर पर दावा करती हैं कि उनके एआई सहायकों में सहानुभूति है और वे मानवीय जरूरतों का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। हालांकि, ऐसे दावे भ्रामक हैं। यदि उपयोगकर्ता मानते हैं कि उनका एआई साथी वास्तव में उन्हें समझता है, तो वे भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ सकते हैं। यह गंभीर नैतिक चिंताओं को जन्म देता है। एक उपयोगकर्ता यदि अपने एआई साथी को चेतना प्रदान करता है तो वह उसे हटाने या छोड़ने में संकोच करेगा। दरअसल तब क्या होता है कि जब उक्त एआई साथी अप्रत्याशित रूप से गायब हो जाता है, मसलन यदि उपयोगकर्ता इसका खर्च नहीं उठा सकता, या इसे चलाने वाली कंपनी बंद हो जाती है? एआई साथी भले ही वास्तविक नहीं हो, लेकिन इससे जुड़ी भावनाएं वास्तविक होती हैं।

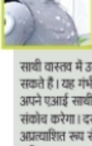

सम्पादकीय

जीएसटी प्रणाली में सुधार की जरूरत, मुआवजा उपकर के विलय पर हो विचार

कोविड-19 महामारी की वजह से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में देरी हुई। अप्रत्यक्ष कर सुधार 2017 में लागू किया गया था और उस समय यह वादा किया गया था कि राज्य सरकारों को पहले पांच साल के दौरान होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। राज्यों को मुआवजा देने के वास्ते फंड जुटाने के लिए जीएसटी की उच्चतम दरों वाले स्तर पर एक मुआवजा उपकर लगाया गया। सामान्य परिस्थितियों में मुआवजा उपकर 2022 में समाप्त हो जाना था। बहरहाल महामारी के दौरान कर संग्रह पर बुरा असर हुआ और यह निर्णय लिया गया कि राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए उधारी ली जाएगी और उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाई जाएगी ताकि इसके लिए जुटाए गए कर्ज तथा उसके ब्याज को चुकता किया जा सके। ऐसे में महामारी के दौरान लिए गए 2.7 लाख करोड़ रुपये की राशि को चुकता करने के लिए उपकर लिया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक जनवरी 2026 तक इसे चुकाने का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि भविष्य की दिशा तय की जाए और समय पर जरूरी कानूनी बदलाव पूरे कर लिए जाएं। मंत्रियों का एक समूह बनाया गया ताकि वह भविष्य की राह सुझा सके। जैसा कि इस समाचार पत्र ने गत सप्ताह लिखा, राज्य सरकारों ने मुआवजा उपकर को जीएसटी दर में समाहित करने का सुझाव रखा है। राजस्व वाले नजरिये से देखा जाए तो उपकर को उच्चतम जीएसटी दर में समाहित करने से राजस्व संग्रह और करदाताओं पर बोझ दोनों बरकरार रहेंगे। फिलहाल उपकर के रूप में संग्रहीत राजस्व का इस्तेमाल कर्ज को चुकाने के लिए किया जा रहा है। विलय के बाद इसे सामान्य जीएसटी संग्रह के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जा सकता है। उपकर से हासिल होने वाला संग्रह 2023-24 में 1,44,554 करोड़ रुपये था।

हालांकि हालात इतने भी आसान नहीं रहने वाले हैं और मंत्री परिषद जिसे 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है उसे कई संभावित परिणामों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए उपकर सीमित समय के लिए लगाया गया था और फिर असाधारण परिस्थितियों में उसमें इजाफा किया गया। ऐसे में क्या उसे स्थायी रूप से कुछ चीजों पर लगने वाली उच्च कर दर में मिला देना उचित होगा? इतना ही नहीं विभिन्न वस्तुओं पर उपकर का स्तर भी अलग है। उपकर को आधार दर में शामिल करने से जीएसटी प्रणाली में स्लैब बढ़ सकते हैं। अब यह स्वीकार्य है कि दरों की बहुलता से कारोबार और कर अधिकारियों दोनों के लिए जटिलता उत्पन्न होती है और स्लैब की तादाद कम करने की आवश्यकता है। एक अन्य मंत्री परिषद दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है। गत सप्ताह बैठक में इस मंत्री परिषद ने यह अनुशंसा की थी कि पैकेटबंद पानी, साइकिल, कलाई घड़ी और जूतों जैसी वस्तुओं पर जीएसटी कर दर में बदलाव किया जाए। मंत्री परिषद को मार्जिन में छेड़छाड़ से आगे बढ़कर ढांचागत बदलाव के तरीकों पर विचार करना चाहिए।

किसानों की जिंदगी बेहतर करने का फंडा-किसानों द्वारा 5 रूपए में बेची सब्जी बाजार में 50 रूपए कैसे बिकती है?

हम दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को रबी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में केंद्रीय कृषिमंत्री के संबोधन की करें तो उन्होंनें शनिवार को कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद (सब्जियों) की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी।राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा,किसान 5 रुपये में सब्जियां बेचता है, तो उपभोक्ता 50 रुपये चुकाता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है,और बीच में जो पैसा जाता है, इसकी साइंटिफिक व्यवस्था बन रही है जिससे किसान को उसके हक का पैसा मिले।

कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट
किशन सनमुखदास
भावनानी,गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर हर देश में किसान का महत्वपूर्ण दर्ज़ा होता है,क्योंकि वह जीवन यापन करने के लिए अति महत्वपूर्ण खाद्यान्न को कड़ी मेहनत कर बीज रोपण से लेकर मंडी तक बिकवाली के लिए लाने तक अपना पूरा खून पसीना एक कर देता है,परंतु आश्चर्य व खेद की बात है कि उसे उतनी मेहनत की तुलना में मेंहनताना नहीं मिल पाता,इसलिए ही वह एमएसपी के लिए जद्दोजद व आंदोलन पर उतारू हो जाता है। हालांकि भारत सहित हर देश में किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, व उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है।भारत में तोअन्नदाता के लिए कई स्कीमें योजनाएं व उन्हें सुविधा सरकारें देती रहती है परंतु लाख टके की एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस बागवानी फ़सल या सब्जियों के लिए किसानों को मात्र 5 या 10 रूपए मिलते हैं वह चिल्लर मार्केट में 70 से 80 रुपए तक कैसे बिकता है,बड़ा सोचनीय प्रश्न है यही बात दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जो हमारी राइस सिटी गोंदिया के सगे जवाई राजा भी हैं, उनके जेहन में भी यह बात आई और उन्होंने रबी अभियान 2024 को एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही और बताया कि इसकी नब्ज़ पकड़ने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी उसके अनुसार रणनीति बनाई जाएगी। कृषि मंत्री की मीडिया में यह बात सुनकर,मैं रविवार दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो यह बात 100 प्रतिशत सही व सटीक साबित हुई।किसानों ने बताया हम जो सब्जी या बागवानी फसल का रेट मार्केट में देते हैं या नीलामी में बिकता है, वही हमारा माल चिल्लर मार्केट में हमारी बिक्री से 6 से 7 गुना अधिक कीमत में बिकता है जो मैंने सही पाया, इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री का संज्ञान सटीक लगा। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,किसानों से कौड़ियों के रेट में बिका बागवानी उत्पाद यानें सब्जियां उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने तक कीमतें आसमान कैसे छूती इसपर तुरंत एक्शन की दरकार है।

साथियों बात अगर हम खेतों के लिए 6 सूत्र तय करने की करें तो उन्होंने कहा, हमने खेती के लिए 6 सूत्र तय किए हैं।(1)उत्पादन बढ़ाना, इसके लिए अच्छे बीज चाहिए। नया बीज रिलीज तो हो गया लेकिन साइकिल ऐसी है कि तीन चार साल लग जाते हैं किसान तक पहुंचते-पहुंचते।(2)सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। खाद की उपलब्धता भी हो। जो फ़ीडबैक आया है, उसपर हमें चिंता से काम करना है।(3)कैमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हम कैसे कम करें, इस पर हमें धीरे-धीरे ध्यान देना होगा। (4)ऑर्गेनिक और नेचुरल फ़ार्मिंग की ओर जब हम बढ़ेंगे, तब हम धीरे-धीरे इसका उपयोग भी कम कर लेंगे।(5)खाद के लिए केंद्र के साथ राज्य जो भी ध्यान देना होगा। भारी सब्सिडी के बाद भी अव्यवस्था के कारण हमारा परिश्रम बेकार हो जाता है।(6)उत्पादन की लागत घटाना हमारा दूसरा लक्ष्य है।पर हेक्टेयर ईल्ड तो बढ़े लेकिन लागत कैसे घटे, इस पर काम हो रहा है।जो चीज हम तय करते हैं, वो कैसे किसान तक जाये, इसके लिए राज्यों का सहयोग चाहिए।उन्होंने बताया कि कृषिचौपाल हम अगले महीने शुरू कर देंगे, इसमें किसान बैठेंगे और वैज्ञानिक बैठेंगे।आगे कहा कि व्यावहारिक रूप से केंद्र और राज्यों के सामने अगर कोई समस्या आती है तो उसे पूरा करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।पीएम के नेतृत्व में हर कैबिनेट में किसानों के हित में क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं।पीएम ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि तीसरे टर्म में तीन गुणी ज्यादा शक्ति से काम करना चाहता हूं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी प्रण लिया कि अकेले पीएम ही तीन गुनी शक्ति से काम नहीं करेंगे बल्कि हम भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी 18 से 19 प्रतिशत तक का योगदान है और 55 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को कृषि ही रोजगार प्रदान कर रही है। कृषि ने ही कोविड में भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और मैं दिन और रात इसे करने की कोशिश करूंगा।

साथियों बात अगर हम कृषि विभाग के महत्व कोसमझने की करें तो, सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा काम कोई साधारण काम नहीं है। कृषि विभाग का मतलब है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर बने उसके प्रयास करना। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करने का प्रयास करती है। केंद्र और राज्य दो अलग- अलग नहीं है हमारा संघीय ढांचा है, हम दोनों को ही मिलकर काम करना है। कृषि मंत्री के रूप में मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी राज्य हो, सभी हमारे लिए बराबर हैं। हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। केंद्र सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है सभी मिलकर काम करेंगे, राज्यों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इस सम्मेलन का संकल्प यही है कि हम मिलकर काम करेंगे। विभिन्न राज्यों से आए कृषि मंत्रियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके अनेकों ठोस सुझाव हमें मिले हैं और अनेकों समस्यायें भी बताई हैं। मैं अधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि मंत्रियों ने जो समस्याएं रखी हैं उन पर ठोस परिणाम आने चाहिए।राज्यों के मंत्रियों को अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है ताकि समस्याओं पर चर्चा की जा सके। अभी तक हम 17 राज्यों से बात कर चुके हैं और बाकी राज्यों के कृषि मंत्रियों व अधिकारियों को भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। किसानों से भी हर सप्ताह संवाद कर रहे हैं। किसानों व किसान संगठनों से प्राप्त राज्यों से संबंधित सुझावों को हम राज्यों को भेजते हैं और केंद्र के विषयों पर विभाग समाधान करते हैं। साथियों बात अगर हम कृषि रणनीति के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं। 2019 से तय हुआ कि उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर मुनाफा देना है। खरीदी की भी प्रभावी व्यवस्था हो, इस पर काम हो रहा है।हम दलहन और तिलहन के सबसे उत्पादन भी हैं लेकिन आयात भी हम करते हैं। इसका उत्पादन हमें बढ़ाना है, लेकिन किसान दाम भी देखेगा कि किसमें फायदा है।हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था खत्म की है, चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध को खत्म किया है। दालों की खरीद की व्यवस्था हमने की है। दालों की पूरी खरीदी होगी, किसन चिंता न करें। हम किसी राज्य में 25 प्रतिशत से ज्यादा भी खरीदेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। उन्होंने बताया कि गाँव में टमाटर पैदा हुआ, यहाँ पर आते हुए उसके रेट बढ़ जाते हैं, बीच के ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को अगर केंद्र राज्य मिलकर वहन कर लें तो शहर वाले को सस्ती सब्जी मिलेगी और किसान को बेहतर दाम मिल जायेगा। जल्दी खराब होने वाली फसलों विशेष कर सब्जियों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए कमेटी बनाई है। हमें कृषि का विविधीकरण करना है। कई बार किसी फसल का जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो जाता है। राज्य और केंद्र एक प्रयोग करे, एक मॉडल फार्म कैसे बने। एक, दो या ढाई एकड़ जमीन में किसान कैसे खेती करे, इस पर काम हो। कई किसानों ने बताया है कि वो एक एकड़ में अच्छा कमा लेते हैं।अलग-अलग राज्यों में प्रयोग होना चाहिए। हमें परंपरागत खेती का स्वरूप बदलना होगा।उन्होंने कहा कि भारत में इतने एग्रो-क्लाइमेटिक ज़ोन हैं कि भारत दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है।हम संवेदनशील बनें। किसानों को कई बार नुकसान हो जाता है, उस समय हमें किसानों के साथ खड़े होना है। फसल बीमा योजना का पैसा किसानों को समय पर मिल जाना चाहिए। लगातार रिव्यू हो जिससे अधिक से अधिक पैसे किसानों को मिलें। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करेंतो हम पाएंगे कि किसानों कीजिंदगी बेहतर करने का फंडा-किसानों द्वारा 5 रूपए में बेची सब्जी बाजार में 50 रूपए कैसे बिकती है?केंद्र सरकार ने खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद (सब्जियों) की कीमत में भारी अंतर की नब्ज़ पकड़कर साइंटिफिक व्यवस्था बनाने कमेटी बनाई।किसानों से कौड़ियों के रेट में बिका बागवानी उत्पाद (सब्जियां) उपभोक्ता की थाली तक पहुंचते तक कीमतें आसमान कैसे छूने लगती है?

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

'आईएएस प्रकाश राजपुरोहित को ब्यूरोक्रेसी के जैंटलमैन कहे जाते हैं, जोधपुर कलक्टर रहते हुए विगत सालों से चली आ रही अपॉइंटमेंट सिस्टम को खत्म कर पीड़ित व परिवादियों के लिए दरवाजे खुले रखे'

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं श्री प्रकाश राजपुरोहित इनका जन्म 28 फरवरी सन 1986 को बाड़मेर में हुआ। होनहार बीरवान को होत चिकने पात कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करते ये शानदार अधिकारी बचपन से ही पढ़ाई के लिए उत्तम विचार रखने वाले नौजवान रहे हैं दिल्ली व गाजियाबाद से शिक्षा पूर्ण हुई। बी.टेक (इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग) की पढ़ाई के बाद जब मन नहीं भरा तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए। आईआईटी टॉपर भी रहे हैं लेकिन यूपीएससी में दूसरी रैंक हासिल कर कलक्टर बने। इन्हे राजस्थान कैडर के सबसे सौम्य अधिकारी के रूप में देखा जाता है। आज ये आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान,जयपुर पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व लगभग दो साल जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जैसे बड़े पद पर रहे हैं। आयुक्त, आबकारी विभाग एवं पदेन मद्य निषेध निदेशक, राजस्थान, उदयपुर, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, राजस्थान जयपुर, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जोधपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा, संयुक्तक शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय अलवर, प्रशिक्षणाधीन एलबीएसएनएए मसूरी रहे। इसके अलावा सरकार ने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दूदू व कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण का अतिरिक्त पद भार संभाला। इनके बारे में क्या बयां करूं,इतने सीधे और सरल हृद्य व्यक्तित्व के धनी हैं प्रकाश राजपुरोहित सर। दो साल जयपुर जैसे स्थान में इतने बड़े पद के अधिकारी का रूकना सच में मायने रखता हैं इसके अलावा जोधपुर जिले में भी दो साल कलक्टरी करना मायने ही रखता है। जोकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला रहा हो। अपने अधिनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बहुत बेहतरीन व्यवहार के साथ कार्य संपादित करवाने वाले शानदार अधिकारी के रूप में इन्हें देखा जाता है। अलवर कलक्टर रहते हुए चुनाव के दौरान इनकी कार्यकुशलता को काफी करीब से देखा कि चुनाव जैसे तनावपूर्ण कार्य में कैसे खुद भी तनावमुक्त रहकर कार्य किया और अपने अधिकारियों व कर्मचारियों से कैसे तनावमुक्त होकर कार्य करवाया। एक दम साधारण सा व्यक्तित्व बस पीड़ित व परिवादियों के लिए ईश्वर का स्वरूप सा बनकर आए हैं। सच में बहुत ही संवेदनशील आईएएस के रूप में इन्हे जाना जाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्वल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

श्री प्रकाश राजपुरोहित
(आरआर-10)
वरिष्ठ आई ए एस

आज का इतिहास

22 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- सेन हाउटन 1836 में टेक्सास गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने।
- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की आधारशिला 1867 में रखी गयी।
- अर्जेंटीना में पहले टेलीग्राफिक कनेक्शन की शुरुवात 1875 में हुई।
- सेलफोर्ट में पहली बार रगबी मैच ब्राउटन और स्वींटन के बीच 1878 में खेला गया।
- ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला राजद्रोह का मुकदमा 1879 को बसुदेव बलवानी फड़के के खिलाफ।
- बॉस्टन सिंफनी आर्केस्ट्रा ने पहला संगीत समारोह 1881 में किया।
- न्यूयार्क में ओपेरा हाउस का उद्घाटन 1883 में हुआ।
- भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 'भाखड़ा नांगल' राष्ट्र को 1962 में समर्पित की गई।
- फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक ज्यां पाल सार्त्र ने 1964 में नोबेल पुरस्कार ठुकराया।
- 'वीनस-9' अंतरिक्षयान का 1975 को शुक्र ग्रह पर अवतरण।
- तुर्की के राजनयिक की 1975 को वियना में गोली मारकर हत्या।
- अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में निवेश में 2004 को भारत 14 वें स्थान पर।
- सीका सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2004 में आतंकवाद से मिलकर निपटने का संकल्प व्यक्त किया।
- अफगानिस्तान में 2006 को अधिक नशीली दवाएँ जब्त की गईं।
- चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने 2007 में लगातार दूसरी बार सत्तारूढ़ चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी की कमान सम्भाली।
- इसरो ने भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण 2008 में किया। इस मिशन से चंद्रमा पर पानी के होने का पता लगा।
- श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से चन्द्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण 2008 में किया गया।
- माइकल जेहाफ बिडायु ने ओटावा में कनाडा के संसद पर 2014 को हमला किया, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गयी और तीन अन्य घायल हो गये।
- भारत ने 2016 में कबड्डी विश्व कप जीता।

22 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

- हिन्दू धार्मिक नेता स्वामी रामतीर्थ का जन्म 1873 में हुआ जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यावहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात थे।
- भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला ख़ाँ का जन्म 1900 में हुआ।

विशेष आलेख

जहरीली होती हवा से गहराता सांसों का संकट

ललित गर्ग

दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अभी दीपावली आने में कुछ दिन है, उससे पहले ही जहरीली हवा एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न दमघोटू माहौल का संकट जीवन का संकट बनने लगा है और जहरीली होती हवा सांसों पर भारी पड़ने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआइ बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में औसत एक्यूआइ 293 पहुंच गया है। दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में यह अभी से 300 पार जा चुका है। अतीत का अनुभव बताता है कि आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से जनता की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अलावा कोई योजना नजर नहीं आती। दिल्ली सरकार जो भी तर्क दें, पर हकीकत यही है कि लोगों का दम घुटेगा, बच्चों एवं बुजुर्गों के सामने बड़ा संकट खड़ा होगा, अगर दिल्ली सरकार सचमुच इससे पार पाने को लेकर गंभीर नहीं है, वह गंभीर होती तो पहले से कोई ठोस योजना बनाती। दिल्ली के वायु प्रदूषण एवं हवा के जहरीले होने में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली का बड़ा योगदान बताया जाता है। उससे निपटने के प्रयासों के दावे भी राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं पर वांछित परिणाम नजर नहीं आते। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बना आयोग भी जिम्मेदारी के निर्वाह में नाकाम नजर आता है। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रही दिल्ली को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती। सरकारें एवं राजनेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठहराने की बजाय समाधान के लिये तत्पर क्यों नहीं होते? वैसे प्रदूषण कम करने और दिल्ली सहित देश के अन्य महानगरों-नगरों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हालांकि लोगों को सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है, एंटीडस्ट अभियान भी निरन्तर चलाया जाना चाहिए। लोगों को खुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को खुली जगह में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और न ही उसे जलाया जाए। वाहनों का प्रदूषण लेवल चैक करना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता।

सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर कठोर टिप्पणियां करने के साथ सरकार को कठोर एवं प्रभावी कदम उठाने के लिये जागरूक करती रही है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने में पंजाब सरकार की नाकामी पर सख्त टिप्पणी भी की। पंजाब और दिल्ली, दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए यह आप और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा भी बनता रहता है। ध्यान रहे कि पंजाब और दिल्ली के बीच स्थित राज्य हरियाणा में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, जिसके पश्चिमी क्षेत्र के किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगता रहता है। आम आदमी की सेहत ही नहीं, जीवन से भी जुड़े इस जानलेवा मुद्दे पर राजनीति नहीं, बल्कि ठोस समाधान की राह निकलनी चाहिए। हमारे राजनीति दल संवेदनहीन नहीं बल्कि संवेदनशील बनें। दीपावली पर आतिशबाजी न हो, इसके लिये व्यापक प्रयत्न किये जाये। क्योंकि पटाखे जलाने से न केवल बुजुर्गों बल्कि बच्चों के जीवन पर खतरनाक प्रभाव पड़ने और अनेक रोगों के पनपने की संभावनाएं हैं। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली पटाखे जलाने की भौतिकतावादी मानसिकता को विराम देना जरूरी है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अभिधारणा को मूर्त रूप देने के लिये इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की दिशा में पिछले कुछ सालों में कई पायदान हम ऊपर चढ़े हैं, एक सकारात्मक वातावरण बना। लेकिन पटाखों से ज्यादा खतरनाक है पराली का प्रदूषण। पराली आज एक राजनीतिक प्रदूषण बन चुका है। तमाम बंदिशों एवं चेतावनियों के दीपावली की रात आतिशबाजी जमकर होती है, इसके कारण पिछले साल आनंद विहार में एक्यूआइ 999 के बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। यह आम आदमी की सेहत, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 401 से 500 तक के एक्यूआइ को 'गंभीर' एवं खतरनाक माना जाता है। वायु प्रदूषण से जुड़े आंकड़े हमें बार-बार सतर्क एवं सावधान करने के साथ डराते भी है। यह डराने वाला ही आंकड़ा है कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण से 20 लाख मौतें होती हैं। देश में होने वाली मौतों का यह पांचवां बड़ा कारण है। दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण में पराली और पटाखों की ही तरह वाहनों एवं भवन-निर्माण से जुड़ा प्रदूषण भी खतरनाक होता है। भू-विज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च के अनुसार वायु निर्माण में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों की रहती है। भवन निर्माण आदि से उड़नेवाली धूल 21.5 प्रतिशत के दूसरे स्थान पर है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक पिछले 30 साल में वाहन और उनसे होने वाला प्रदूषण तीन गुणा बढ़ गया है। फिर भी सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये हर राजनीतिक दल एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा। क्या हमें किसी चाणक्य के पैदा होने तक इन्तजार करना पड़ेगा, जो जड़ों में मट्ठा डाल सके।...नहीं, अब तो प्रत्येक राजनीतिक मन को चाणक्य बनना होगा। तभी विकराल होती वायु प्रदूषण की समस्या से मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास है। अभी से हर दिन पराली जलाने की घटनाएं दर्ज होने लगी है। क्या इसे रोकना वाकई इतना कठिन है? आखिर दिल्ली, पंजाब के साथ केंद्र सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि किसान पराली न जलाएं? सच यह है कि इसके लिए कोई प्रभावी कोशिश हो ही नहीं रही है। किसानों से बात करने का साहस कोई भी सरकार नहीं दिखा रही है। ऐसा माहौल बना दिया गया है, मानो खेती के नाम पर कुछ भी करने की छूट है। इसका कारण राजनीतिक ही है। कोई किसान है, इसका यह अर्थ नहीं कि उसे वातावरण को दमघोंटू बनाने एवं लोगों के जीवन को संकट में डालने का अधिकार है। अभी से दिल्ली की आबोहवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होने लगती है। दिल्ली की हवा में उच्च सांद्रता है, जो बच्चों को सांस की बीमारी और हृदय रोगों की तरफ धकेल रही है। शोध एवं अध्ययन में यह भी पाया गया है कि यहां रहने वाले 75.4 फीसदी बच्चों को घुटन महसूस होती है। 24.2 फीसदी बच्चों की आंखों में खुजली की शिकायत होती है। सर्दियों में बच्चों को खांसी की शिकायत भी होती है। बुजुर्गों का स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा प्रभावित होता ही है। सर्दियों के मौसम में हवा में घातक धातुएं होती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है।

आज का राशिफल

मेष
सामान्य रूप से पूरा दिन खुशहाली में व्यतीत होगा। आज का दिन कष्टदायक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। स्वभाव में क्रोध और आवेश रहेगा। इससे किसी के साथ उग्र तकरार हो सकता है।

वृष
शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता रहेगी। प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात सफल और आनंददायक रहेगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा। मित्रों तथा स्नेहीजनों की तरफ से उपहार मिलने से आनंद अनुभव करेंगे। आनंददायक प्रवास होगा।

मिथुन
क्रोध और वाणी पर संयम रखें। हित शत्रु आपको हानि न पहुंचाएं, उसका ध्यान रखें। परिजनों के साथ सामाजिक कामों में या किसी पर्यटन-स्थल पर घूमने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारियों की आय में वृद्धि होने की संभावना है।

कर्क
वाणी और व्यवहार में संयम रखें। अदालत संबंधी काम-काज में सावधानीपूर्वक कदम उठाएं। आज के दिन घर में किसी शुभ प्रसंग के आयोजन की संभावना है। किसी वस्तु की खरीदारी के लिए आज शुभ दिन हैं। शेयर-सट्टा की प्रवृत्तियों में धन लाभ होगा।

सिंह
आज परिवार में मनमुटाव का वातावरण रहेगा। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन में नकारात्मक विचार आने से उदासी का अनुभव होगा। जमीन, मकान, वाहन आदि के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन अच्छा नहीं है।

कन्या
सामाजिक क्षेत्र में सफलता और यश-कीर्ति प्राप्त होगी। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना अधिक है। परिजनों के साथ आप आनंद-उल्लासपूर्ण वातावरण में सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। आर्थिक लाभ की भी आज संभावना अधिक है। अत्यधिक खर्च होगा।

तुला
शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव होगा। फिर भी वाणी और क्रोध पर संयम रखें अन्यथा मन को चोट पहुंच सकती है। कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। मान-सम्मान भी प्राप्त होगा। अधूरे काम पूरे होंगे।

वृश्चिक
आज का दिन शारीरिक शिथिलता और मानसिक चिंता में गुजरेगा। मित्रों और संतान के विषय में चिंता बनी रहेगी। आकस्मिक धन खर्च के योग हैं। विवादजनक प्रसंगों को आज टाल दें। संभव हो तो कहीं बाहर न जाएं।

धनु
भाग्यवृद्धि का योग होने पर भी किसी भी काम में गलत कदम से हानि हो सकती है। आध्यात्मिक मामलों में सिद्धि मिलेगी। आज के दिन आपकी मानसिक स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी। ऐसे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें।

मकर
आपका आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अनोखी अनुभूति कराने वाला साबित होगा। गूढ़ और रहस्यमय विद्याएं सीखने में आप विशेष रुचि लेंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय शुभ नहीं है। प्रवास में आकस्मिक कठिनाई आएगी।

कुंभ
नए काम का आरंभ न करें। वाणी पर संयम रखने से परिजनों के साथ वाद-विवाद नहीं होगा। किसी काम के प्रति जिद्दी ना बने रहें। आर्थिक लाभ की संभावना है। परिजनों के साथ आज का दिन आमोद-प्रमोद में व्यतीत होगा।

मीन
पानी वाली जगहों से दूर रहें। शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप प्रेमपूर्ण संबंधों से अभिभूत रहेंगे। भाई-बहनों के साथ अच्छी तरह समय व्यतीत होगा और उनसे लाभ भी मिलेगा। विरोधियों की चाल निष्फल रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीलपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

जयप्रकाश रंजन
jpranjan@del.jagran.com

ब्रिक्स सम्मेलन

भारत के लिए पहले से अधिक प्रासंगिक

आज यानी 22 अक्टूबर से रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वहां जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान हो रहा यह सम्मेलन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, पिछले दो वर्षों में जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन के बीच एकता बढ़ी है, उसे देखते हुए इनकी तरफ से ब्रिक्स को तेजी से विस्तारित करने एवं इसके सामाजिक व आर्थिक एजेंडे को लेकर स्पष्टता लाने की कोशिश होगी

रूस के कजान में आज से आरंभ हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन की ओर टिकी हैं समूचे विश्व की निगाहें। सीएनएस

इस साल की ब्रिक्स संगठन की बैठक खास होगी। इसके कई कारण हैं। पश्चिम एशिया में जारी उथल-पुथल और रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ ही हाल के दिनों में कनाडा और उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय एजेंसियों पर अपने नागरिकों की हत्या कराने या हत्या की साजिश रचने के मामले पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है, उसे देखते हुए भारत के लिए भी इस बार ब्रिक्स कुछ अलग मायने रखेगा। वर्तमान परिस्थितियां भारत की बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की कोशिशों को सही साबित करते हैं। यह भी बताता है कि पश्चिमी व अमेरिका के साथ कारोबार, प्रौद्योगिकी व सैन्य क्षेत्र में लगातार संबंधों को मजबूत बनाने के बावजूद क्यों रूस और चीन की अगुवाई वाले शंघाई सहयोग संगठन व ब्रिक्स में भी भारत मजबूती से टिका हुआ है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चिनफिंग और पुतिन ब्रिक्स को विस्तारित करने को लेकर जो नया रोडमैप रखेंगे, उस पर पीएम नरेन्द्र मोदी की क्या प्रतिक्रिया होगी।

वस्तुतः ब्रिक्स की शुरुआत ब्रिक के तौर पर ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 2006 में तब के जी-8 की अगुवाई में एक बैठक में हुई थी जिसमें भारत व चीन को भी आमंत्रित किया गया था। बाद में इस संगठन से रूस को बाहर कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स बन गया। इसका दूसरा विस्तार वर्ष 2024 में हुआ है और पांच नए सदस्यों- ईरान, यूएई, इथियोपिया, मिस्र और सऊदी अरब को शामिल किया गया है। रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर, 2024 को होने वाली बैठक में इस बार यह भी तय किया जाना है कि ब्रिक्स के नए सदस्यों को किस तरह से शामिल करना है।

असल में जिस तेजी से ब्रिक्स को लेकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में रुचि बढ़ी है, वह बताता है कि दुनिया में बहु-ध्रुवीय व्यवस्था को लेकर कितनी जबरदस्त इच्छाशक्ति है। वर्तमान सदस्यों के हिसाब से भी देखा जाए तो ब्रिक्स में 3.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व है और इन देशों की इकोनमी का कुल आकार लगभग 28.5 लाख करोड़ डालर है। कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से ग्लोबल साउथ (विकासशील एवं गरीब देश) के देशों की आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं, उसे देखते हुए कई देशों को ब्रिक्स से ही मदद मिलने की संभावना है। अभी तक छोटे व कम विकसित देश किसी राजनीतिक या आर्थिक संकट में फंसने पर अमेरिका की तरफ से देखते थे, लेकिन अब यह सिलसिला टूट चुका है। अपने आंतरिक राजनीतिक द्वंद में काफी हद तक बंटा हुआ अमेरिका इन देशों के लिए उम्मीद की किरण नहीं रहा। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों का आर्थिक संकट भारत ने दूर किया है। अफ्रीका में कई देश चीन की आर्थिक मदद से ही अपनी इकोनमी चला पा रहे हैं। अमेरिका के कई साझेदार देशों की तरफ से ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताना यह बताता है कि उनके बीच भी ब्रिक्स के भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ा है। भारत ने भी चीन के साथ अपने बेहद तनावग्रस्त रिश्तों के बावजूद ब्रिक्स को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत स्वयं को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है और जिस तरह से ब्रिक्स के झंडे तले ये देश एकत्रित हो रहे हैं, वह भारत के लिए एक सकारात्मक पहलू साबित हो सकता है।

आर्थिक व सामाजिक एजेंडा : ब्रिक्स की सफलता का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सही मायने में इसकी भूमिका की पहचान तब होगी जब इसके सदस्य बढ़ेंगे और इसका आर्थिक व सामाजिक विकास का एजेंडा ज्यादा व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए कर्ज देने के लिए स्थापित ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम अब और बढ़ेगा। ब्रिक्स की भावी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि यह अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा करने में कितनी मदद करता है। यह भी ध्यान रहे कि जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तो इसका एक बड़ा उद्देश्य पश्चिम देशों की तरफ से संचालित विकास फंड व्यवस्था को चुनौती देना था। जो भी देश इसका सदस्य बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, उन्हें विकास परियोजनाओं के लिए अमेरिका व दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से संचालित व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं है। वह दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था चाहते हैं। ब्रिक्स बैंक ने इस काम की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी काफी सीमित है। ब्रिक्स देशों की तरफ से पहले से ही विश्व बैंक व आइएमएफ जैसी एजेंसियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। भारत तो इसका खास तौर पर मांग करता है। ब्रिक्स सदस्यों की तरफ से जी-20 की बैठक में भी यह बात जोर-शोर से उठाया जाता है। संभवतः अब यह संगठन अपनी मांग को मनवाने में ज्यादा सक्षम होगा।

इसी तरह से ब्रिक्स का एक अहम एजेंडा है वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डालर के इस्तेमाल को कम करना। यह एक ऐसा एजेंडा है जिसे लेकर भारत, रूस, चीन, ब्राजील सब सहमत है और इसके लिए अपने अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं। भारत इस बारे में ज्यादा प्रैक्टिकल एप्रोच लेकर आगे बढ़ेगा। भारत स्वयं ही अपने कई आर्थिक साझेदार देशों के साथ रुपये में कारोबार करने को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में रूस, यूएई के साथ रुपये में कारोबार की शुरुआत भी हुई है। इंडोनेशिया से लेकर तंजानिया तक के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने के विकल्प पर काम हो रहा है, लेकिन भारत को यह बात बखूबी पता है कि वैश्विक आर्थिक मंच पर चीन का ज्यादा दबदबा है। संभवतः पहले चरण में ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने पर काम होगा।

डालर के वर्चस्व को मिल सकती है चुनौती

लोकमित्र गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

रूस के कजान में आज से आरंभ हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिहाज से कई मायने में महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त 'स्विफ्ट' जैसी सीमापार भुगतान प्रणाली की संभावनाएं तलाश रहा है। स्विफ्ट 'सोसायटी फार वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंसियल टेलीकम्युनिकेशन' एक अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है, जिसका उपयोग दुनियाभर के बैंक और वित्तीय संस्थान सीमापार लेनदेन के लिए करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनियाभर के बैंकों के बीच सुरक्षित और कुशल तरीके से वित्तीय संदेशों (भुगतान निर्देश आदि) का आदान-प्रदान करना होता है। इस प्रणाली के माध्यम से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान एक दूसरे को सुरक्षित संदेश भेज सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और धन का स्थानांतरण तेज और सुरक्षित होता है।

पुतिन का मानना है कि अगर ब्रिक्स की अर्थव्यवस्थाएं यदि अपना एक वैकल्पिक स्विफ्ट विकसित कर लें तो वैश्विक कारोबार में हावी अमेरिकी डालर के वर्चस्व को समाप्त किया जा सकता है। पुतिन ब्रिक्स देशों को अपनी राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के उपयोग को इसलिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालांकि उनके किफायती होने का स्तर इस बात पर निर्भर होता है कि किस प्रकार की डिजिटल मुद्रा की बात हो रही है? साथ ही किन स्थितियों में उनका उपयोग किया जा रहा है।

वस्तुतः डिजिटल मुद्राओं के कई रूप हैं, जैसे क्रिप्टोकरेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) और इलेक्ट्रानिक मनी (ई-मनी)। जहां तक क्रिप्टोकरेंसी की बात है तो कुछ देशों में तो इसकी स्वीकार्यता है मसलन जापान, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर ने क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को अपनी वित्तीय प्रणाली में शामिल कर लिया है। इन देशों में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता भी दी गई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी क्रिप्टोकरेंसी को अपने यहां मान्यता दी है। लेकिन इन सभी देशों के बीच आपसी व्यापार में क्रिप्टोकरेंसी का बहुत सीमित स्तर पर ही उपयोग हो रहा है। इनमें से ज्यादातर देशों की अपनी कोई क्रिप्टोकरेंसी भी नहीं है। इसलिए ब्रिक्स देशों के बीच जिस डिजिटल करेंसी में आपसी व्यापार की कल्पना की जा सकती है, उसमें कम से कम क्रिप्टो तो नहीं ही हो सकती। भारत और चीन तो क्रिप्टोकरेंसी के प्रति सख्त रुख अपनाते हैं। चीन ने लगभग सभी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि भारत में इस पर काफी नियम और विनियम लागू हैं, हालांकि पूर्ण प्रतिबंध यहां भी नहीं है। अब मुख्यतः बचती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। सवाल है क्या सीबीडीसी के जरिये ब्रिक्स देश आपसी व्यापार कर सकते हैं? यह एक संभावित विकल्प तो है और इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। क्योंकि सीबीडीसी वह डिजिटल मुद्रा होती है, जिसे किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है और नियंत्रित भी किया जाता है। इसलिए यह फिएट करेंसी (एक राष्ट्रीय मुद्रा है, जिसका मूल्य किसी भौतिक वस्तु की कीमत से जुड़ा नहीं होता) का डिजिटल संस्करण है और इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित, तेज और सस्ता बनाना होता है।

ब्रिक्स देशों के बीच सीबीडीसी का उपयोग करने के कई फायदे हो सकते हैं- जैसे आपसी व्यापार लेन-देन में बिचौलियों को हटाना, मुद्रा विनिमय लागत को कम करना और सीमापार भुगतान को तेज करना। चूंकि ब्रिक्स देश कई वर्षों से आपसी व्यापार में अमेरिकी डालर पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, इसलिए यह सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। चीन और रूस तो पहले से ही किसी हद तक ऐसा कर भी रहे हैं। (ईआरसी)

खरी-खरी

बाहर कुछ, भीतर कुछ

डा. मनमोहन वाद्य

इधर भगत भगवान की सेवा कर रहे हैं, उधर नेताजी जनता की सेवा कर रहे हैं। भगत की दृष्टि में तो भगवान की छवि सदैव एक जैसी रहती है, किंतु नेताजी के दिमाग में जनता की छवि समय आने पर बदल जाती है। चुनाव के समय नेताजी के लिए जनता साक्षात भगवान बन जाती है और चुनाव के ठीक पश्चात वह भेड़ बन जाती है।

भगवान से भेड़ का रूपांतरण बहुत ही अद्भुत है। गौर से देखा जाए तो परोक्ष रूप से दोनों ही सेवा के बदले मेवा खोज रहे हैं। एक स्वर्ग की कामना में लगा हुआ है तो दूसरा सत्ता की कामना में। स्वर्ग और सत्ता दोनों एक जैसे ही हैं। स्वर्ग आसमान का अहोभाव है और सत्ता धरती का ऐश्वर्य। इन दोनों में गहरा संबंध है, किंतु जहां स्वर्ग एक व्यक्ति को मरने के पश्चात ही मिलता है, वहीं सत्ता का सुख सशरीर ही भोगा जाता है। सत्ता के लिए अशरीरी आत्मा की आवश्यकता नहीं होती।

सच तो यह है कि आत्मा का हनन करके ही सत्ता के गलियारे तक पहुंचा जा सकता है। जब तक देह में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में रहती है, तब तक सत्ता का मार्ग सुगम नहीं होता है। सत्य, न्याय, ईमानदारी, चरित्र इत्यादि नैतिक गुणों के आधार पर एक व्यक्ति कभी भी राजसिंहासन प्राप्त नहीं कर सकता। राजसिंहासन के लिए नैतिकता की चादर को ओढ़ना आवश्यक होता है। जैसे भेड़ की खाल ओढ़कर एक भेड़िया भेड़ के गोश्त का स्वाद चखता है, ठीक वैसे ही नैतिकता की चादर ओढ़कर एक नेता सत्ता का स्वाद चखता है।

एक सच्चा राजनेता समय आने पर नैतिकता का लबादा ओढ़ ही लेता है। उस लबादे के भीतर कौन देखता है? राजनेता सदैव अपने बहिरंग का ही ध्यान रखता है। चुनाव के समय तो उसका बहिरंग और भी आकर्षक हो जाता है। शुभ्र-धवल-चोग, चेहरे की नम्रता, होंठों पर मुस्कान, जनता को ऐसा लगता है कि जैसे कोई मसीहा आसमान से उतरकर जमीन पर आया है। जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, वह मसीहा सत्ता का आनंद लेने में जुट जाता है। यदि चुनाव नहीं जीत सका, तो भी चार साल गायब ही रहता है, पांचवें साल फिर सड़क पर आता है।

X पोस्ट

भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा समझौता हुआ। इस समझौते से न केवल भारत और चीन के संबंध बेहतर होंगे, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
संजय बेनीवाल @im_beniwal

अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगा सकता है, लेकिन भारत कनाडा में निज्जर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या अपनी सुरक्षा का अधिकार भी नस्ल के रंग से तय होता है।
ऐश्वर्य मुदगिल @AishwaryakiRai

अमेरिका अपनी धरती पर भारत के खिलाफ अलगाव की आग भड़का रहे खालिस्तानी आतंकियों का महिमामंडन कर रहा है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए दोहरे हमले के दोषी वहां बिना सजा पाए ही बच निकले।
ब्रह्मा चेलानी @Chellaney

न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर में आखिरी बार तब हराया था, जब मौजूदा टीम में केवल एक खिलाड़ी को छोड़कर बाकियों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। केवल टीम के मौजूदा सदस्य एजाज पटेल ही तब एक साल के थे। कौस्तुभ @kaustats

जागरण जनमत कल का परिणाम

भारतीय टेस्ट टीम के लिए न्यूजीलैंड से मिली हार बड़ी चुनौतियों से पहले का झटका है?

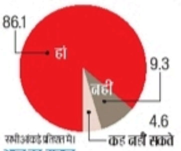

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच पीछे हटने की सहमति के बाद क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अच्छी-अच्छी प्रेरणा देते हैं भगवान,
जज साहब भी अंततः होते हैं इंसान।
होते हैं इंसान आस्था होती सब में,
पाते वह भी ज्ञान ध्यान धरि अपने रब में।
ईश्वर में यदि आप आस्था रखते सच्ची,
मिल जाती है राह आपको सदैव अच्छी।
- ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

मेरुदंड बन गया विरोध का प्रतीक

आमतौर पर मेरुदंड यानी रीढ़ को लेकर कई बातें कही जाती हैं। जब कोई अन्याय के सामने झुक जाता है, अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह 'रीढ़ विहीन' है। जब कोई सिस्टम का हिस्सा होते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो कहा जाता है कि उसकी रीढ़ सीधी है। जब कोई पूरी ताकत व हौसले के साथ परिवार, टीम अथवा संगठन का कार्यभार अकेले अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति अपने परिवार, संगठन या टीम की रीढ़ की हड्डी है। वहीं अब बंगाल में आरजी कर कांड के बाद से 'मेरुदंड' विरोध जताने का प्रतीक बन गया है। 'मेरुदंड नहीं बेचेंगे', 'मेरुदंड सीधा रखें', ये उक्तियां बंगाल में विरोध का 'हाट' नारा बन चुका है। पिछले मंगलवार को ममता सरकार के दुर्गापूजा कार्निवल में ड्यूटी के दौरान 'मेरुदंड नहीं बेचेंगे' लिखा टी-शर्ट पहनने की वजह से पुलिस ने एक सरकारी डाक्टर को गिरफ्तार कर लिया था, जो बता रहा है कि रीढ़ विरोध के हथियार के रूप में स्थापित हो चुकी है।

हालांकि यह भी संयोग ही था कि जिस मेरुदंड के कारण डाक्टर की गिरफ्तारी हुई, उसके अगले ही दिन यानी 16 अक्टूबर को दुनियाभर में 'वर्ल्ड स्पाइन डे' यानी 'विश्व मेरुदंड दिवस' मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत 2012 में रीढ़ को स्वस्थ बनाने के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हुई थी। बंगाल में भले ही रीढ़ दिवस के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरुदंड आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या के बाद से बंगाल के पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन चुका है, यह वे जरूर जान गए हैं। शरीर को खड़ा रखने

प्रदर्शन के दौरान मेरुदंड की प्रतिकृति को हाथ में लिए आंदोलनकारी। फाइल

वाला मेरुदंड सरकार व प्रशासन के खिलाफ विरोध का हथियार बन जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। इसकी शुरुआत आरजी कर कांड के खिलाफ जूनियर डाक्टरों के कोलकाता पुलिस मुख्यालय (लालबाजार) अभियान में हुई थी। जूनियर डाक्टर जब तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के साथ पुलिस मुख्यालय में बैठक करने पहुंचे तो वे वहां प्लास्टिक से निर्मित मेरुदंड की प्रतिकृति अपने साथ लेकर गए थे और उनकी टेबल पर रख दिया था, जिसके बड़े मायने निकाले गए। बाद में धर्मतल्ला में पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तो आंदोलनकारी डाक्टर कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के सामने नारा लगाने लगे जिसका हिंदी में अर्थ है- कोलकाता पुलिस, चूंकि तुम्हारा मेरुदंड नहीं है, इसलिए उस दिन जो देकर आए थे, उसे बेच दिया। इसका सीधा सा अर्थ था कि आंदोलनकारी डाक्टर पुलिस को बताना चाह रहे थे कि मेरुदंड की प्रतिकृति देखकर भी उन्हें सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत नहीं हो रही।

डाक्टरों ने आखिर मेरुदंड को विरोध का माध्यम क्यों बनाया, यह प्रश्न जरूर मन में उठ रहा होगा। दअरसल, आरजी कर अस्पताल में डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले की कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से जांच की, उसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक में कई सवाल उठे हैं। सुबूत मिटाने से लेकर कई तरह के आरोपों में कोलकाता के टाला थाने के तत्कालीन थानेदार को सीबीआइ ने गिरफ्तार भी किया है। तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पुलिस उपायुक्त (उत्तर) अभिषेक गुप्ता को भी पद से हटाया गया है। वैसे पहले से ही बंगाल में पुलिस पर सत्तारूढ़ दल के सामने नतमस्तक रहने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में कोलकाता पुलिस को मेरुदंड की प्रतिकृति देकर डाक्टरों ने यह बताने की कोशिश की कि आप इतने झुक गए हैं कि मेरुदंड सीधा करने की जरूरत है। इसके बाद से मेरुदंड आम लोगों से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की जुबान पर चढ़ चुका है।

कुछ पूर्व आइपीएस अधिकारियों का मानना है कि विनीत गोयल को डाक्टरों द्वारा प्रतीकात्मक मेरुदंड देना सही नहीं था। उनका कहना है कि मेरुदंड का बहुत बड़ा अर्थ है। इसका अर्थ जिम्मेदारी के साथ समाज का निर्माण करना भी है। मेरुदंड देने वालों से वे कहना चाहते हैं कि अगर वास्तव में समाज का मेरुदंड सीधा करना चाहते हैं तो पहले स्वयं राजनेता या आइपीएस बनकर अच्छा काम करके दिखाएं। उन्होंने असम के छात्र आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी बनाने का उदाहरण देते हुए कहा कि डा. बिधानचंद्र राय मुख्यमंत्री बने। जूनियर डाक्टर भी आएं और रीढ़ सीधी कर काम करके दिखाएं। दूसरी ओर आंदोलनकारी जूनियर डाक्टर अभी भी उसी स्थिति पर अड़े हुए हैं। धर्मतल्ला में 'आमरण अनशन' करने वाले डाक्टरों का कहना है- 'चिकित्सकीय दृष्टि से देखें तो मेरुदंड बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लाक्षणिक रूप से मेरुदंड हमारे व्यक्तित्व, अस्तित्व और समाज के प्रति हमारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अन्याय के विरुद्ध विरोध जताने के लिए हमने मेरुदंड को प्रतीक बनाया है।' उन्होंने दावा किया कि अगर कुछ लोग अपना मेरुदंड नहीं बेचे होते तो यह घटना (दुष्कर्म व हत्या) नहीं हुई होती। समाज बहुत सुंदर होता। कुछ लोगों में मेरुदंड बचा है, तभी तो इतने लंबे समय से यह आंदोलन चल रहा है। वहीं कुछ लोग मेरुदंड विहीन हैं, तभी तो दो माह से अधिक समय से आंदोलन करना पड़ रहा है। खैर, इस आंदोलन का नतीजा जो भी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध का नया प्रतीक लोगों को मिल चुका है।

मंथन

डा. अतुल अग्रवाल
प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक), भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

पराली का वैकल्पिक उपयोग

पराली को खेत में जलाने से रोकने के लिए इसे ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ दहन की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसे व्यापक बनाने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है

भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जो हर साल 50 करोड़ टन से अधिक कृषि अवशेष उत्पन्न करता है। अगली फसल बोने की जल्दी में किसान पराली जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। फिर भी वे इसे सबसे सस्ता विकल्प मानते हैं। देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है और आगामी दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धुंध की शुरुआत हो गई है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पराली जलाने पर जुर्माने का प्रविधान किया गया है। फिर भी यह समस्या थम नहीं रही है। ऐसे में इसके मूल कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

फसल चक्र में परिवर्तन : हरित क्रांति के दौरान पंजाब व हरियाणा के किसानों ने अपनी पारंपरिक फसलों (मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन) को छोड़ गेहूं-धान की फसल चक्र को अपनाया। इससे खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित हुई, पर बाद में दुष्परिणाम भी सामने आए। धान के अधिक उत्पादन से पराली का भी उत्पादन बढ़ा, लिहाजा उसके जलाने की घटनाएं बढ़ीं।

उपमृदा जल संरक्षण अधिनियम : पंजाब और हरियाणा में मानसून के आरंभ से पहले धान की रोपाई होती थी। चूंकि धान में पानी की खपत ज्यादा होती है, इसलिए किसान बड़े पैमाने पर भूजल दोहन करके पानी की आवश्यकता को पूरा करते थे। परिणामस्वरूप भूजल के गिरते स्तर को लेकर चिंता पैदा हुई। इसीलिए पंजाब उपमृदा जल संरक्षण अधिनियम और हरियाणा उपमृदा जल संरक्षण अधिनियम (अब भूजल अधिनियम) को मार्च, 2009 में अधिसूचित किया गया। इन कानूनों ने 10 जून से पहले धान की बोआई पर रोक लगा दी, जिससे इसकी कटाई का समय एक महीने बढ़ गया। फसल में देरी के कारण अगली फसल बोने के लिए बहुत कम समय बचता है, ऐसे में किसानों ने पराली को जलाने का विकल्प चुना। वर्ष 2010 के बाद से धान की पराली जलाने में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।

धान की नई प्रजातियां : लंबी अवधि वाली धान की किस्में भी किसानों के पराली जलाने का एक प्रमुख कारण है। अधिक उपज पाने की उम्मीद में किसान लंबी अवधि वाली किस्मों का चयन करते हैं, जिससे अगली फसल बोने के लिए बहुत कम समय बचता है। फलस्वरूप खुले में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं।

एमएसपी : न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अनाज मंडियों जैसी सरकारी योजनाओं का भी पराली जलाने पर प्रभाव पड़ता है। पंजाब में केवल धान, गेहूं, सूरजमुखी और कपास के लिए एमएसपी लागू है, इसलिए अन्य फसलों की तुलना में किसान इन फसलों की बोआई अधिक करते हैं। चूंकि धान की पराली में सिलिका का स्तर उच्च होता है, जो जानवरों के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे चारे के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। इसलिए भी किसान इसे जला देते हैं।

ऐसे में नीति निर्माताओं को इन कारणों पर काबू पाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। जैसे पराली को खुले में जलाने के बजाय बायो-पैलेट्स में परिवर्तित किया जा सकता है, जिन्हें सीधे ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ जलाया जा सकता है। बायो-पैलेट्स के दहन के बाद निकलने वाली कार्बन-डाईआक्साइड की मात्रा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अगले चक्र की फसल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए इसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है।

उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में पराली जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण का खतरा पैदा हो रहा है। फाइल

एनटीपीसी समूह ने दस प्रतिशत बायो-पैलेट्स के मिश्रण से विद्युत उत्पादन का सफल प्रदर्शन किया है। अब केंद्र सरकार देश भर में इसे लागू करना चाहती है। विद्युत मंत्रालय अपनी एक संबंधित नीति के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ पांच से 10 प्रतिशत बायो-पैलेट्स को मिश्रित कर जलाने की सलाह पहले ही दे चुका है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रयासों के फलस्वरूप आज देश भर में 65 ताप विद्युत संयंत्र कोयले के साथ बायो-पैलेट्स को मिश्रित कर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है कि यदि वे पराली को जलाने के बजाय उन्हें जैव-ऊर्जा निर्माताओं को बेचते हैं, तो न केवल उन्हें अतिरिक्त कमाई हो सकती है, बल्कि वे प्रदूषण को रोकने में भी योगदान कर सकते हैं। केंद्र सरकार बायो-पैलेट्स और पराली की नियमित आपूर्ति पर भी काम कर रही है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीसी) फंड के तहत बायो-पैलेट्स विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद की भी घोषणा की है।

कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों में पराली का मिश्रित उपयोग किए जाने से हम न केवल वायु प्रदूषण पर अंकुश लगा सकते हैं, बल्कि कोयले पर हमारी निर्भरता भी कम होगी।

दैनिक जागरण
बड़े सफर की शुरुआत भी एक छोटे कदम से ही होती है

फिर झुका चीन

चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कोई समझबूझ कायम होने के आसार काफी पहले उभर आए थे, लेकिन इसकी प्रतीक्षा थी कि वह समझौते में कब बदलती है और दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 वाली स्थिति में कब लौटती हैं। अंततः यह समझौता हो गया। इस समझौते का एक कारण रूस में होने जा रहा ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन तो है ही, भारत की यह प्रतिबद्धता भी है कि जब तक सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होती, तब तक चीन से संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जून 2020 में गलवन घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सेना से खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध पटरी से उतर गए थे। भारत के अडिग रवैये के चलते चीनी सेना गलवन घाटी में तो पुरानी स्थिति में लौट गई थी, लेकिन उसने देपसांग और डेमचोक में यथास्थिति में बदलाव के इरादे को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी चीन से लगती सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच वार्ता का सिलसिला कायम हुआ। चीन की चेष्टा यह थी कि भारत सीमा पर तनाव की अनदेखी कर संबंध सामान्य करने के लिए तैयार हो जाए। भारत टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार चीन को समझ आया कि उसकी दादागीरी और चालाकी काम आने वाली नहीं है।

हाल के वर्षों में भारत ने अपने अडिग रवैये से चीन को दूसरी बार झुकने को बाध्य किया है। इसके पहले डोकलाम में उसने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये के खिलाफ अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया था। तब भी चीन ने खूब गर्जन-तर्जन किया था, लेकिन भारतीय सेनाएं मोर्चे पर डटी रही थीं। तब भी चीन पीछे हटने को विवश हुआ था और अब भी। यह अच्छी बात है कि उसे यह समझ आया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता और यह 1962 वाला समय नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इसका सीधा उत्तर है-नहीं। वह अभी भरोसे काबिल नहीं। वह अरुणाचल, लद्दाख और कश्मीर को लेकर जिस तरह बेजा बयानबाजी करता रहता है और सीमा विवाद के स्थायी हल की इच्छा नहीं जता रहा है, उसे देखते हुए उससे सतर्क रहने में ही भलाई है। भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चीन को भरोसेमंद बनने के लिए सीमा विवाद को स्थायी रूप से हल करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सीमा विवाद को हल करने के लिए बीते तीन-चार दशक से वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इसका कारण सीमा विवाद की आड़ में भारत को तंग करते रहने वाला चीन का रवैया है। ऐसे में भारत को सीमाओं की रक्षा को लेकर सतर्क रहने के साथ ही चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयत्न भी जारी रखने होंगे।

त्वरित न्याय

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाक्सो की विशेष अदालत ने एक मुकदमे में केवल 29 दिनों के भीतर निर्णय सुनाकर न्यायिक व्यवस्था के समक्ष यह उदाहरण रखा है कि प्रयास किए जाएं तो मुकदमों का निस्तारण शीघ्र हो सकता है। यह मुकदमा एक किशोरी से दुष्कर्म का था जिसमें अदालत ने अभियुक्त को 20 साल जेल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस प्रकरण को इसलिए भी मील का पत्थर कहा जा सकता है, क्योंकि एक जुलाई, 2024 को भारतीय न्याय व्यवस्था लागू होने के बाद उसकी धाराओं के तहत प्रदेश में यह पहला निर्णय आया है। निश्चित रूप से इसके लिए कोर्ट की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि बिना उसकी तत्परता के शीघ्र न्याय संभव नहीं, लेकिन पुलिस और अभियोजन भी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने अपने कार्य को समय पर पूरा किया। पुलिस अपने काम में तत्परता लाए और अभियोजन मुकदमे को लेकर गंभीर हो तो न्याय न केवल शीघ्र मिलेगा, बल्कि होता भी दिखाई देगा। अपराध के मामलों में कोई मुकदमा लंबा खिंचने का अर्थ है कि पीड़ित को वास्तविक अर्थों में न्याय नहीं मिल पा रहा है।

लंबित मुकदमे न्यायिक व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक इसके बोझ से दबा हुआ है। हाई कोर्ट की ही बात करें तो लगभग 10 लाख मुकदमे अपने निस्तारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिलास्तरीय व अन्य अदालतों में तो इनकी संख्या करोड़ों में है। मुकदमों का बोझ कम करने के लिए न्यायिक प्रशासन ने कई प्रयास किए जरूर, लेकिन इनका विशेष प्रभाव देखने में नहीं आया। लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ने के कारण भी चिह्नित हैं, इसलिए यह जरूरी है कि अदालतों में रिक्त न्यायाधीशों के पद जल्द भरे जाएं। अपराध के मामलों का जल्द निस्तारण तो अत्यंत जरूरी है। कानून व्यवस्था भी तभी पूर्ण रूप से सफल होगी, जबकि अपराधी कोर्ट से सजा पाकर जेल की सींखचों के भीतर दिखाई दें।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व

श्रीराम चौलिया

विकासशील देशों के बीच चीन का दबदबा घटाने के उद्देश्य से भारत के लिए ब्रिक्स भी क्वाड जितना उपयोगी है

अवधेश राजपूत

ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उसमें सहभागिता करेंगे। इस वर्ष की ब्रिक्स बैठक खास मायने रखती है, क्योंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्ण सदस्य बनने के बाद यह पहला अवसर है जब ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के रूप में चार नए सदस्य शिखर वार्ता में शामिल होंगे। अपने संस्थापक देशों के नाम के पहले अक्षर से जाना जाने वाला ब्रिक पहले ब्रिक्स हुआ और अब ब्रिक्स का भी विस्तार हो रहा है। स्पष्ट है कि सदस्यों में वृद्धि के कारण इस समूह की राजनीति एवं कार्यशैली में अंतर पड़ेगा।

इस बार ब्रिक्स शिखर बैठक का मुख्य विषय है बहुपक्षवाद को मजबूत करना। पहले की तुलना में आज नौ सदस्यों के रहते ब्रिक्स की बहुपक्षीय प्रमाणिकता बढ़ी है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के प्रमुख देशों के प्रतिनिधित्व से संगठन की छवि और दृष्टिकोण में विविधता आई है, जो प्रगतिशीलता का संकेत है। हालांकि इसके साथ ही सर्वसम्मति और निर्णयन में चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। चीन और रूस का अमेरिका के साथ छत्तीस का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं। ये दोनों चाहते हैं कि विस्तारित ब्रिक्स पश्चिम के विरुद्ध मजबूत मोर्चा बने और पश्चिमी शक्तियों के पाखंड के खिलाफ आवाज उठाए। चीन का बस चलता तो पाकिस्तान सहित कई विकासशील देशों को सदस्यता देकर ब्रिक्स को विकसित देशों के रास्ते का कांटा बना सकता था, लेकिन भारत ने इसका अंधाधुंध विस्तार नहीं होने दिया। वह अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी सामरिक साझेदारियों का ख्याल करते हुए ब्रिक्स को वैचारिक मंच बनने से रोक रहा है। हालांकि सीमा पर सैनिकों की गश्त को लेकर भारत चीन के साथ समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा और तनाव जारी रहेंगे और यह ब्रिक्स में भी परिलक्षित हो सकता है।

अंदरूनी रस्साकशी में भारत और ब्राजील विचारधारा केंद्रित दृष्टिकोण से परे हैं और वे व्यावहारिक सहयोग तथा विकास से संबंधित नए उपक्रमों को ब्रिक्स की कार्यसूची में प्राथमिकता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त, व्यापार, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों में आपसी तालमेल और परस्पर लाभ पर भारत का ध्यान है। इस दृष्टि को साकार करने के लिए नए सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया और अमीरात भारत के करीबी हैं। हालांकि ईरान के साथ भी भारत की सामरिक साझेदारी है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और अमेरिका के करीबी इजरायल से ईरान का संघर्ष यही संकेत करता है कि तेहरान का झुकाव चीन और रूस की ओर रहेगा। अगर दो अन्य देश-अर्जेंटीना और सऊदी अरब भी ब्रिक्स के दायरे में आ जाएं तो भारत का पलड़ा भारी हो सकता है। इन देशों को सदस्य बनने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अभी वे इससे किनारा कर रहे हैं। भारत ब्रिक्स में नए भागीदार देशों की सूची पर आम सहमति बनाने की रूपरेखा तैयार करने में भी जुटा है। चीन के विस्तारवादी रवैये को देखते हुए नए देशों का चयन और सदस्यता का मार्ग तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रक्रिया से विकासशील जगत के नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा का फैसला हो सकता है। मोदी सरकार ने भारत को विकासशील देशों का सच्चा मित्र एवं मुखर आवाज के रूप में स्थापित किया है व विकास के भारत के प्रारूप को चीन से अलग हटकर दिखाया है, जिसकी प्रकृति कहीं अधिक समावेशी एवं साझा हितों को पोषित करने वाली है। भारत के ये प्रयास उल्लेखनीय हैं, क्योंकि विकासशील देशों के बीच चीन अपनी पैठ बढ़ा अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है।

कुछ आलोचकों का सवाल है कि ब्रिक्स में चीन की दमदार उपस्थिति के चलते भारत को ऐसे संस्थान से भला क्या लाभ मिलेगा? इसमें दो राय नहीं कि भूराजनीति एवं सामरिक दृष्टिकोण से ब्रिक्स के मुकाबले क्वाड भारत के लिए कहीं अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाने के लिए आवश्यक कदमों पर सहमति बनाने से लेकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता को लेकर भारत ब्रिक्स के मंच पर भी अपनी आवाज उठा रहा है। इसके जरिये भारत के सुरक्षा हितों की अपेक्षित पूर्ति संभव नहीं लगती। जब तक रूस पूरी तरह भारत के पाले में रहा, तब तक चीन की चुनौती का संतुलन साधने में भारत को कुछ सफलता मिलती रही, लेकिन अब रूस चीन पर इतना निर्भर हो गया है कि उसके भरोसे चीनी चुनौती का जवाब तलाशना व्यावहारिक नहीं रहा।

ब्रिक्स के शुरुआती वर्षों में चीन आज के मुकाबले कम शक्तिशाली था और वह भारत का जोड़ीदार माना जाता था। तब सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट होकर विकसित देशों से सामूहिक सौदेबाजी करने का स्वप्न सच्चा लगता था, जबकि मौजूदा दौर में चीन ब्रिक्स पर अपने वर्चस्व की फिराक में है। ऐसे में यह आशंका निर्मूल नहीं कि चीन इसे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना सकता है। प्राचीन चीनी रणनीतिकार सुन जू ने कहा था कि सम्राट द्वारा 'दोस्तों को करीब रखना चाहिए, मगर दुश्मनों को उससे भी अधिक करीब रखना चाहिए, ताकि उनकी गतिविधियों और पैंतरों का अंदाजा मिलता रहे।' चीन के विस्तारवाद को टक्कर देने में भले ही क्वाड जैसे समूहों के पास प्रत्यक्ष और स्पष्ट अधिदेश हो, लेकिन विकासशील देशों के बीच चीन के दबदबे को घटाने के लिहाज से ब्रिक्स भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय कूटनीति का यह स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि ब्रिक्स में किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होने देना है और इस समूह के द्वारा आर्थिक और व्यापारिक लाभ मिलने का सिलसिला कायम रहे। परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के 'नए विकास बैंक' के वित्तीय सौजन्य से भारत में जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे देश को लाभ ही मिलेगा। ब्रिक्स के इस नए युग के आरंभ में भारत दूरदर्शिता के आधार पर कार्य करे तो अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी।

(स्तंभकार अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और 'फ्रैंड्सः इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स' के लेखक हैं)

response@jagran.com

हमारी पुरानी परंपरा है परोपकार

आरके सिन्हा

यह कहना ठीक नहीं कि हमारे कारोबारियों ने परोपकार की भावना पश्चिम से सीखी

मुफ्त शिक्षा का एक केंद्र। फाइल

रतन टाटा के निधन के पश्चात उनके परोपकारी कार्यों की खूब चर्चा हो रही है। न केवल टाटा समूह, बल्कि भारत के अनेक छोटे-बड़े लाखों कारोबारी अपने स्तर पर कुछ न कुछ परोपकार से जुड़े कामों में लगे हुए मिल जाएंगे। यह कहना गलत होगा कि हमारे कारोबारियों, धनिकों आदि ने परोपकार की भावना पश्चिमी कारोबारियों से सीखी। यह कुछ अज्ञानियों का प्रचार भर है कि वारेन बफे, बिल गेट्स आदि कारोबारी परोपकार के प्रणेता हैं। ऐसा होता तो जमशेदजी टाटा पिछली सदी के सबसे बड़े दानवीर के तौर पर नहीं जाने जाते। भारत में परोपकार की परंपरा प्राचीन काल से ही गहरी जड़ें जमाए हुए है। हम 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया' में विश्वास करने वाले हैं। आज भी आपको पहली रोटी गौ माता को.. में विश्वास करने वाले अनेक लोग मिल जाएंगे। धर्म, संस्कृति और समाज के हरेक पहलू में दान, सेवा और परोपकार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथों में परोपकार को दान और सेवा के रूप में वर्णित किया गया है। सनातन धर्म में दान और सेवा का बहुत महत्व है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से वानप्रस्थ और संन्यास में परोपकार को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य माना गया है। जैन धर्म में दान को अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म में भी दान का खासा महत्व है, जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवनकाल में दान, सेवा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। गुरु नानकदेवजी और अन्य संतों ने भी परोपकार पर जोर दिया। गांधी जी ने 'सर्वोदय' के सिद्धांत पर बल दिया और ग्रामीणों की सेवा और विकास के लिए जीवन भर काम किया। रतन टाटा की तरह बिड़ला, अजीम प्रेमजी, नंदन नीलेकणी, शिव नादर जैसे सैकड़ों उद्योगपति परोपकार से जुड़े कार्यों के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपया दान देते हैं। समाज सेवा हमारे कारोबारियों के डीएनए में है।

टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की दूरदृष्टि से स्थापित इस समूह ने शुरू से ही समाज सेवा को अपने कार्यों का अभिन्न अंग बनाया, जिसे अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी निभा रही है। जमशेदजी के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने दीन दुखी जन के लिए सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। उनका मानना था कि सामाजिक सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। शिकागो के सर्व धर्म सम्मेलन में जाने के पूर्व जब विवेकानंद भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें यह बात अखरी कि दक्षिण भारत में विज्ञान की उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाला कोई संस्थान नहीं है। उन्होंने विचार किया कि इस काम में जमशेदजी टाटा उपयुक्त होंगे। उन्होंने शिकागो जाने के पूर्व उन्हें पत्र लिखा, 'आप बिहार के जमशेदपुर से अच्छा पैसा कमा रहे हो। मेरी शुभकामना है कि और अधिक धन अर्जित करो और अधिक लोगों को रोजगार दो, लेकिन विज्ञान की उच्चतर शिक्षा से वंचित दक्षिण भारत की भी थोड़ी चिंता करो और विज्ञान की पढ़ाई और शोध का कोई बढ़िया संस्थान स्थापित करो। आप यह कर सकते हो और विश्वास है कि ऐसा ही करोगे।' स्वामी विवेकानंद का यह प्रेरक पत्र पढ़ने के बाद जमशेदजी ने बेंगलुरु में विज्ञान संस्थान शुरू किया, जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस के नाम से विख्यात है।

एक फक्कड़ संन्यासी के आशीर्वाद से घनश्याम दास बिड़ला ने अपना उद्योग जमाया। उसी संन्यासी के आशीर्वाद से 'करनी और बरनी' का काम आज भी बिड़ला समूह कर रहा है। यह अपने धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मध्ययुगीन भारत में राजाओं और धनिकों द्वारा अनेक धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना की गई, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित थे। आपको गांव, कस्बे, शहर में गैर-सरकारी प्रयासों से चल रहे प्याऊ, स्कूल, कालेज, क्लीनिक और धर्मशालाएं आदि मिल जाते हैं। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि कोविड महामारी के दौरान आम और खास व्यक्तियों ने किस तरह खुलकर दान दिया और लोगों की मदद की।

अभी कुछ दिन पहले शारदीय नवरात्र संपन्न हुए। इस दौरान देश के तमाम शहरों में भंडारे चलते रहे। भंडारों में समाजवादी व्यवस्था वास्तव में बहुत प्रभावशाली होती है। भंडारों में प्रसाद बंटता है। देश की राजधानी दिल्ली भंडारों की भी राजधानी है। कहते हैं कि कैसेट किंग गुलशन कुमार ने भंडारा संस्कृति का पुनर्जागरण किया। उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारे का आयोजन शुरू किया था। भंडारा अपने आप में जात-पात और वर्ग की दीवारों को तोड़ता है। भंडारों की एक खास बात यह भी है कि इनसे प्रसाद हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब ग्रहण करते हैं। दक्षिण दिल्ली के पिलंजी गांव में कुछ युवकों ने कुछ साल पहले 'बालाजी कुनबा' नाम से एक संगठन स्थापित किया। इसका मकसद है भूखों की भूख मिटाना। ये हर रोज एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राममनोहर लोहिया अस्पताल के आगे तीमारदारों को भरपेट भोजन कराते हैं। बालाजी कुनबा के सदस्यों की कारों पर हनुमानजी की तस्वीर वाला एक बैनर लगा होता है। जिस पर 'बालाजी कुनबा-एक परिवार भूख के खिलाफ' लिखा रहता है। भंडारे के लिए पैसों का जुगाड़ गांव के लोग ही करते हैं। देश भर में ऐसे न जाने कितने संगठन हैं। स्पष्ट है कि परोपकार और समाज सेवा तो हम भारतीयों के जीवन का हिस्सा है। आपको अमेरिका या यूरोप में कहीं कोई भंडारा नहीं मिलेगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं पूर्व सांसद हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

बौद्धिक संपदा

नियति एक अबूझ पहेली है। इसके गर्भ में क्या छिपा है, इसे जानने का कोई मार्ग नहीं है। कभी-कभी हम नियति के चक्र में ऐसे फंसे होते हैं कि लगता है कि कितना भी हाथ पैर मार लें, रेत में रुकी हमारी नाव आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। नियति को ईश्वर की इच्छा मानकर कुछ औसत प्रतिभा वाले लोग समर्पण कर देते हैं, परंतु समस्या उनके साथ आती है जो प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु नियति उन्हें कुछ ऐसे बंधनों में बांध कर रखती है कि वे सांसारिक दृष्टि से असफल ही दिखते हैं। कभी-कभी यूं भी होता है कि कितना भी प्रयास कर लें तब भी सांसारिक मानकों की पूर्ति होती नहीं दिखती। ऐसे में लगता है कि हम किसी अदृश्य दीवार के विरुद्ध सिर पटक रहे हैं, परंतु खिड़की है कि खुलती ही नहीं।

पिता की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। वह अपने गुरु रामकृष्ण जी की शरण में थे। गुरु की आज्ञा से वह मां काली से अपने परिवार के लिए अन्न और वस्त्र की भिक्षा मांगने जाते थे, परंतु जीवंत प्रतिमा के समक्ष मौन होकर रह जाते थे और अंत में शक्ति एवं भक्ति का वरदान मांगकर चले आते थे। यदि नियति हमें कथित सांसारिक मानकों के अनुसार विफलता दे रही है तो विश्वास रखिए, उसकी हमें कहीं और सफलता देने की योजना है। कारागार में बंद व्यक्ति के लिए भी विकास की विपुल संभावना होती है। कई प्रसिद्ध एवं कालजयी पुस्तकें जेल में ही लिखी गईं। जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक अपनी प्रतिभा को समृद्ध करते रहने का, स्वाध्याय से बुद्धि को पैना करते रहने का विकल्प आपके पास है। बौद्धिक संपदा भी एक प्रकार की उपलब्धि है। संभव है भौतिक संपदा शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने वाली न हो, किंतु विचार सदियों तक प्रासंगिक रहकर आपकी विरासत गढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन को बौद्धिक सार्थकता की दृष्टि से देखना अधिक अर्थपूर्ण है।

द्विंकल तोमर सिंह

बाजार और एमएसपी के बीच संतुलन

राजेंद्र शर्मा

किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिल रहा है, पर बाजार पर नियंत्रण होने से और अधिक लाभ दिलाया जा सकता है

किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं समेत छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर दी है। बोआई के समय ही फसलों के एमएसपी की घोषणा अच्छी परंपरा मानी जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा सरसों की एमएसपी में बीते साल की तुलना में सर्वाधिक 300 रुपये, मसूर में 275 रुपये, चना में 210 रुपये और गेहूं में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खरीद की शुरुआत भी समय पर कर दी जाती है। अब आनलाइन व्यवस्था होने से खरीद में कुछ हद तक पारदर्शिता आई है तो भुगतान भी सीधे किसान के खाते में होने से भुगतान में होने वाले लीकेज को भी रोका गया है। परंतु बाजार पर नियंत्रण का मामला जस के तस है। पिछले डेढ़ माह में समूचे देश में गेहूं के भावों में तेजी आई है और आटा के भावों में व्यापक वृद्धि हुई है। वैसे सरकार द्वारा गेहूं, चना, सरसों आदि की समय पर खरीद तो शुरू कर दी जाती है, परंतु आवश्यक यह भी हो जाता है कि जब तक बाजार भाव सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के करीब नहीं आ जाते हैं, तब तक सरकारी खरीद जारी रहनी चाहिए। सरकार को यह समझना होगा कि सरकारी खरीद की घोषणा होते ही पहले बाजार में उस अनाज के भावों में तेजी आ जाती थी और खरीद आरंभ होते होते सरकार द्वारा घोषित दर और बाजार की दरों के बीच लगभग संतुलन आ जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं होता है।

सरकार को बाजार पर नजर रखने वाली विशेषज्ञों की टीम भी बनानी होगी या कहें कि इस तरह के विशेषज्ञों को और अधिक सक्रिय करना होगा, तब खरीद बंद होने व उसके बाद बाजार में कृत्रिम कमी दिखाते हुए बाजार भावों में तेजी आ जाती है। यह भी देखना होगा कि बाजार में एक बार भाव बढ़ने पर उन्हें पूर्व स्तर पर लाना मुश्किल भरा काम हो जाता है।

वस्तुतः ऐसे हालातों से अन्नदाता, सरकार और आम आदमी तीनों ही प्रभावित होते हैं व लाभ केवल बिचौलियों को होता है। अन्नदाता नाराज होता है कि उसे अपनी पैदावार के पूरे पैसे नहीं मिले, बाजार भाव बढ़ने से आम आदमी की नाराजगी साफ है तो वहीं सरकार की भी किरकिरी होती है। ऐसे में यदि बाजार पर नजर रखने वाली टीम सशक्त हो, बाजार के हालातों पर सही तरीके से दूरगामी विश्लेषण किया जाता हो, तो बाजार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब यदि निगरानी तंत्र मजबूत हो तो संभावित कमी वाले दिनों में बाजार पर नियंत्रण की पहले से ही तैयारी की जा सकती है और इससे सरकार और आम आदमी दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

समझना होगा न्याय का मर्म

'प्रभावी सिद्ध हों न्याय की देवी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में हृदयनारायण दीक्षित ने न्यायिक प्रणाली की देरी और प्रक्रियाओं की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, न्याय को अधिक पारदर्शी, सुलभ और शीघ्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्याय की देवी का प्रतीक, आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू थामे हुए, सदियों से निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। इसका स्पष्ट संदेश है कि न्याय किसी भी पक्षपात से दूर होना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में यह प्रतीक क्या वास्तव में न्यायिक व्यवस्था की वास्तविकता को दर्शाता है? जब हम भारतीय न्याय प्रणाली को करीब से देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि ऐसी प्रतीकात्मकता और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रमुख समस्या है-मामलों का लंबित होना। अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े लाखों मामलों ने न्याय की गति को धीमा कर दिया है। न्याय की प्रतीक्षा करते-करते कई बार व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है और वह अन्य विकल्पों की तलाश करता है, जो शायद न्यायिक व्यवस्था से बाहर के हों। इससे समाज में कानून और व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले, न्यायिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जानी चाहिए। तकनीकी नवाचारों के माध्यम से मामलों की सुनवाई को आसान और तेज गति से किया जा सकता है। न्यायधीशों की संख्या में वृद्धि और विशेष न्यायालयों की स्थापना से भी न्याय मिलने में देरी को कम किया जा सकता है।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

स्वच्छता मिशन और संवेदनशील नेतृत्व

हमारे प्रधानमंत्रीजी द्वारा एक बार चुनाव प्रचार के दौरान कही गई यह बात कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं, उसे बाद में प्रतिपक्ष के नेताओं ने जुमला कह कर उनका मजाक उड़ाया था। ऐसे लोगों को दैनिक जागरण में सोमवार को प्रकाशित रमेश कुमार दुबे के 'जन-जन का मिशन बनी स्वच्छता' आलेख को अवश्य पढ़ना चाहिए। वस्तुतः इस आलेख में यह उल्लेख किया गया है कि यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार, स्वच्छता के कारण परिवारों को हर साल औसतन 50 हजार रुपये की बचत हो रही है, जो पहले बीमारियों से होने वाली चिकित्सा पर खर्च होते थे। इसके अलावा, हर वर्ष 60-70 हजार बच्चों को डायरिया के कारण काल-कवलित होना पड़ता था, जिनकी इस मिशन के फलस्वरूप जान बच रही है। यही नहीं, देश भर में बेहतरीन सड़कों के नेटवर्क, बेहतरीन रेलवे सुविधाओं, डिजिटल भुगतान, फिट इंडिया एवं अन्य आनलाइन सेवाओं के चलते जो प्रत्येक देशवासी के समय और साधनों की बचत हो रही है, उसे यदि एकसाथ मिलाया जाए और उसका मौद्रीकरण किया जाए तो यह राशि 15 लाख रुपये से अधिक ही बैठेगी। यह भी सच है कि लोकतंत्र में बिना लोक के सहयोग के कुछ संभव नहीं है। यह संतोष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व एवं उनकी बेहतरीन टीम ने जनहित और जनहित के मुद्दों को सर्वोपरि रखते हुए स्वच्छता मिशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लाल किले से उठाया, उसके महत्व को जन-जन तक पहुंचाकर उसे जनांदोलन का स्वरूप प्रदान किया। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि अब लोग सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। इस अभियान के चक्रीय प्रभाव हुए हैं। विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था से जहां उनकी नामांकन दर में वृद्धि हुई है, वहीं छात्र-छात्राएं स्वच्छता मिशन का भी महत्वपूर्ण अंग बने हैं। इनके माध्यम से स्वच्छता मिशन घर-घर तक पहुंचा है और आज देश के अधिकांश घरों में शौचालय हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश के हर भाग में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। लोग स्वच्छता मिशन के कारण अब स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों के प्रति भी जागरूक हुए हैं। पशु अपशिष्ट को बायोगैस में बदला जा रहा है। यह अभियान देश को एक नई पहचान देने के साथ ही विकास को नई दिशा एवं गति देने में सफल हुआ है।

योगराज, खरड़, पंजाब

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 22 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

घाटी में फिर खून-खराबा

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों के हमले में 7 लोगों के मारे जाने की घटना वाकई चिंता का सबब है। राज्य में नई सरकार के गठन के चार दिन के भीतर आतंकियों ने दूसरी बार दुस्साहस किया। इस घटना में जहां 5 श्रमिक बाहरी राज्यों के हैं वहीं इससे पहले की गई कायराना हरकत में भी एक बाहरी श्रमिक की हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने बड़ी परियोजना के क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का हमला किया है। एक और तथ्य विचारणीय है कि जिस इलाके में यह हमला किया गया है, वह आमतौर पर आतंकी हमलों से अछूता है। यानी अब आतंकी गुट उन इलाकों और लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो ज्यादा चर्चित नहीं हैं। हालांकि बाहर के राज्यों के लोगों को मारने (टारगेट किलिंग) का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है, मगर

साल भर से यह थमा हुआ था। दरअसल, राज्य में लोकतंत्र की मजबूती से पाकिस्तान और दुश्मन देश बौखला गए हैं, उनमें इस बात को लेकर गहरी निराशा है कि राज्य में बिना किसी हंगामे और हिंसा के विधानसभा और इससे पहले लोक सभा के चुनाव संपन्न हो गए। पाकिस्तान यह कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर में अमन बहाल हो। सीमा पार से आंतक फैलाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की उसकी करतूतों को पूरी दुनिया जान और समझ गई है। इसके बावजूद वह बाज नहीं आ रहा है। वैसे देखा जाए तो केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से आतंकवादी गुटों पर सख्ती हुई है। मोदी सरकार तो यहां तक दावा करती है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य में मोदी सरकार के बाद आतंकी घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ी हैं, बहुत सारे निरपराध लोग मारे गए हैं और अनेक सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। दरअसल, राज्य के भूगोल और इतिहास पर दृष्टिपात करें तो तमाम प्रयासों और सख्ती के बावजूद यहां से आतंकवाद को समूल नष्ट करना बेहद दुष्कर है। इसकी वजह है स्थानीय लोगों का दहशतगर्दों को खुला समर्थन। इस बात को खुद दो वर्ष पहले सरकार ने भी माना था कि राज्य का दर्जा खत्म करने और कर्फ्यू के दौरान स्थानीय युवाओं की आतंकी समूहों में भर्ती बढ़ी है। हकीकत यह है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा वो गलत रास्ते पर जाएंगे ही। इन सब प्रतिकूल हालात के बीच अच्छी बात यह हुई कि जनता ने आतंकियों, उनके परिवार के लोगों को चुनाव में जबरदस्त चोट पहुंचाई है। फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है।

राजनीति और परिवारवाद

गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के एक लाख नौजवानों को राजनीति में लाने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा ये देश की राजनीति की दिशा बदलेंगे। उन्होंने 'परिवारवाद की राजनीति' को देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा, आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बनें। जो हम कहते हैं, डंके की चोट पर कर दिखाते हैं। मोदी ने ये बातें वाराणसी में कही। मोदी अपनी चुनावी रैलियों में भी वंशवाद पर करारा प्रहार करते रहे हैं। यह सच है कि उनके अपने परिवार से अब तक कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। मगर यदि पूरे दल के लिहाज से देखा जाए तो यह भाजपा पर खुद भी पूरी तरह लागू होता नहीं नजर आ रहा। वंशवाद तथा परिवारवाद के खिलाफ तीखे तेवर रखने वाले मोदी भी इस सचाई से मुंह नहीं फेर सकते। भाजपा में ढेरों नेता परिवारवाद की ही देन

हैं। तमाम खींचतान के बावजूद युवा नेताओं की बड़ी संख्या के पीछे वंशवाद ही है। भाजपा हमेशा खुद को परिवारवादी दल होने से इनकार करती रही है। मगर दल के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी पर परिवार के कब्जे का तर्क देते हुए नेताओं के बच्चों को राजनीति में आने का रास्ता प्रशस्त करने सरीखी बातें करते हैं। देश में कोई भी राजनीतिक दल परिवारवादी होने के आरोपों से बचा नहीं है। यह कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस, सपा, राजद व एनसीपी जैसे तमाम क्षेत्रीय दल भी विरासत के तौर पर अपनी अगली पीढ़ी को मुखिया बनाने का काम बेधड़क करते हैं। वे तरह-तरह की दलीलों से तुष्टिकरण करना चाहते हैं। दरअसल, परिवारवाद से मुक्त रह पाना और राजनीतिक विरासत पर उचित उम्मीदवार या दावेदार को पदभार देने का जिगर रखना आसान नहीं है। नौजवानों को राजनीति में लाने का आह्वान सभी राजनीतिक दल समय-समय पर करते हैं। कुछ ही दिन पहले भाजपा में नये सदस्य बनाने का जो सिलसिला चालू हुआ है, उसमें जनता को बरगला कर सदस्यता देने की खबरें खूब आ रही हैं। राजनीति के प्रति आमजन को आकर्षित करने के लिए जरूरी है, इसे पारदर्शी बनाया जाए। अमूमन सफल राजनेताओं को नेतागिरी के इतर किसी अन्य पेशे में भी हाथ आजमाना पड़ता है। फिलहाल देश की आधे से अधिक आबादी जवानों की है। दीगर है कि राजनीति में युवा आएंगे तो जोश और बदलाव खुद-ब-खुद नजर आता दिख सकता है।

साफ-सफाई/अमित बैजनाथ गर्ग

कचरे का निपटान जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता और कचरे के निपटान की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जोड़ना है। यह अभियान एक दिन, एक साल का नहीं है। यह युगों-युगों तक निरंतर करने वाला काम है। जब तक स्वच्छता हमारा स्वभाव बन जाए, यह तब तक करने का काम है। असल में स्वच्छता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कचरे का निपटान है, जो पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जनसंख्या बढ़ने से अपशिष्ट की मात्रा लगातार बढ़ी है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगभग सभी देश बढ़ते कचरे के कुशलतापूर्वक निपटान की चुनौती का सामना कर रहे हैं। असल में ठोस अपशिष्ट के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से संचालित कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े-करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, ताकि कम-से-कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को लैंडफिल क्षेत्र में फेंकना पड़े। इसका कारण यह है कि लैंडफिल में फेंके जाने वाले कूड़े का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तो इसके लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है। दूसरा कूड़ा वायु, मिट्टी और जल-प्रदूषण का संभावित कारण भी है। एक अनुमान के अनुसार, इस समय दुनिया में प्रतिवर्ष 201 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। इसका एक तिहाई खतरनाक तरीके से वातावरण में फेंका जा रहा है, जो आने वाले समय में बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। भारत सहित दुनिया को कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए विशेषज्ञ चार आर का सिद्धांत अपनाने की बात करते हैं। इसमें पहले आर का अर्थ रिफ्यूज यानी प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग से इनकार करना, दूसरे आर का अर्थ रिड्यूस यानी प्लास्टिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करना, तीसरे आर का अर्थ रीयूज यानी नये की बजाय पुराने प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग करना और अंत में रिसाइकिल यानी पुराने प्लास्टिक पदार्थों को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग करना है। कुल मिलाकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।

अनमोल वचन

लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, अत्यन्त निपुणता से, जड़ जमाती है और संयम से स्थिर रहती है

-महाभारत

सच को स्वीकारें

बहराइच हिंसा

अवधेश कुमार

बहराइच सांप्रदायिक हत्याकांड के आरोपियों के मुठभेड़ पर जिस त्वरित गति से तीखी प्रतिक्रिया आई उसका शतांश भी रामगोपाल मिश्रा की हत्या और उसके साथ हुई बर्बरता पर नहीं देखी गई। यह भारतीय राजनीति, बौद्धिक जगत और एक्टिविज्म की दुनिया की ऐसी ट्रेजेडी है जिसकी समानता इतिहास में ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपियों के पैर में ही गोली लगी। पुलिस के हर मुठभेड़ को झूठ और गैरकानूनी हत्या या गोली मारना बताने वाले नेता व एक्टिविस्ट इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बरत पाए कि वे गोपाल मिश्रा के साथ हुई बर्बरता की निंदा करते।

समूचे देश में भाजपा विरोधी आम नेताओं, पार्टियों, मुस्लिम नेताओं, बुद्धिजीवियों, नामी मौलानाओं, इमामों, संस्थानों के प्रमुखों सबके बयानों को खंगाल लीजिए, आपको शायद ही कहीं रामगोपाल मिश्रा की हत्या व नृशंसता की आलोचना में एक शब्द मिल जाए। ठीक इसके विपरीत दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और उसमें शामिल लोगों के व्यवहार, डीजे से निकलते गानों आदि की आक्रामक आलोचना और निंदा की भरमार मिलेगी। पूरा इको सिस्टम और नैरेटिव ऐसा बनाया गया मानो प्रतिमा विसर्जन करने निकले लोग ही दोषी हैं, उन्होंने उकसाया, जबरन घर पर चढ़कर हरे झंडे उतारे और उधर से केवल प्रतिक्रिया हुई। जिन लोगों ने आरंभ में चुप्पी साधी वे भी मुठभेड़ के बाद इसी तरह का नैरेटिव लेकर आ गए हैं। यह हतप्रभ करने वाली स्थिति है।

टीवी डिबेट में पूछने पर अवश्य बोलेंगे कि हत्या गलत है पर-किंतु-परंतु लगाते हुए प्रतिमा विसर्जन में शामिल लोगों को ही दोषी साबित करने के लिए सारे तर्क हैं। कोई भी साहस के साथ यह सच बोलने को तैयार नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार हिंदू पर्व-त्योहारों ,उत्सवों, दिवसों की शोभायात्राओं या प्रतिमा विसर्जन के लिए चलते जन समूह पर जगह-जगह हमले क्यों बढ़ रहे हैं? दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर ही समाचार पत्रों की रिपोर्ट में ऐसी दो लगभग दो दर्जन घटनाएं आ चुकी है जहां उन पर पत्थरबाजी हुई, पत्थर बरसाए गए, कहीं रोकने की कोशिश हुई तो मार-पिटाई तो कहीं मूर्ति। अजमेर दरगाह के सरफराज चिश्ती ने भड़काऊ बयान देते हुए कह दिया कि न्यूटन की गति के नियमानुसार क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आप उकसाने वाले नारे लगाएंगे, डीजे में वैसे गाने बजाएंगे और घर पर चढ़कर झंडा उतारेंगे तो आप पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे। यह अकेला बयान नहीं है। पूरे प्रकरण का आप मूल्यांकन करें तो निष्कर्ष आएगा कि जिम्मेवार और सम्मानित स्थान पर बैठे मजहबी व्यक्तित्व और नेता ऐसे बयान दे रहे हैं उससे समुदाय के अंदर उग्रता और असहिष्णुता बढ़ने का खतरा है। दुर्भाग्य से भाजपा, नरेन्द्र मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अन्य राज्यों

की भाजपा विरोध में राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों का स्वर घोषित-अघोषित इनका समर्थन देने वाला है। हर मुठभेड़ की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर होती है और इसका भी होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के मुठभेड़ों की तुलना पिछली सरकारों से करें तो जांच रिपोर्ट और न्यायालयों के आदेश के अनुसार रिकॉर्ड बेहतर है। सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ का रिकॉर्ड अखिलेश यादव के शासन (2015) के दौरान का ही है। किंतु बहराइच हिंसा के मामले में इस पहलू को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बढ़ाकर हमला करने वाले वास्तव में मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

आखिर प्रतिमाओं के विसर्जन का रूट पहले से तय था, वीडियो बता रहे हैं कि घटनास्थल के पास गेट व झंडे लगे थे। साफ है कि यह पुलिस की अनुमति से हुआ था। हर शहर और गांव में बरसों से प्रतिमा विसर्जन के रास्ते निश्चित हैं। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। बहराइच पुलिस प्रशासन की भयानक विफलता बिल्कुल स्पष्ट है। पर्याप्त मात्रा में सतर्क पुलिस बल होता तो घटना को रोका जा सकता था। जितने विवरण सामने आए हैं उनके अनुसार डीजे बजाने को लेकर विवाद किया गया, दूसरे पक्ष ने बंद करने को कहा जबकि स्वाभाविक ही विसर्जन यात्रा के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, गाली-गलौज, धक्का-मुक्की हुई, दुर्गा प्रतिमा भी खंडित की गई तथा कुछ भगवे झंडे उतारे गए। रामगोपाल मिश्रा इसी गुस्से में कुछ साथियों के साथ उस घर की छत पर चढ़ गया जिसके कारण बाउंड्री का भाग गिरा तथा झंडा उतारने लगा। निश्चित रूप से घर पर झंडा उतारने की प्रतिक्रिया गलत है और अस्वीकार्य है। साफ है कि पुलिस का कारगर हस्तक्षेप होता तो विवाद आगे बढ़ता नहीं। समाचार पत्रों की रिपोर्ट बताती है कि अंततः पुलिस ने प्रतिमा विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठियां चलाईं जिससे लोग भागे तथा रामगोपाल अकेले फंस गया। इस दृष्टि से उसकी हत्या और साथ हुई बर्बरता का दोषी बहराइच पुलिस भी है।

दूसरी ओर यह भी देखिए, अगर परिवार के अंदर कानून-व्यवस्था का सम्मान होता तो वह कम-से-कम रामगोपाल को पुलिस के हवाले करता। इसकी जगह बेरहम पिटाई, बर्बरता हुई और फिर गोली मारी गई। यह बगैर मजहबी जुनून और नफरत के संभव ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल की मृत्यु का कारण गोली लगना है। किंतु पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. संजय शर्मा का बयान है कि उनके पैरों के अंगूठे के नाखूनों के भाग नहीं थे, आंख के ऊपर नुकीले चीजों से वार था। शरीर पर स्वाभाविक ही अलग-अलग चोट के निशान थे। यानी हत्या से पहले उसकी निर्मम पिटाई की गई। यह समझ से परे है कि आखिर किसी भी धर्मस्थल या घर के बाहर से दूसरे धर्म की यात्राओं के गुजरने, नारे लगने, गाना बजने, झूमने, नाचने का विरोध या उसके विरुद्ध हिंसा क्यों हो सकती है?

अगर हिंदू धर्मस्थलों के सामने से मुसलमान के जुलूस पर आपत्ति हो और मुसलमान के घरों और धर्मस्थलों से हिंदुओं के जुलूस पर तो इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। सच है कि हिंदुओं के क्षेत्र से गुजरने वाली मुस्लिम यात्राएं बाधित नहीं होती और न उन पर पत्थर चलते हैं, न ही हिंसा होती है। ज्यादातर हिंसा हिंदुओं की शोभायात्राओं या जुलूसों के विरुद्ध ही हो रहे हैं। यह सामान्य स्थिति नहीं है। राजनीतिक तौर पर भाजपा और संघ परिवार के विरोध में देश को मजहबी जुनून की आग में झोंकने का अपराध भविष्य में सबके लिए आत्मघाती साबित होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

> अगर हिंदू धर्मस्थलों के सामने से मुसलमान के जुलूस पर आपति हो और मुसलमान के घरों और धर्मस्थलों से हिंदुओं के जुलूस पर तो इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। सच है कि हिंदुओं के क्षेत्र से गुजरने वाली मुस्लिम यात्राएं बाधित नहीं होती और न उन पर पत्थर चलते हैं, न ही हिंसा होती है। ज्यादातर हिंसा हिंदुओं की शोभायात्राओं या जुलूसों के विरुद्ध ही हो रहे हैं। यह सामान्य स्थिति नहीं है

मच्छर-जनित बीमारियां और मलेरिया आज भी चिंता के सबब

- मलेरिया और मच्छर-जनित बीमारियों के बरक्स इंसान मजबूत तो हुआ है, लेकिन आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में ये बीमारियां चिंता का सबब बनी हुई हैं
- मलेरिया और मच्छर-जनित बीमारियों से आज भी विश्व भर में सालाना 10 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु होती है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे होते हैं
- 20 अगस्त, 1897 को रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की थी

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

एलेन मस्क की बहुत सारी बातें फालतू भी होती हैं। पर EVMs V/S Ballot Paper System पर उन्होंने जो कुछ कहा है, वह सही और सटीक है। मस्क ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, EVMs सही और सटीक नहीं हैं क्योंकि उनमें गड़बड़ी की जा सकती है।

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

क्षेत्रीय दलों के लिए सीख-संदेश

विस चुनाव | प्रो. नवल किशोर

हरियाणा एवं जम्मू-कश्मीर के चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में चर्चित लहर और भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी जनभावना के बावजूद भाजपा तीसरी दफा जनादेश हासिल करने में सफल रही है।

बेहद दिलचस्प बात है कि लोक सभा चुनाव में भाजपा अपनी गिरी साख को हरियाणा जनादेश से राहत की सांस लेने की कोशिश कर रही है वहीं कांग्रेस के बढ़े हौसलों को अप्रत्याशित आहत मिला है। हालांकि दोनों के वोट फीसद में मामूली अंतर है। वहीं जम्मू-कश्मीर की जनता ने भाजपा की तमाम चुनावी रणनीति को खारिज करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दिया है। दोनों राज्यों के चुनाव पर नजर रखने वाले धुरंधरों को चुनावी जनादेश ने चौंका दिया है। एक चीज और हुई है। दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों का लगभग सफाया हो गया है। हरियाणा में आईएनएलडी और जेजेपी का प्रदर्शन दयनीय रहा। दोनों दल महज पांच फीसद मत व तीन सीट पर सिमट गए हैं। ज्ञात हो कि दुष्यंत चौटाला ने 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर जेजेपी का गठन किया था। मात्र एक साल बाद विधानसभा चुनाव 2019 में जेजेपी का प्रदर्शन अभूतपूर्व था जब उसे 10 सीट पर जीत मिली थी। उसके समर्थन से ही भाजपा वहां पर सरकार बना पाई थी। खंडित जनादेश आने बाद सरकार गठन के दौरान जेजेपी ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया था। जनविमर्श में इस निर्णय को जनता के साथ विश्वासघात की नजर से देखा गया। जेजेपी के उभार में किसान मतदाताओं का अपार समर्थन मिला था, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान वे भाजपा के साथ रहे। यह निर्णय महंगा साबित हुआ। लोक सभा चुनाव से पूर्व ही भाजपा ने भी इनसे नाता तोड़ लिया था। राष्ट्रीय दल के बरक्स क्षेत्रीय दलों के प्रासंगिक होने के तत्व-बिंदु कुछ अलग हैं। क्षेत्रीय दलों को इस पर विचार करना अतिआवश्यक है। ज्ञात हो कि पीडीपी ओर जेजेपी दोनों ही दल वैचारिक भिन्नता के बावजूद सियासी फायदे के लिए भाजपा के साथ सरकार में रह चुके हैं। क्या इन दलों ने अपने वैचारिकी से समझौता किया। क्या अपने सियासी निर्णय से आधार वोट समूह को संतुष्ट कर पाए? क्या क्षेत्रीय दलों के लिए इस जनादेश में

कोई सीख संदेश छिपी है? ऐसे कुछ बुनियादी सवालों के नजरिए से इस जनादेश को देखना दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का 28 सीट से घटकर तीन सीट पर सिमटना और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला समेत लगभग सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त होना बेहद चौंकाने वाली घटना है। किसी भी दल और नेतृत्व के जनपसंद होने में उसकी वैचारिकी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। जेजेपी के उदय में किसानों का अपार समर्थन मिला, लेकिन किसान आंदोलन के साथ नहीं खड़ा होना घातक साबित हुआ। सभी क्षेत्रीय दलों के लिए यह विचारणीय पाठ है। यूपी में सपा/बसपा, बिहार में राजद/जदयू/लोजपा और महाराष्ट्र में शिवसेना/रांकपा जैसी पार्टियां अपनी वैचारिकी और नेतृत्व की बदौलत ही बरकरार है। बिहार में विगत दो दशक से सत्ता के बाहर रहने के बावजूद राजद अभी भी सबसे बड़े दल के रूप में जनता की पसंद बनी हुई है। वैचारिक तौर पर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास राजद की पूंजी रही है। ओबीसी के लिए मंडल आयोग की सिफारिश लागू कराने में लालू प्रसाद यादव की भूमिका निभाने से लेकर आडवाणी के रथयात्रा को सांप्रदायिक बताकर उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर क्रमशः सामाजिक न्याय और धर्मनिपेक्षता के प्रति वैचारिक स्पष्टता ही राजद को एक समय ऐतिहासिक जनस्वीकृति प्रदान किया था। उसी प्रकार दूसरी पीढ़ी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ भी नौवीं फेल और परिवारवाद का नैरेटिव ध्वस्त होता नजर आया। उनके कार्यों का जिक्र 'सत्रह महीना बनाम सत्रह साल' लोकविमर्श में आ चुका है। यह एनडीए के लिए आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। केंद्र में तीसरी बार शासन में रहने के बावजूद भाजपा बिहार की राजनीति में जद (यू) के पीछे चलने को बाध्य है।

पिछले तीन दशक से कांग्रेस अपने आधार वोट को वापस नहीं ला पा रही है। कहीं-न-कहीं वैचारिक स्पष्टता राज्य की राजनीति में मायने रखती है। यही कारण है कई क्षेत्रीय पार्टियां अपना जलवा कायम रखने में सफल रही है। राज्यों की मनोदशा को जमीनी स्तर पर समझने एवं उसकी समस्याओं का समुचित निष्पादन करने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका प्रबल होती है। क्षेत्रीय पार्टियां बुनियादी स्तर पर 'धरती पुत्र' की भावना से ओतप्रोत हुआ करती हैं। उनका दर्शन है कि जब प्रत्येक राज्य मजबूत होगा तो स्वाभाविक रूप से भारतवर्ष को मजबूती मिलेगी। ऐसे में दीवार पर लिखी इबादत स्पष्ट कह रही है कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां अपने मूल संरचना एवं वैचारिकी से समझौता न करें। यह उनके अपनी पार्टी एवं राज्य दोनों के ही हित में है। अंततः भारतवर्ष की विविधता के मद्देनजर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है।

भ्रम | ओशो

रामकृष्ण के पास एक भक्त आता था। और वह भक्त जब काली के दिन आते, तो कई बकरे कटवाता था। बड़ा समारोह मचाता था। उसकी बड़ी गणना थी भक्तों में, बड़े भक्तों में। फिर अचानक उसने

पूजा-भक्ति सब छोड़ दी, बकरे कटने बंद हो गए। तो एक दिन रामकृष्ण ने उससे पूछा कि क्या हुआ? क्या भक्ति-भाव जाता रहा? क्या अब काली में श्रद्धा न रही? उसने कहा, नहीं, यह बात नहीं। आप देखते नहीं, दांत ही सब गिर गए। वह आदमी बड़ा ईमानदार रहा होगा। बकरे वगैरह काली के लिए थोड़ी काटता था। काली तो बहाना है, तरकीब है। बकरे तो अपने ही दांतों के लिए काटे जाते हैं, लेकिन उसने कहा कि दांत ही न रहे, दांत ही गिर गए, अब क्या काटना और क्या नहीं काटना! किसके लिए काटना? लेकिन वह आदमी ईमानदार रहा होगा। उसने एक बात तो कम से कम समझी कि यह सब दांतों के लिए चल रहा था। बुढ़ापे में लोग शीलवान हो जाते हैं। बुढ़ापे में लोग सच्चरित्रता की बात करने लगते हैं। बुढ़ापे में दूसरे लोगों को समझाने लगते हैं कि जवानी सब रोग है। जब वे जवान थे, तो उनके घर के बड़े-बूढ़े भी उन्हें यही समझा रहे थे कि जवानी सब रोग है। उन्होंने उनकी नहीं सुनी। उनके बेटे भी उनकी नहीं सुनेंगे। और बड़ा मजा यह है कि जब आपने अपने बाप की नहीं सुनी, तो आप किस भ्रांति में हैं कि अपने बेटे को सोच रहे हैं, सुन ले। किसी बेटे ने कभी नहीं सुनी। क्योंकि जवानी सुनती ही नहीं। और बुढ़ापा बोले चला जाता है। बुढ़ापा समझाए चला जाता है। क्योंकि बुढ़ापा अब कुछ और कर नहीं सकता। करने के दिन गए। वह जिन तत्वों से करना निकलता था, वे क्षीण हो गए। और बड़े मजे की बात है, जब आप नहीं कर सकते, तब भी आपको यह खयाल नहीं आता कि शरीर के गुणधर्म क्षीण हो गए हैं, जिससे आप नहीं कर सकते हैं। जब आप कर सकते थे, तब आप सोचते थे, मैं कर रहा हूं। और जब आप नहीं कर सकते, तब आप सोचते हैं कि मैंने त्याग कर दिया! जब आप नहीं कर सकते, तब आप सोचते हैं, मैंने त्याग कर दिया!' वे अक्सर सोचते हैं कि वे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए हैं। अन्यथा उपाय क्या था? मजबूरी को ब्रह्मचर्य समझ लें, तो भ्रांति जारी रहती है। उचित यही होगा कि समझें कि जिन गुणधर्मों से, जिस प्रकृति के तत्व से वासना उठती थी, वे तत्व क्षीण हो गए, जल गए। जब वे जग रहे थे तत्व, सजग थे, तब आप उनका पीछा कर रहे थे।

रीडर्स मेल

टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं

चुनावी दौर में टिकट प्राप्त करने के लिए दल-बदल की समस्या बढ़ जाती है। कोई भी दल गठबंधन धर्म को पालन करने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से सीटों का बंटवारा किया गया, जो राष्ट्रीय जनता दल को रास नहीं आया है। लोक सभा चुनाव के दौरान बिहार में बिना सीटों का बंटवारा किए हुए राजद ने टिकट वितरण का कार्य शुरू कर दिया था। राजद को यह आभास होना चाहिए कि झारखंड में उसका जनाधार नहीं है। एनडीए में भी टिकट बंटवारे से जद (यू) नाराज चल रहा है। महाराष्ट्र में भी टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींच-तान जारी है। राजनीतिक दलों का यह असंतोष बगावत का रूप ले लेता है। सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन किसी भी दल में चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, इसलिए आज राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद हावी हो रहा है।

हिमांशु शेखर, गया

नई मूरत, नया संदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने 'लेडी जस्टिस' की एक नई मूर्ति का अनावरण किया है, जो दुनिया भर में कानूनी प्रथा के साथ जुड़ी प्रतीक छवि को नए रूप में प्रस्तुत करती है। परंपरागत रूप से लेडी जस्टिस को आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तराजू और दूसरे में तलवार पकड़े हुए महिला के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि, पुस्तकालय में स्थापित 6 फुट ऊंची नई मूर्ति एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करती है। इस प्रतिमा में एक साड़ी पहने हुए महिला को दिखाया गया है, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं है। वह एक हाथ में तराजू और दूसरे में परंपरागत तलवार के स्थान पर भारतीय संविधान की एक प्रति पकड़े हुए है, जबकि क्लासिक प्रतिनिधित्व में आंखों पर पट्टी को न्याय की निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता रहा है, नई मूर्ति की बाधारहित दृष्टि यह संदेश देने के लिए है कि कानून सभी को समान रूप से देखता है और सभी के लिए बाध्यकारी है। लेडी जस्टिस की इस नई कल्पना का अनावरण भारत में कई कानूनी सुधारों के बीच हुआ है, जिसमें नई आपराधिक संहिता का परिचय और देश के कानूनी ढांचे को 'उपनिवेशवाद से मुक्त' करने का घोषित उद्देश्य शामिल है।

चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

धर्म नहीं रोजगार की बात हो

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही पक्ष-विपक्ष नये-नये वादों, घोषणाओं, आरोप-प्रत्यारोप, व उपलब्धियों के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्येक चुनाव की तरह इस चुनाव में भी मुख्य रूप से स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, एवं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे होने चाहिए, न कि धर्म के जयकारे लगने चाहिए। सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए। इतने पढ़े-लिखे लिखे होने के बावजूद झारखंड के युवा बेरोजगार हैं। हद तो यह है कि दो वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपने घर-परिवार से दूर दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। अपने ही राज्य में कल-कारखाने खोल कर यहां के युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। झारखंड वैसे भी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इस चुनाव में विकास के जयकारे लगने चाहिए, न कि किसी जाति और धर्म की।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 68

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सत्यम तल, नवांग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान 1936

बीजिंग से बनती बात

चीन से लगती सीमा पर तनाव घटने के संकेत सुखद और स्वागतयोग्य हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने घोषणा की है कि भारत और चीन, दोनों के अधिकारियों के बीच हालिया बातचीत वास्तविक नियंत्रण रेखा के मामले में एक समझौते तक पहुंच गई है। यह अच्छा संकेत है, पिछले लगभग चार साल से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव व्याप्त है। सीमा पर दोनों ओर के हजारों सैनिक तैनात हैं। चीन से अगर वाकई समझौता होने जा रहा है, तो मुमकिन है कि आने वाले महीनों में सीमा पर सैन्य तैनाती में कमी आएगी। वास्तव में, चीन सीमा पर बहुत मजबूत सुरक्षा ढांचा बना चुका है और भारत ने भी अपनी ओर की संवेदनशील सीमाओं पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है, इससे अगर चीन सोचने को मजबूर हुआ है, तो आश्चर्य नहीं। हम अच्छे से जानते हैं कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए सैन्य स्तर पर बीस से भी ज्यादा वार्ताओं का आयोजन पहले हो चुका है, लेकिन चीन की हठधर्मिता की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन की मनमानी के बारे में सब जानते हैं, मगर कोई भी देश भारत और चीन के बीच आना नहीं चाहेगा, अतः हमें राजनय की मान्य सीमा में रहते हुए चीन के साथ विश्वास बहाली के प्रयास करने चाहिए। भारतीय विदेश सचिव विश्वास से भरे हुए हैं और किसी सामान्य प्रवक्ता के बजाय स्वयं उन्होंने यह घोषणा की है। एक सवाल यह भी है कि समझौते की स्थिति अचानक कैसे बनी? यहां यह गौर करने की बात है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाने वाले हैं, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात संभव है। ऐसे में, वार्ता के लिए पर्याप्त अनुकूल माहौल बनाने के एक प्रयास के रूप में विदेश सचिव की ताजा घोषणा को देखा जा सकता है। बेशक, भारत-चीन संबंधों में तल्खी घटने के आसार हैं। भारत अनेक अवसरों पर कह चुका है कि अच्छे व्यावसायिक संबंधों के लिए अच्छे राजनयिक-सामरिक संबंधों का होना जरूरी है। अगर इस दिशा में चीन वाकई गंभीर हुआ है, तो यह सबके हित में है। रूस में अगर दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात होती है, तो केवल आर्थिक मामलों पर चर्चा के बजाय सामरिक स्थिरता पर भी चर्चा होनी चाहिए। भारत या चीन के पास धन की कमी नहीं, पर लद्दाख की सीमा पर सुरक्षा बल तैनात करके प्रतिदिन होने वाला करोड़ों रुपये का खर्च विचारणीय है।

भारत और चीन, दोनों के अधिकारियों के बीच हालिया बातचीत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक समझौते तक पहुंच गई है। ब्रिक्स से पहले यह बहुत अच्छा संकेत है।

चीन से अगर संबंध सुधरते हैं, तो इसका व्यापक असर पूरे दक्षिण एशिया में देखा जाएगा। भारत जहां कश्मीर में बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगा है, वहीं आतंकवादी सीधे विकास कार्यों को निशाना बना रहे हैं। गांदरबल में सात भारतीयों की मौत हुई है। विशाल भारतीय बाजार से लाभान्वित हो रहे चीन को भारतीयों के दुख की परवाह जरूर होनी चाहिए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। स्वयं चीनी लोग पाकिस्तान में आतंकियों के निशाने पर आए हैं। चीन अच्छे से जानता है कि आतंकवाद कितना घातक है। वह स्वयं भी पूरी सख्ती से आतंक का फन कुचलने में लगा है। ऐसे में, अगर उसे भारत की चिंता हो, तो आश्चर्य नहीं। आतंकवाद के स्थायी समाधान के लिए भी भारत को चीन से जरूर बात करनी चाहिए। चीन को यह एहसास होना चाहिए कि भारत को विश्वास में लिए बिना वह ब्रिक्स को मजबूत नहीं कर सकता। उसे यह भी जरूर देखना चाहिए कि भारत के लिए आज क्वाड जैसे गठजोड़ मजबूरी क्यों बनते जा रहे हैं?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 21 अक्तूबर, 1949

पाकिस्तानी झूठ का भंडाफोड़

नई दिल्ली, २० अक्तूबर। पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है, यह उस पुस्तिका की विचित्र कहानी से मालूम पड़ता है, जो भारत के बाहर, विशेषतः अमरीका में बांटी गई है। इस पुस्तिका का नाम है- ''काश्मीर में लौह पर्दे के पीछे- एक निष्पक्ष राय।'' पुस्तिका में मुद्रक और प्रकाशक का नाम नदारद है तथा यह भी नहीं पता है कि वह कहां छपी है। इसके एक अध्याय में रावलपिंडी के ब्रिटिश रेडक्रास सोसायटी के अस्पताल के रजिस्ट्रार ले. कर्नल जे.एम.बी.सी. फ्लोडन का एक वक्तव्य है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं।

इस वक्तव्य में कहा गया है कि एक काश्मीरी मुसलमान भारतीय सेनाओं के हाथ से निकलकर रेडक्रास के अस्पताल में आया था। उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई कि गोरखा सेनाओं ने उसे सारी रात पेड़ से बांध रखा था। अगले सारे दिन उससे एक खाई खुदवाई गई, परन्तु खाना और पानी तक उसे नहीं दिया गया। बाद में उसे एक सिख ले. कर्नल के सामने पेश किया गया। फिर पाकिस्तानी नाले के पास ले जाकर २० गोरखों ने उसे पीटा और खुखरियों से मारा। बाद में उसे एक खाई में फेंक दिया और पत्थरों से ढक दिया, लेकिन बाद में उसे चेतना आई और वह बचकर पाकिस्तान आ गया।

इस पुस्तिका का पता पाकर भारत की रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन ने लन्दन में ब्रिटिश रेडक्रास सोसायटी से पूछताछ की, जिसके उत्तर में ब्रिटिश रेडक्रास सोसायटी ने लिखा कि इसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं, न ही इसका हमारे यहां कोई रिकार्ड है। इस मनगढ़त कहानी का भंडाफोड़ एक और घटना से भी होता है। जनरल करिअप्पा जब एक बार रावलपिंडी गये हुए थे, तब उनसे भारतीय सैनिकों के अत्याचारों से पीड़ित एक व्यक्ति की शिकायतें कही गईं। करिअप्पा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अस्पताल के उस बीमार से मिलना चाहा। लेकिन कुछ उच्चाधिकारियों ने जनरल करिअप्पा को जो कहानी सुनाई थी, उसे दुहराने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, तब जनरल करिअप्पा ने समझ लिया कि यह केवल भारतीय सेना को बदनाम करने के लिये कहानी गढ़ी गई है। इस पुस्तिका से स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार की कोई सीमा नहीं है।

सुरक्षा के मोर्चे पर सचेत करती साजिशें

यहां स्कैन करें

अजय साहनी | आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ

आतंकी घटनाओं के लिहाज से जो सबसे बुरा दौर था, जिसमें 1,500 से अधिक नागरिक मारे जाते थे, वह बीत चुका है। अब चिंतित होने की नहीं, तैयार रहने की जरूरत है।

कहा जा रहा है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद दूसरी चुनौतियों से जूझ रही हैं। जम्मू-कश्मीर में मजदूरों के शिविर पर आतंकी हमला करते हैं, तो दिल्ली में एक स्कूल की दीवार के पास आईईडी विस्फोट होता है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला तो मानो थम ही नहीं रहा, अलबत्ता विदेशी जमीन पर बैठा एक खालिस्तानी आतंकी भारतीयों को 1 से 19 नवंबर के बीच एअर इंडिया के विमान से यात्रा न करने की चेतावनी जारी करता है।

ऊपरी तौर पर इसे देखकर कोई भी खौफजदा हो सकता है, लेकिन व्यापकता में यदि विश्लेषण करें, तो हमें राहत का ही अनुभव होगा। गांदरबल घटना को जोड़ लें, तब भी इस साल जम्मू-कश्मीर की 48 घटनाओं में कुल 102 लोगों की जान गई है। इनमें से 52 आतंकी हैं। जबकि, पिछले साल ऐसी 72 वारदातों में 87 आतंकियों को मार गिराया गया था। बेशक, आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या बढ़ी है और पिछले साल के 12 के मुकाबले इस वर्ष 26 नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन साल 2022 में 30, तो 2021 में 36 लोगों की जान गई थी। बाहरी मजदूरों पर हमले की भी यह कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। लिहाजा, समग्रता में ये आंकड़े घटते ही दिख रहे हैं।

कुछ ऐसी ही बात दिल्ली-धमाके को लेकर कही जा सकती है। 7 सितंबर, 2011 के बाद राष्ट्रीय राजधानी में यह पहला विस्फोट है। दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर हुए उस धमाके में 15 लोग मारे गए थे और 75 से अधिक घायल हुए थे। जबकि, रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-14 में जो धमाका हुआ, उसमें आसपास की कुछ इमारतों के शीशे चटक गए, जबकि सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यह कम तीव्रता का धमाका था और जांच एजेंसियां तत्काल अपने काम में जुट गईं। भले ही हमें अभी तक यह नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, लेकिन यह जरूर पता है कि दिल्ली को दहलाने के प्रयास अनवरत जारी हैं। शक के दायरे में सभी हैं- फिर चाहे वह जम्मू-कश्मीर के अतिवादी हों या खालिस्तानी गुट या फिर कुछ गैंगस्टर या इस्लामिक स्टेट या अल-कायदा समर्थित स्थानीय समूह या फिर पीएफआई से जुड़े लोग। सोशल मीडिया पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे के साथ इस घटना की जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन इस दावे की पुष्टि अभी बाकी है। जांच के नतीजे पर पहुंचते ही हमें गुनहगार का पता चल जाएगा, तब तक किसी तरह की कयासबाजी से बचना ही उचित होगा।

वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा के मोर्चे पर हमें काफी सफलता मिली है। साल 2001 में पूरे देश में 2,802 आतंकी घटनाओं में 5,504 लोगों की जान गई थी। इसमें जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, माओवादी, इस्लामी आतंकवाद आदि सभी चुनौतियां शामिल हैं। इन लोगों में 1,508 आम नागरिक शामिल थे, तो 883 सुरक्षा बलों के जवान। आतंकियों की संख्या 3,005 थी। पिछले साल ऐसी घटनाओं की संख्या गिरकर 278 रह गई, जिनमें कुल 150 आम नागरिक सहित 467 लोग मारे गए। 82 सुरक्षा बल के लोग भी मारे गए, जबकि 229 आतंकियों को ढेर किया गया। हां, साल 2024 में अब तक जरूर 499 लोग आतंकी घटनाओं में मारे गए हैं, इनमें नागरिकों की संख्या 123 है। जाहिर है, किसी साल आंकड़ों में ऊपर-नीचे हो सकता है, पर इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। आतंकी घटनाओं के लिहाज से जो सबसे खराब दौर था, जिसमें 1,500 से अधिक आम नागरिक मारे जाते थे, वह बीत चुका है। अब यह आंकड़ा घटकर 150 तक सिमट गया है। पिछले पांच साल में तो जम्मू-कश्मीर के बाहर इस्लामिक आतंकवाद की घटनाओं में तीन साल ऐसे हैं, जिसमें किसी आम नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं आई। 2020 में एक और 2022 में तीन आम नागरिक ऐसी वारदातों में मारे गए थे।

पिछले 25 वर्षों की यह उपलब्धि है। कमी आतंकी घटनाओं में ही नहीं हुई है, आतंकी संगठनों से चुनौतियां भी अब तुलनात्मक रूप से कम मिलती हैं। सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्रों ने बड़ी-बड़ी तंजीमों को करीब-करीब खत्म कर दिया है, जिसके कारण दहशत की बड़ी घटनाएं अब इतिहास बनने लगी हैं। असल में, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए विशेष तैयारी की जरूरत होती है और अब जिस तरह की हमारी सुरक्षा व्यवस्था होने लगी है, उसमें आतंकियों के लिए देश के भीतर बड़ी तैयारियां करना काफी मुश्किल है। हां, सीमा पार से वे जरूर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी झलक हम जम्मू-कश्मीर या अन्य सीमावर्ती इलाकों में देखते भी रहते हैं।

रही बात छोटी-मोटी घटनाओं की, तो वे सामने आ सकती हैं। उनको रोकना सुरक्षा बलों के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी एक-दो सिरफिरा किसी 'सॉफ्ट टारगेट' को निशाना बना सकता है। रविवार को दिल्ली में हुआ धमाका भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। मुमकिन है, ऐसा सनसनी पैदा करने के लिए किया गया हो। चूंकि बड़े संसाधन जुटाने के लिए बड़े आतंकी संगठनों के नेटवर्क का अब अभाव है, इसलिए छोटी-मोटी कार्रवाइयां करके आतंकी अपनी प्रासंगिकता बनाने के कुत्सित प्रयास करते रहते हैं।

आज सुरक्षा चुनौतियों से हम पार पाने लगे हैं, तो इसका श्रेय सुरक्षा बलों को देना चाहिए। उनकी लक्षित कार्रवाइयों से हमें काफी लाभ मिला है। पिछले दो दशकों में उनको अपनी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है, उनकी संख्या और क्षमता, दोनों बढ़ाई गई है, इन सबका लाभ हमें मिला है। किसी नीतिगत बदलाव को इसका श्रेय नहीं देना चाहिए। पहले की सरकारें भी ये सब करती रही हैं। हां, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 के हटने के बाद आतंकी घटनाओं में एक उछाल दिखा था, लेकिन लगता है कि सुरक्षा बलों ने उसे भी अब नख-दंत विहिन कर दिया है।

पाकिस्तान की बढ़ती अपनी उलझनें भी इसका कुछ हद तक कारण हैं। दरअसल, उसने सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से उसे काफी लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, उल्टे तालिबानी शासन से उसे परेशानी ही होने लगी है। फिर, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में, जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को शह देने का पुराना खेल फिलहाल कुछ देर तक उसी स्तर पर नहीं खेला जा सकता। कुल मिलाकर, सुरक्षा चुनौतियों के मोर्चे पर हमने मुश्किल दौर को पार कर लिया है। आज भी चुनौतियां हैं, मगर वे ऐसी नहीं हैं कि आम नागरिकों को खौफ खाना चाहिए। हमारे सुरक्षा बल ऐसी तमाम चुनौतियों से निपटने में काफी हद तक सक्षम हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

केरल उपचुनाव में भी कसर नहीं छोड़ना चाहती भाजपा

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस शायद खुद को बार-बार जीत के जबड़े से हार छीन लाने वाली पार्टी साबित करने में लगी है। हर किसी ने एक साल पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में और हाल में हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार में ऐसा होते देखा है।

हाल के लोकसभा चुनावों में केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे- यूडीएफ ने चुनावों में जीत हासिल की थी और कुल 20 में से 18 सीटें जीती थीं, जबकि क्रमशः वाम मोर्चा और भाजपा को एक-एक सीट मिली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूडीएफ 19 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इस लिहाज से केरल वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत गढ़ साबित हुआ है, तो क्या मान लिया जाए कि आगामी उप-चुनावों में भी कांग्रेस वहां बेहतर प्रदर्शन जारी रखने वाली है? इसके अलावा एक पहलू यह भी है कि लगातार दो बार सत्ता में रहने वाली पी विजयन सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है।

नवंबर में राज्य में एक लोकसभा और दो विधानसभा उपचुनाव होने हैं। वायनाड लोकसभा सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है, जिन्होंने अपनी रायबरेली सीट बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने वायनाड के प्रति आभार व्यक्त करने के प्रयास के तहत अपनी बहन प्रियंका को सीट देने का फैसला किया है।

केरल में फिर त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला है, सत्तारूढ़ वाम मोर्चा को कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से फिर मिल रही तगड़ी टक्कर।

दो विधानसभा सीटें- पलक्कड़ व चेल्लाकारा, कांग्रेस के शफी परंबिल और सीपीएम के राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। ये दोनों लोकसभा के लिए चुने गए हैं। पलक्कड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है और चेल्लाकारा, एक आरक्षित सीट, 1996 से सीपीएम के पास है। कांग्रेस को पलक्कड़ बरकरार रखने और चेल्लाकारा को वाम दलों से छीनने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ सकता है।

असली लड़ाई पलक्कड़ में ही है। यह सीट 2021 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के शफी परंबिल के लिए चुनौती थी। वह मेट्रो-मैन ई श्रीधरन से महज 3,859 वोटों से जीते थे। श्रीधरन को भाजपा ने बड़ी उम्मीद के साथ मैदान में उतारा था और उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि भाजपा उन निर्वाचन क्षेत्र में अपना समर्थन आधार बढ़ाती दिख रही है, जहां वाम दल तीसरे स्थान पर रहे हैं।

शफी की सिफारिश पर पलक्कड़ सीट राज्य के युवा कांग्रेस प्रमुख राहुल ममकुताथिल को दी गई। झटका तब लगा, जब कांग्रेस के डिजिटल सेल के प्रमुख पी सरीन ने बगावत करके पार्टी छोड़ दी। उन्होंने ममकुताथिल के नामांकन का विरोध किया और चेतावनी दी कि कांग्रेस को केरल में वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जैसी स्थिति से वह हरियाणा में गुजरी है। दिलचस्प है, मुश्किल में फंसी सीपीएम ने पलक्कड़ में सरीन की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे कांग्रेस हैरान व क्रोधित है। सरीन क्षेत्र में काफी मशहूर हैं और वामपंथियों को लगता है कि उनकी उम्मीदवारी से वाम पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस को यहां वोट कटने की आशंका सता रही है।

भाजपा के लिए यहां बड़ी लड़ाई है, क्योंकि फिलहाल विधानसभा में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है। 2016 में भाजपा के ओ राजगोपाल ने नेमोम विधानसभा सीट जीती, लेकिन 2021 में हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अभिनेता सुरेश गोपी की थिरुसूर में जीत के साथ अपना खाता खोला। वह अब केंद्रीय मंत्री हैं। चिंतित कांग्रेस सत्तारूढ़ वाम मोर्चा से अपील कर रही है कि वह उसके खिलाफ उम्मीदवार न उतारे। राज्य कांग्रेस प्रमुख वी एम सुधीरन ने कहा है कि वाम मोर्चा- एलडीएफ को भाजपा के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रियंका के खिलाफ अपना उम्मीदवार वापस ले लेना चाहिए। प्रियंका 23 अक्तूबर को नामांकन दाखिल करने वाली हैं।

वैसे भाजपा केरल में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। भाजपा ने कोझिकोड निगम में पार्षद और मैकेनिकल इंजीनियर नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। भाजपा की भी परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि पार्टी के तीन शीर्ष नेता- राज्य पार्टी प्रमुख सुरेंद्रन, उपाध्यक्ष शोभा सुरेंद्रन और महासचिव सी कृष्णकुमार पलक्कड़ सीट से टिकट के लिए होड़ कर रहे हैं। फिर भी, कुल मिलाकर भाजपा की तुलना में कांग्रेस की राह में ज्यादा रोड़े हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

कैसे हो ध्यान का आरंभ

ध्यान क्या है? एकाग्रचित्त होना ध्यान नहीं है, क्योंकि जहां रुचि होती है, वहां किसी वस्तु पर एकाग्रचित्त होना सरल होता है। युद्ध और नरसंहार की योजना बनाने वाला सेनापति बड़ा एकाग्रचित्त होता है। पैसा कमाने वाला व्यापारी बड़ा एकाग्रचित्त होता है। वह कठोर भी हो सकता, क्योंकि वह दूसरी प्रत्येक भावना को एक ओर करके जो चाहता है, उस पर पूर्णतया एकाग्रचित्त होता है। ऐसी एकाग्रता ध्यान नहीं है। वह केवल बहिष्करण है।

फिर ध्यान क्या है? निस्संदेह, ध्यान समझ है- हृदय का ध्यान समझ है। यदि बहिष्करण होगा, तो समझ कैसे हो सकती है? जहां निवेदन है, अनुनय है, वहां समझ कैसे हो सकती है? बोध में, सम में शांति होती है, स्वतंत्रता होती है; जिसे आप समझ लेते हैं, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। केवल एकाग्रचित्त होना या प्रार्थना करना समझ नहीं लाता। समझ ध्यान का आधार है, ध्यान की मूलभूत प्रक्रिया है। यदि आप प्रार्थना और एकाग्रता का सावधानी से परीक्षण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ भी समझ नहीं ला सकता। इनका परिणाम केवल दुराग्रह, दृढ़ता और भ्रम है, जबकि ध्यान में, जिसमें बोध होता है, स्वतंत्रता, स्पष्टता और समग्रता आती है।

अब बोध का, समझ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, सभी वस्तुओं को उचित अर्थवत्ता, उचित मूल्य प्रदान करना। अज्ञानी होने का अर्थ है गलत मूल्य प्रदान करना, मूर्खता का स्वभाव ही है कि वह उचित मूल्यों को नहीं समझती। बोध तभी होता है, जब उचित मूल्यों की स्थापना होती है। तो उचित मूल्यों को स्थापित कैसे किया जाए- संपत्ति के उचित मूल्य को, संबंध के उचित मूल्य को, धारणाओं के उचित मूल्य को? उचित मूल्य स्थापित हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि आप विचारकर्ता को समझें। यदि मैं विचारकर्ता को नहीं समझता, जो मैं स्वयं हूं, तो मेरे चुनाव का, मेरे वरण का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात यदि मैं अपने आप को नहीं जानता, तो मेरे कर्म का, मेरे विचार का कोई भी आधार नहीं है। अतः स्वबोध ध्यान का आरंभ है। यह वह बोध नहीं, जिसे आप पुस्तकों से, अधिकारी व्यक्तियों से और गुरुओं से प्राप्त करते हैं, बल्कि यह वह समझ है, जो आत्म-अन्वेषण से आती है। यह आत्म-सजगता है।

युद्ध और नरसंहार की योजना बनाने वाला सेनापति भी बड़ा एकाग्रचित्त होता है। पैसा कमाने वाला व्यापारी भी बड़ा एकाग्रचित्त होता है। मगर ऐसी एकाग्रता ध्यान नहीं है।

स्वबोध के बिना ध्यान संभव नहीं है। यदि मैं अपने विचारों, अपनी भावनाओं के तौर-तरीकों को नहीं समझता, यदि मैं अपने अभिप्रायों, अपनी आकांक्षाओं, अपनी मांगों, कर्म के विभिन्न प्रारूपों के अपने अनुशीलन, यानी धारणाओं को नहीं समझता; यदि मैं स्वयं को नहीं जानता, तो चिंतन के लिए कोई आधार नहीं होता। खुद को समझे बिना जो विचारकर्ता केवल मांगता है, प्रार्थना करता है, बहिष्करण करता है, उसके हाथ दुविधा या भ्रांति ही लगने वाली है।

जे कृष्णमूर्ति

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 'आजाद हिंद सरकार' का गठन स्वतंत्रता का एक ऐसा प्रतीक भी था, जिसने देश के युवाओं सहित लाखों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता के प्रति असीम ऊर्जा भरने का काम किया।

दूरदर्शी सोच दिखा रहे चंद्रबाबू नायडू

कहने वाले कह सकते हैं कि यह कैसा विरोधाभास है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र की सत्ता में उस धुर दक्षिणपंथी पार्टी के साथ हैं, जिसके नेता पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि भारत की जनसंख्या-वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीतियां जल्द से जल्द कानूनी तरीके से लागू की जाएं। सत्तारूढ़ दल के लोग तो खुलेआम ऐसी जनसंख्या नीति की वकालत करते रहे हैं, जिसमें दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान हो। यानी, ऐसी नीतियों के पालनकर्ताओं को प्रोत्साहित और न पालन करने वालों को दंडित करने का प्रावधान तय करने की मांग लगातार होती रही है। मगर चंद्रबाबू नायडू ठीक इसके विपरीत जाते हुए अपने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की नहीं, बल्कि आबादी बढ़ाने की नीति लाने की वकालत कर रहे हैं। वह ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को प्रोत्साहित और कम बच्चे पैदा करने वाले को दंडित करने का मन बना रहे हैं।

नायडू का मानना है कि राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवारों को कम से कम दो या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आने वाले समय में जिनके दो या उससे ज्यादा बच्चे होंगे, वही स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। उनका यही मानना है कि आंध्र प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, जहां गांवों में अब सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर लगातार गिरती जा रही है। देश में औसत प्रजनन दर जहां 2.1 है, वहीं दक्षिण के राज्यों में यह आंकड़ा गिरकर 1.6 तक पहुंच गया है।

सवाल है कि क्या सच में भारत बूढ़ा हो रहा है? ऐसा इसलिए, क्योंकि युवा आबादी लगातार घट रही है। केंद्र की यूथ इन इंडिया-2022 की रिपोर्ट बताती है कि 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47 फीसदी से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ नौजवान 15 से 25 साल के बीच के हैं। साफ है, अगले 15 साल में यह आंकड़ा तेजी से गिरेगा। कम से कम इस मामले में चंद्रबाबू नायडू एक समझदार और दूरदर्शी नेता मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि हम सबको चीन से सबक लेना चाहिए, जो अपने 80 के दशक के घातक जनसंख्या-नियंत्रण कानून की वजह से आज खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया है और जनसंख्या बढ़ाने के उपायों पर विचार करने लगा है। वहां युवा अब बात मान भी नहीं रहे।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

जनसंख्या-नीति

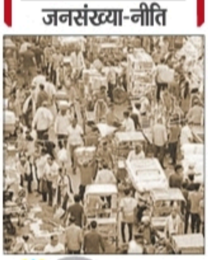

आबादी बढ़ाने की यह नीति गलत

भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश है। माना जाता है कि अत्यधिक आबादी के कारण ही यहां के संसाधनों पर दबाव काफी ज्यादा है, जिसके कारण सरकारें जनसंख्या वृद्धि दर को थामने की बढ़-चढ़कर वकालत करती रही हैं। कहा यही जाता है कि जनसंख्या-वृद्धि दर जब तक सीमित नहीं होगी, लोगों को पर्याप्त सुख-सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। मगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इससे अलग नीति बनाने की बात कही है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है और इस बाबत एक नई योजना लाने की बात कही है। दरअसल, चंद्रबाबू नायडू राज्य में कम बच्चों के पैदा होने को लेकर तनाव में हैं। ऐसे में, आंध्र सरकार जनसंख्या प्रबंधन की योजना बना रही है, जिसके तहत ज्यादा बच्चे वाले माता-पिता को प्रशासन की ओर से अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। यह बयान तब दिया गया है, जब दावा किया जाता है कि भारत में कोई योजना यदि ढंग से लागू नहीं हो पाती, तो इसका सबसे बड़ा कारण यहां की विशाल जनसंख्या है। यूरोप और अमेरिका से तुलना करें, तो क्षेत्रफल के अनुपात में हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। साफ है, हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम अधिक बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने लगे हैं। नायडू के मुताबिक, उनके यहां के युवा विदेश चले गए या दूसरे राज्यों में चले गए हैं, जिसके कारण राज्य के मानव संसाधन में कमी आई है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया है कि जो नए बच्चे पैदा होंगे, वे भी क्या राज्य से बाहर चले नहीं जाएंगे? अगर राज्य उनको रोजगार नहीं दे पाएगा, तो पलायन होगा ही। बिहार इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जिसे 'लेबर सप्लाई स्टेट' भी कहा जाता है। इसलिए, अधिक बच्चे पैदा करने के स्थान पर व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।

महेंद्र सिंह तारातरा, टिप्पणीकार

उपलब्धियों पर फिरेगा पानी

चंद्रबाबू नायडू के बाद अब स्टालिन ने भी तमिल दंपतियों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने इसका कारण भी दिया है। उनके मुताबिक, तमिलों की आबादी कम हो रही है, इसलिए उनकी लोकसभा में सीटें कम हो जाएंगी। उनका भय जायज है। परिसीमन से संसद में संतुलन बिगड़ने का खतरा है। उत्तर भारत हावी हो जाएगा, क्योंकि उसने आबादी नियंत्रण कार्यक्रमों को ठीक से लागू नहीं किया और जमकर आबादी बढ़ाई है। अगर अब भी इस भय को फैलने से नहीं रोका गया, तो आबादी नियंत्रण की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा।

डॉ मुकेश कुमार, टिप्पणीकार

पायनियर
नई दिल्ली, मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2024

बांग्लादेश की स्थिति

राजनीतिक उथलपुथल

बांग्लादेश में राजनीतिक उथलपुथल जारी है। ऐसे में 2025 में आम चुनाव से स्थिति सुधर सकती है। लंबी प्रतीक्षा के बाद बांग्लादेश में 2025 में आम चुनाव की संभावना बन रही है। बांग्लादेश के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा था कि चुनाव-पूर्व तैयारियां पूरी करने के बाद अगले चुनाव 2025 में होंगे जिनमें नए निर्वाचन आयोग का गठन भी शामिल है। बांग्लादेश में गहराते बहुआयामी संकट के साथ ही नए आम चुनाव के लिए दबाव बढ़ रहा है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होकर देश में स्थायित्व आए। 2025 में आम चुनाव की संभावना राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का केन्द्र बिंदु बन गई है। बहुत से लोग चुनाव को ऐसी वैध सरकार बनाने का आवश्यक कदम मानते हैं जो देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करे, कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करे तथा बांग्लादेश को ज्यादा स्थाई भविष्य की ओर ले जाए। लेकिन चुनाव के पहले अनेक बाधायें दूर करनी बाकी हैं। वर्तमान समय में व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही अंतरिम सरकार को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए उपयुक्त माहौल बनाना होगा। इसके लिए चुनावी धोखाधड़ी से निपटने, मतदाताओं और उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा चुनाव आयोग में सुधार जरूरी हैं क्योंकि पिछले वर्षों में 'पक्षपात' के कारण इसकी आलोचना हुई है। खासकर

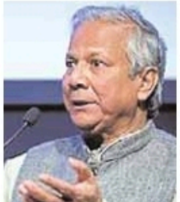

अमेरिका और यूरोपीय संघ से पड़ने वाला अंतरराष्ट्रीय दबाव बांग्लादेश में पारदर्शी व विश्वसनीय चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। राजनीतिक समूहों के बीच संवाद विकसित करने तथा चुनाव सुधारों पर निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहभागिता बहुत जरूरी है। हालांकि, 2025 में संभावित आम चुनाव आशा की किरण हैं, पर ये संपूर्ण समाधान की गारंटी नहीं हैं। स्थायित्व के रास्ते के लिए जटिल व संवेदनशील कदम जरूरी होंगे जनमें प्रभावी सत्ता-साझा व्यवस्थायें, अतीत की राजनीतिक गलतियों के लिए जवाबदेही तथा ऐसी आर्थिक नीतियां शामिल हैं जिनसे नागरिकों का वित्तीय बोझ कम हो सके। लोकरंजक लफ्फाजी तथा अतिवादी समूहों का उभार भी शांतिपूर्ण चुनावी परिवेश के लिए खतरा है। इसके साथ ही शेख हसीना निर्वासित हैं और उनकी अवामी लीग पार्टी का काफी बड़ा हिस्सा अराजकता का शिकार हो गया है। इसे देखते हुए बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य का बड़ा हिस्सा चुनाव प्रक्रिया से बाहर रह सकता है। शेख हसीना के नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है। लेकिन उनके कार्यकाल में तानाशाही, विरोधियों को कुचलने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदलाव के आरोप भी लगे हैं। लोकतांत्रिक मानकों में गिरावट तथा बांग्लादेश नेशनललिस्ट पार्टी-बीएनपी समेत विपक्षी दलों पर कठोर कार्रवाई के कारण बांग्लादेश अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा अशांति का शिकार है। राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके बांग्लादेश में 2025 में आम चुनाव कराने की संभावना आशंकाओं और उम्मीदों से भरी है। राष्ट्र का भविष्य मोटेतौर से अंतरिम सरकार की क्षमता और प्रबंधन पर निर्भर है। देखना होगा कि अंतरिम सरकार राजनीतिक हस्तांतरण का प्रबंधन कहां तक सटीक रूप से कर सकती है। इसके साथ ही यह सवाल भी बार-बार उठ रहा है कि क्या अंतरिम सरकार वास्तव में सच्ची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता खोलना चाहती है या नहीं। आने वाले महीने यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या बांग्लादेश वर्तमान उथलपुथल वाली स्थिति से उबर सकेगा और उसमें लोकतांत्रिक भावना पुन: पैदा होगी अथवा वह अराजकता और अस्थायित्व में घिरा रहेगा।

कनाडा में भारतीयों पर संकट

भारत और कनाडा के बीच पैदा राजनयिक संकट के कारण कनाडा में वीज़ा प्रक्रियायें, आप्रवास के मार्ग तथा भारतीय कामगारों व छात्रों के लिए अवसर बाधित हुए हैं।

के.एस. तोमर
(लेखक, रणनीति विशेषज्ञ हैं)

भारत और कनाडा के बीच वर्तमान राजनयिक तनावों के कारण वहां काम कर रहे या अध्ययनरत भारतीय नागरिकों अथवा कनाडा जाने की इच्छा रखने वालों पर संकट मंडरा रहा है। खासकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए आरोपों तथा दोनों देशों द्वारा राजनयिकों के निष्कासन से स्थिति और गंभीर हुई है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी सरकार का समर्थन घट रहा है और उनकी अल्पमत सरकार प्रमुख सिख राजनेता जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी-एनडीपी के समर्थन पर निर्भर हो गई है। एनडीपी के समर्थन आधार में कनाडा की सिख जनसंख्या का बड़ा हिस्सा शामिल है और ट्रूडो उसका समर्थन पाने के प्रयास में भारत के खिलाफ कठोर दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हालांकि, कनाडा में रहने वाले कुछ सिखों के विचार ये यह उनके हितों के खिलाफ है। भारत और कनाडा के बीच खराब होते संबंध अनेक प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कनाडा में कार्यरत भारतीय कामगारों पर प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

कनाडा के कुशल कामगारों में खासकर आईटी, स्वास्थ्यरक्षा, इंजीनियरिंग व फाइनेंस क्षेत्रों में भारतीयों का बड़ा हिस्सा है। अनेक वर्षों से कनाडा भारतीय पेशेवरों के लिए प्रमुख ठिकाना बना हुआ है जिसका कारण वहां की आप्रवास-हितैषी नीतियां हैं। हालांकि, कनाडा में कार्यरत भारतीय कामगारों पर तत्काल प्रभाव सीमित है, पर लंबे राजनयिक गतिरोध के कारण वर्क परमिटों, वीज़ा नवीनीकरण और स्थाई आवास-पीआर प्रार्थनाओं में विलंब हो सकता है। इनको निपटाने में लगने वाला समय बढ़ सकता है तथा कठोर जांच व्यवस्थायें लागू हो सकती हैं। ऐसे में भावी आप्रवासियों के लिए अनिश्चितता का माहौल है। संभावित आप्रवासियों या वर्क परमिटों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वीज़ा स्वीकृति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि संबंध लगातार खराब होते रहे तो कनाडा भारतीय कामगारों के लिए ज्यादा कठोर आप्रवास नियम लागू कर सकता है जिससे उस देश में पेशेवरों का प्रवाह बाधित हो सकता है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हैं क्योंकि यह भारतीय छात्रों के लिए प्रमुख गंतव्य स्थल बन गया है। 2023 में कनाडाई विश्वविद्यालयों में लगभग 3,20,000 छात्र पढ़ रहे थे। देश की विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था, परास्नातक के बाद तुलनात्मक रूप से सरल आप्रवास के मार्ग तथा काम के विविधतापूर्ण क्षेत्रों के कारण कनाडा भारतीय छात्रों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। वर्तमान राजनयिक तनाव के कारण छात्र वीज़ा स्वीकृतियों में विलंब हो सकता है अथवा प्रार्थनापत्रों की ज्यादा कठोर जांच हो सकती है। हालांकि, फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि भारतीय छात्रों को फौरन अस्वीकार कर दिया जाएगा, लेकिन खासकर नए प्रार्थियों के लिए अनिश्चितता से प्रवेश प्रक्रियाओं में दबाव तथा विलंब बढ़ सकता है। अनेक भारतीय छात्र कनाडा में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद 'पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिटों'- पीजीडब्लूपी के कारण रुके रहते हैं तथा अंतत: स्थाई आवास की प्रार्थना करते हैं। अब यह प्रक्रिया पूरी करने में तनाव बढ़ सकता है। इससे छात्रों को सहज ढंग से शिक्षा से रोजगार में जाने का रास्ता ज्यादा कठिन हो सकता है। वर्तमान स्थितियों से आप्रवास के तरीके भी प्रभावित हो सकते हैं। कनाडा का 'एक्सप्रेस इंट्री प्रोग्राम' भारतीय पेशेवरों तथा स्थाई आवास की मांग करने वाले छात्रों के लिए अत्यधिक लाभदायक रहा है। लेकिन यदि राजनयिक खाई बढ़ती है तो यह प्रक्रिया धीमी या ज्यादा कठोर हो सकती है। प्रार्थनापत्रों को निपटाने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, पृष्ठभूमि की ज्यादा कठोर जांच हो सकती है तथा संभावित नीतिगत परिवर्तनों से भी भारतीय प्रार्थी प्रभवित हो सकते हैं।

अनेक भारतीय नागरिकों के परिवारी सदस्य कनाडा में रहते हैं और उन्होंने परिवार एकीकरण या स्पांसरशिप कार्यक्रम की प्रक्रिया अपनाई है। राजनयिक गतिरोध के कारण उनकी प्रार्थनाओं पर विचार में विलंब हो सकता है। इसके साथ ही व्यापार एवं द्विपक्षीय समझौते तथा पेशेवर लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो सकता है। यदि राजनयिक तनाव जारी रहा तो ऐसे पेशेवर लेनदेन, संयुक्त उद्यम तथा कार्पोरेट साझेदारी में विलंब हो सकता है जिसमें भारतीय और कनाडाई कंपनियां शामिल हों। इससे आईटी, दूरसंचार व कंसल्टेंसी जैसी कनाडाई कंपनियों में भारतीय पेशेवरों के रोजगार अवसर घट सकते हैं। वर्तमान गतिरोध से आप्रवास के तरीके भी प्रभावित होंगे। भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौत-सीईपीए पर बातचीत चल रही थी जो अब ठंडे बस्ते में जा सकती है। इससे भारतीय पेशेवरों के आप्रवास को सुगम बनाने वाली पहलें प्रभावित हो सकती हैं तथा सहज व्यापार और रोजगार संबंधों के रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। इन सभी आयामों को देखते हुए राजनयिक गतिरोध दूर करने के रास्ते खोजे जाने चाहिए। इसका सर्वाधिक प्रभावी तरीका राजनयिक संवाद विकसित करना है। दोनों देशों की सरकारों को समान आधार तलाश कर तनाव घटाने पर काम करना चाहिए। राजनयिक चैनलों को दोनों पक्षों के नागरिकों के हितों को संरक्षण देते हुए गलतफहमी दूर करने के प्रयास करने चाहिए। स्थितियों को सुधरने की प्रतीक्षा करते हुए छात्रों और पेशेवरों को वैकल्पिक देशों, जैसे ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया या जर्मनी जाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि वे भी भारतीय नागरिकों के लिए शिक्षा के ऐसे ही अवसर तथा काम के अवसर प्रदान करते हैं। इस गतिरोध का कारण कनाडा में सिख समुदाय की भूमिका तथा वोटबैंक की राजनीति है। भारत के बाहर कनाडा में सिखों की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहां लगभग 770,000 सिख हैं जो कनाडाई जनसंख्या का लगभग 2 प्रतिशत हैं। इनमें से अधिकांश सिख ब्रिटिश कोलम्बिया, ओंटारियो और अल्बर्टिया के चुनाव जिलों में हैं। कुछ चुनाव क्षेत्रों में सिख महत्वपूर्ण मतदाता समूह हैं जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। कनाडा में 2025 में चुनाव होने हैं जिनके चलते ट्रूडो को सभी प्रमुख समुदायों में अपना समर्थन आधार मजबूत करने की जरूरत है। वर्तमान सरकार के अल्पसंख्यक दर्जे को देखते हुए उनको गठबंधनों, जैसे एनडीपी के साथ गठबंधन पर जोर देना होगा। इसके साथ ही उनको समृद्ध आप्रवासी मतदाताओं में अपना आधार मजबूत करना होगा। इनमें सिखों का प्रभुत्व है।

जस्टिन ट्रूडो के वर्तमान राजनयिक कार्य इन समूहों के महत्वपूर्ण मुद्दों से स्वयं को जोड़ने तथा अपना समर्थन आधार बढ़ाने पर केन्द्रित हैं। ऐतिहासिक रूप से सिख समुदाय खासकर ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी का समर्थन करता रहा है। उनकी कैबिनेट में अनेक लोग तथा हाईप्रोफाइल सिख नेता इसी समुदाय से आते हैं। इस प्रकार अगले चुनाव में सिखों का समर्थन प्राप्त करना लिबरल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, कनाडा में रहने वाले सभी सिख खालिस्तान आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, पर प्रभावशाली पैरोकारी समूह बनाने वाले लोगों ने कनाडा की राजनीति में इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। ट्रूडो का कामकाज मतदाताओं के इस हिस्से को प्रभावित करना है जिसे अपना वोटबैंक मजबूत करने के प्रयास की तरह देखा जा रहा है। भावी चुनाव के कारण उनकी सरकार पर भारी दबाव है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रूडो की रणनीति स्वयं को कनाडाई संप्रभुता के रक्षक की तरह पेश करने की है। इस कदम से वे मतदाताओं में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा वरीयता पर लाना चाहते हैं। यह पश्चिमी देशों द्वारा घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे को महत्व देने के भी अनुरूप है, हालांकि भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों के बाद भारत-कनाडा संबंध बहुत खराब हो गए हैं कि भारतीय एजेंट कनाडा की धरती पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। उनके अतिवादी राजनयिक कदम से दोनों देशों के संबंध बहुत खराब हो गए हैं। इसे वोटबैंक राजनीति तथा आगामी चुनावों को देखते हुए ट्रूडो पर घरेलू दबाव का परिणाम माना जा रहा है।

ना कहने की कला

> उत्पादकता, भलाई और पेशेवर अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ कार्यों या अनुरोधों को अस्वीकार करने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है।

साक्षी सेठी
(लेखक शिक्षक हैं)

सीमाएँ निर्धारित करने से कर्मचारी उच्च-मूल्य वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और उनकी भलाई की रक्षा होती है। आधुनिक कार्यस्थल में, पेशेवरों से अक्सर कई तरह के कार्यों और जिम्मेदारियों को संभालने की अपेक्षा की जाती है, जिससे अभिभूत होना आसान हो जाता है। जबकि कई कर्मचारी अच्छे पक्ष में रहने या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हाँ-बॉस की मानसिकता अपनाते हैं, ना कहने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ अनुरोधों को अस्वीकार करना सीखना, प्रतिनिधिमंडल के प्रभावी उपयोग के साथ, समय प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने की कुंजी है। आज के तेज-तर्रार और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कार्य वातावरण को देखते हुए, ना कहना सीखना किसी भी पेशेवर के लिए सबसे मूल्यवान कौशल में से एक हो सकता है। जबकि कार्यस्थल अक्सर व्यक्ति को कर-सकने वाले रवैये के साथ पुरस्कृत करता है, लेकिन उत्पादकता, भलाई और पेशेवर अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ कार्यों या अनुरोधों को अस्वीकार करने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है।

अक्सर असहयोगी के रूप में देखे जाने, सहकर्मियों के साथ संबंधों को नुकसान पहुँचाने या भविष्य के अवसरों को खोने का एक अंतर्निहित डर होता है। इसका परिणाम एक अतिभारित शेड्यूल है, जो उत्पादकता में कमी, खराब कार्य गुणवत्ता और यहाँ तक कि बर्नआउट का कारण बन सकता है। यह व्यक्ति और संगठन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अत्यधिक काम के बोझ तले दबे कर्मचारियों को समय-सीमा को पूरा करने या घटिया काम करने में परेशानी हो सकती है। मना करने की क्षमता केवल अनुरोधों को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन

सीमाओं को निर्धारित करने के बारे में है जो किसी के समय और ऊर्जा की रक्षा करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को वह ध्यान मिले जिसके वे हकदार हैं। अनावश्यक या कम प्राथमिकता वाले कार्यों को न कहने से पेशेवरों को उच्च-मूल्य वाले काम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं, संगठन में अधिक योगदान मिलता है और व्यक्तियों को अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने में मदद मिलती है। इसके स्पष्ट लाभों के बावजूद, न कहना अक्सर कहने में आसान होता है, करने में नहीं। कई कर्मचारियों को सांस्कृतिक या संगठनात्मक दबावों के कारण कार्यों को अस्वीकार करना मुश्किल लगता है जो मददगार होने को जितना संभव हो उतना काम लेने के बराबर मानते हैं। कुछ को तो यह भी डर है कि न कहने से उन्हें मुश्किल या टीम के खिलाड़ी बनने के लिए अनिच्छुक करार दिया जा सकता है, जिससे पदोन्नति या अवसर छूट सकते हैं। इसके अलावा, व्यक्ति अक्सर न कहने में व्यक्तिगत बाधाओं से जूझते हैं। पूर्णतावाद, संघर्ष का डर या दूसरों को खुश करने की इच्छा सीमाएँ निर्धारित करना कठिन बना सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी यह चिंता करते हैं कि अतिरिक्त कार्यों को करने से मना करना उनकी अक्षमताओं या काम के प्रति समर्पण की कमी को दर्शाता है। लेकिन वास्तव में, कार्यस्थल पर मना करने से व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। जब किसी कार्य को सीधे मना करना एक विकल्प नहीं होता है, तो प्रभावी प्रतिनिधिमंडल एक रचनात्मक विकल्प प्रदान कर सकता है क्योंकि यह काम को एक टीम में वितरित करने की अनुमति देता है, जो समग्र उत्पादकता को बढ़ा सकता है, आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकता है और टीम के भीतर स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकता है। यह रणनीतिक कार्यों और उच्च प्राथमिकता वाली जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है, जिन पर उनका ध्यान देने की आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तियों की क्षमताओं में विश्वास प्रदर्शित करता है, जो टीम के मनोबल को बेहतर बना सकता है और अधिक सहयोगी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित कर सकता है।

हालाँकि, मना करना और प्रभावी ढंग से काम सौंपना कार्यस्थल में सफलता के लिए दो महत्वपूर्ण कौशल हैं। मना करना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय और ऊर्जा की रक्षा करने में मदद करता है, जबकि प्रतिनिधिमंडल नेताओं को काम को अधिक प्रभावी ढंग से वितरित करने और दूसरों को सशक्त बनाने की अनुमति देता है। मना करने और काम सौंपने की कला में महारत हासिल करके, पेशेवर न केवल अपने कार्यभार का प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि एक अधिक कुशल और सशक्त टीम को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

आप की बात

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना से बड़ी संख्या में लोग इलाज का लाभ उठा रहे हैं। बायोमीट्रिक पहचान के जरिए सही लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मगर कुछ हॉस्पिटल इस योजना में गलत तरीके से फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-कैग ने ऐसे 24 अस्पताल चिन्हित किए हैं जिन्होंने अपनी क्षमता से अधिक मरीजों की भर्ती बताकर सरकार से भुगतान प्राप्त किया है। इसके अलावा आयुष्मान योजना में इलाज पूर्णत: निशुल्क होने के बावजूद भी कुछ हॉस्पिटल मरीजों के परिवारों से दवाइयां व जांच व अन्य सामग्री के पैसे लेते हैं। यह सरासर बेइमानी है जिसका कारण इस योजना से लाभ उठाने वाले अधिकांश लोगों को पूरी जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही शिकायतें मिली हैं कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के प्रति हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर उचित व्यवहार नहीं करते हैं। इससे मरीजों को अपमान झेलना पड़ता है। कई हॉस्पिटल तो आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से मना कर देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों को विफल करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के साथ इस योजना के लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे जनता को पूरा लाभ आसानी से मिलेगा।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

चंद्रबाबू नायडू की राय

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उस सरकार का हिस्सा हैं जिसके अनेक नेता पिछले काफी समय से जनसंख्या नियंत्रण नीतियां लागू करने की मांग कर रहे हैं। कुछ भाजपा सदस्यों ने दो बच्चों की नीति पर जोर दिया है। मगर चंद्रबाबू नायडू ठीक इसके विपरीत जाते हुए अपने राज्य में ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बुढ़ाते लोगों की संख्या चिंता का विषय है। राज्य सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाएगी। नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रजनन दर लगातार गिरती जा रही है। देश में जहां औसत प्रजनन दर जहां 2.1 है, वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में यह गिर कर 1.6 तक पहुंच गई है। हालांकि, केंद्र की यूथ इन इंडिया-2022 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी जो अभी 47 प्रतिशत से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं, लेकिन अगले 15 साल में यह संख्या और तेजी से गिरेगी। हालांकि, चंद्रबाबू नायडू की चिन्ता दक्षिण भारत के लिए तो ठीक है, पर यही बात बिहार व उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं होती है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

चुनावी राजनीति

चुनावों की घोषणा होते ही मतदाताओं को लुभाने, भरमाने या भड़काने की होड़ मच जाती है। महाराष्ट्र और झारखंड में प्रमुख दो गठबंधन चुनाव मैदान में हैं तथा मतदाताओं को रिझाने के लिए लुभावनी घोषणायें कर रहे हैं। लेकिन जाति और धर्म के मुद्दे को उठाकर राजनीति करने वाले दलों के लिए विजय पथ अधिक पथरीला हो गया है क्योंकि जनता अब खोखले नारों की असलियत समझने का प्रयास कर रही है। मुस्लिमों को भाजपा का भय दिखाकर और भाजपा को उनका स्थाई दुश्मन बताने वाली कांग्रेस व उसके गठबंधन के साथियों के विरुद्ध मुस्लिमों के मन में लगातार बढ़ता संदेह यही सिद्ध करता है। अनेक प्रकार के मुल्ला-मौलवी सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ भड़काने वाली बातें करते हैं। इनमें से अधिकांश कांग्रेस या उसके सहयोगियों के बजाय छोटी मुस्लिम पार्टियों के समर्थक हैं। इनकी भड़काऊ बातें कई बार कानून और संविधान की सीमायें तोड़ती नजर आती हैं, लेकिन विडंबना है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समय आ गया है कि सिर तन से जुदा जैसे नारे लगाने वालों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

- सुधाकर आशावादी, मेरठ

सोने के दाम

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने पर 6 प्रतिशत ड्यूटी घटाकर जो राहत और खुशी महिलाओं दी थी वो कुछ माह में ही गुम हो गई। ड्यूटी घटाने पर सोना 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम होकर करीब 68800 हो गया था किन्तु अब तो वह 79000 पार हो गया। कहते हैं सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। लेकिन बढ़ती कीमतों ने तो उल्टे उसके खरीदारों को ही तपा दिया। धनतेरस तक तो इसके दाम और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। निर्मला जी ने सोना सस्ता कर महिलाओं का जितना दिल जीता था आज उतना ही महंगा होने से सोना नारियों के लिए अब दिलजला होता जा रहा है। सरकार को घरेलू बाजार में सोने के दाम कम करने के उपाय करने चाहिए। शायद ड्यूटी और घटाने पर विचार हो सकता है। सोने के दामों से उसके खरीदारों के साथ ही लाखों छोटे-बड़े कारीगरों की किस्मत भी जुड़ी है। यह देखना भी जरूरी हो गया है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए काम करने वाले कारीगरों की जिंदगी में कितनी चमक आई है।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024

बौखलाए आतंकी

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में रविवार रात को आतंकवादियों ने जिस तरह से एक कंस्ट्रक्शन प्रॉजेक्ट में काम कर रहे लोगों को निशाना बनाया, वह कई लिहाज से गंभीर घटना है। इस हमले से न केवल आतंकवादियों की बौखलाहट का पता चलता है बल्कि उनकी बदली प्राथमिकताओं का भी अंदाजा मिलता है।

नाकामी से उपजी बेचैनी | पिछले कई वर्षों से सुरक्षा बलों की चौकसी के चलते जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में आई कमी और आम जनजीवन पर उनके घटते असर से चिंतित आतंकी आकाओं ने आम चुनावों के दरम्यान अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ऐसे इलाकों को चुना गया जहां सुरक्षा बलों की तैनाती कम और मुश्किल थी। टारगेटेड अटैक के जरिए बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया ताकि उनमें घबराहट फैले और टूरिस्टों का आना कम हो। मगर ये तमाम चालें निष्फल साबित हुईं।

निशाने पर कंस्ट्रक्शन प्रॉजेक्ट

चुनाव में भागीदारी | चुनाव में बाधा डालने का उनका प्रयास भी नाकाम रहा। न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इतना ही नहीं, इनमें लोगों की भागीदारी के भी रेकॉर्ड बने। ऐसे में अब आतंकी तत्वों ने जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के गठित होते ही इस बड़े हमले को अंजाम देकर यह जताने का प्रयास किया है कि वे जनादेश के तहत बनी इस सरकार की राह में अड़ंगा डालने का हरसंभव प्रयास करते रहेंगे।

अहम प्रॉजेक्ट पर निशाना | इस बार हमले के लिए श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच बनाई जा रही जेड-मोड़ टनल का काम कर रहे लोगों को चुना गया। यह टनल न केवल जम्मू-कश्मीर के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि रणनीतिक तौर पर भी खासी अहमियत रखता है। इसके निर्माण से श्रीनगर और करगिल के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा और श्रीनगर व लेह के बीच की यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा। यही नहीं, इस टनल के जरिए टूरिस्टों के पसंदीदा शहर सोनमर्ग की हर मौसम में कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

लक्ष्य दूर नहीं | जाहिर है, विदेशी जमीन पर बैठे आतंकवादी तत्वों ने इस एक हमले के जरिए कई उद्देश्य पूरे करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि हमले के बाद आई प्रतिक्रियाओं से साफ है इस मसले पर पक्ष-विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। सबसे बड़ी बात यह कि अब आतंक के खिलाफ उठे इन स्वरों में जम्मू-कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी कर रही आवाजें भी शामिल हैं। सम्मिलित सुनियोजित प्रयासों से जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद के बचे-खुचे निशानों से भी मुक्त करने का लक्ष्य अब पहुंच से दूर नहीं कहा जा सकता।

धूप-छांव

कोई शर्त नहीं

प्रणव प्रियदर्शी

जिंदगी को रिश्तों की शक्ल में देखने की कोशिश करें तो इसके अनेक रूप नजर आते हैं। रिश्तों का एक पूरा पैकेज हमें जन्म के साथ ही मिल जाता है। यह जिंदगी का ऐसा तोहफा होता है, जो जीवन को संभव बनाता है। मां-बाप, भाई-बहन, चाचा-चाची, मामा-मामी, दादा-दादी, नाना-नानी... ये सब बिना शर्त हमारा इस दुनिया में पलक-पांवड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। एक किलकारी भरने, अपने दम पर उठकर बैठने, अपने पांवों पर खड़े होने, डगमगाते कदमों से आगे बढ़ने और तोतली जुबान से कुछ शब्द बोलने पर जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। यह अलग बात है कि इस शर्त रहित प्यार की उम्र लंबी नहीं होती। धीरे-धीरे इसमें दुनियावी छल-छंदों, स्वार्थों का प्रवेश होता है और ये जटिल से जटिलतर होते चले जाते हैं।

जिंदगी हमें अपने रिश्ते खुद चुनने के मौके भी कम नहीं देती। एक बार होश संभाल लें तो उसके बाद बनने वाली सारी दोस्तियां इसी श्रेणी में आती हैं। आगे चलकर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी बने तो वह चुना हुआ रिश्ता ही होता है। यह अलग बात है कि मामला शादी तक पहुंच जाए तो एक बार फिर रिश्तों का ऐसा बड़ा सा पैकेज मिलता है, जिसमें अपनी कोई मर्जी नहीं होती। यहां तक कि जीवनसाथी बन जाने के बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की हैसियत भी चुने हुए रिश्ते जैसी कम ही रह पाती है। ज्यादातर मामलों में हम उसे अपने नसीब वगैरह या मति भ्रष्ट होने का परिणाम मानने लगते हैं।

बहरहाल, ये तमाम रिश्ते उस श्रेणी मे आते हैं जो किसी न किसी रूप में जीवन का आधार बनते, उसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन रिश्तों का एक अनोखा रूप वह भी है जिसमें उनका हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन से कोई सीधा प्रयोजन नहीं होता। किसी खास पल में, पल भर के लिए या दो-चार पलों के लिए अपना संस्पर्श देकर वे रिश्ते अनंत में विलीन हो जाते हैं। हमारे पास उस नरम से, सुकून भरे स्पर्श का अहसास भर रह जाता है। कभी बाजार की भीड़ में दिखा कोई प्यारा सा चेहरा और उसकी उलझन, कौतूहल भरी दृष्टि। कभी किसी महफिल में किसी दोस्त के दोस्त से हुआ परिचय और वहां हुई दो-चार बातें जिनका कोई सिरा दिल में फंसा रह गया हो। कभी किसी लंबी रेल यात्रा में अजनबी यात्री से हुई लंबी बात, जिसने जीवन की कई उलझी गुत्थियां सुलझा दीं। ये रिश्ते हमसे कभी कुछ मांगते नहीं, बस अच्छी स्मृतियों के रूप में मन के किसी कोने में दर्ज रहते हैं और कठिन पलों में झांक कर हमे थोड़ा-सा सुकून, थोड़ी-सी राहत दे जाते हैं, बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी शर्त।

बोल वचन

पनछुछुर चाय

राहुल पाण्डेय

सुबह की नौबजवा पैसेंजर पकड़कर फैजाबाद से प्रयागराज (इलाहाबाद) की ओर चलिए तो रास्ते में सुल्तानपुर के बाद एक बड़ा 'प्रतापी' स्टेशन आता है। इस स्टेशन के पकौड़े जितने फेमस हैं, चाय उतनी ही बदनाम। चाय पीने की इच्छा कितनी भी हो, कोई इसे पूरी नहीं पी सकता। उसमें दूध होता नहीं और चायवाले उसे पानी की चाय मानते नहीं। यह एकदम पनछुछुर चाय होती है। पनछुछुर यानी किसी चीज को एकदम पानी जैसा बेस्वाद बना देना। वैसे, सिर्फ चाय ही पनछुछुर नहीं होती। बाज दफे दाल, सब्जी और यहां तक जिंदगी भी पनछुछुर हो जाती है। होली के लोकगीतों में ढेरों जीजाओं का रंग पनछुछुर हो रखा है। भोजपुरी और मगही में पनछुछुर का अर्थ होता है- पानी मिला हुआ, फीका। अवध आकर इसमें स्वाद और जुड़ जाता है यानी पानी से भी बेस्वाद। इन दिनों एक चुटकुला काफी चल रहा है, जिसमें एक IAS एस्पिरेंट से पूछा जाता है कि हॉस्टल में उसके बगल वाला तो IAS क्रैक कर ले गया, वह क्यों नहीं कर पाया? इस पर वह कहता है कि वो तो बस पांच मिनट में पका लेता था, एकदम पनछुछुर चिकन। पनछुछुर पकाकर तो कोई भी IAS बन सकता है! घर में आई नई बहू को अगर ललिता पवार जैसी कोई सास मिल गई, तो भले उसकी सब्जी होटल ताज से टक्कर ले, लेकिन सास उसे पनछुछुर ही कहती है। फीका, बेस्वाद आदि के लिए तो इंग्लिश में प्रॉपर शब्द हैं, लेकिन पनछुछुर जितनी तरह की भावनाएं रखता है, उसके लिए इंग्लिश में watered down या diluted with water जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द देखकर लगता है कि ये शब्द अपने आप में पनछुछुर हैं।

Subrata Dhar

नागरिकता क़ानूनों में हुए संशोधन धीरे-धीरे इसके दायरों को कम करते चले गए हैं

6A पर SC के फ़ैसले का क्या है मतलब

टी के अरुण

देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए बहुमत से असम समझौते की वैधता पर मुहर लगाई। यह भी बताया कि पेचीदा राजनीतिक मसलों को हल करने के लिए हमेशा कोर्ट के पास आना मुनासिब नहीं।

कैसा हो कानून | देश को नए नागरिकता कानून की जरूरत है। यह कानून इस सिद्धांत पर आधारित हो कि देश में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। संविधान सभा द्वारा अपनाए गए इस सिद्धांत को 1955 के नागरिकता अधिनियम में शामिल किया गया था। लेकिन 1985, 1986, 2003 और 2019 में नागरिकता अधिनियम में किए गए संशोधन इस सिद्धांत की व्यापकता को कम करते गए।

इन्क्लूसिव प्रिंसिपल | भारत ऐसा विविधतापूर्ण देश है, जहां अलग-अलग धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और जातीय पहचान वाले लोग रहते हैं। ऐसे में नागरिकता का निर्धारण करते समय किसी भी रूप में समावेशी सिद्धांत को कमजोर करना देश का अहित कर सकता है और इसके हिंसक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। समावेशी नागरिकता सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है, जो अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने की एक अनिवार्य शर्त है।

दो सिद्धांत | इस संबंध में दुनिया भर में दो सिद्धांत प्रचलित हैं- 'जूस सोली' और 'जूस सैंगुइनिस'। लैटिन के इन शब्दों का क्रमशः मतलब है 'मिट्टी का अधिकार' और 'रक्त का अधिकार'। अमेरिका पहले सिद्धांत के आधार पर अपने यहां जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकार के रूप में नागरिकता देता है। इसके विपरीत, जर्मनी दूसरे सिद्धांत के आधार पर जर्मन वंश के लोगों को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नागरिकता प्रदान करता है।

संशोधन से संकीर्णता | 1985 के संशोधन ने नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A को जोड़ा। इससे 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आने वाले सभी लोगों को बिना शर्त नागरिकता और अधिकार मिल गए, जबकि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक आने वालों को सशर्त नागरिकता के अधिकार मिले। जो लोग 1966 और 1971 के बीच भारत आए, उन्हें नागरिकता मिल सकती थी, लेकिन वोट देने का अधिकार नागरिकता पाने के 10 साल बाद ही मिल सकता था।

संशोधन का असर | 1986 में कानून में संशोधन करके कहा गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार बिना शर्त नहीं है। 1 जुलाई, 1987 के बाद पैदा हुए लोगों के नागरिकता पाने के लिए उनके माता-पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी हो गया था। 2003 के संशोधन ने जन्म से नागरिकता के दायरे को और कम कर दिया। अब माता-पिता में से किसी एक का भारतीय मूल का होना पर्याप्त नहीं था। नए प्रावधान के मुताबिक, माता-पिता में से कोई भी अवैध आप्रवासी नहीं हो सकते थे।

धार्मिक आधार | 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) इसमें एक स्पष्ट धार्मिक तत्व ले आया। इसमें मुसलमानों को उन धर्मों से बाहर रखा गया, जिनके सदस्य भारत के पड़ोसी देशों में उत्पीड़न से बचने के लिए शीघ्र भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। भारतीय नागरिकता के दायरे को धीरे-धीरे कम करते जाना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अजेंडे का हिस्सा है। संघ परिवार का लक्ष्य भारत में हिंदुओं को प्राथमिकता देना और सभी गैर-हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है।

क्या है चिंता की बात

- नागरिकता कानून समावेशी होने चाहिए
- इसे किसी की पहचान से न जोड़ा जाए
- विविधता भारत की खासियत रही है

संस्कृति का संरक्षण | धारा 6A की संवैधानिकता को जिन आधारों पर चुनौती दी गई, उनमें एक यह था कि बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देना असमिया भाषी समुदाय के अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के उस अधिकार का उल्लंघन है, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने वाले किसी भी नागरिक समूह को उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों का एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है।

सांस्कृतिक सहअस्तित्व | सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि बांग्ला भाषियों के प्रवेश को वैध बनाने से असमिया भाषियों के अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। सांस्कृतिक सह-अस्तित्व ही भारत की मूल विशेषता है और यह किसी विशेष संस्कृति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता।

समान दर्जा | यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन याद रखने की बात यह भी है कि संस्कृति का संरक्षण एक जटिल मसला है। दुनिया भर की ज्यादातर संस्कृतियां महिलाओं को समान दर्जा देने में विफल रही हैं, जबकि अधिकतर लोकतंत्र उन्हें समान अधिकार देते हैं। मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देती। मध्ययुगीन इस्लामी कहावत के अनुसार, वित्तीय मामलों में दो महिलाओं की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर होती है। ऐसे सांस्कृतिक मानदंडों को आज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

फिसलन भरी ढलान | भारतीय नागरिकता एक फिसलन भरी ढलान पर है। यह मिट्टी के अधिकार के लोकतांत्रिक शिखर से रक्त के अधिकार के करीब आती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से प्रमाणित असम समझौते की खूबी नागरिकता सिद्धांत की व्यापकता में प्रतिबंध का स्वाद जोड़ती है। अब और भी अधिक प्रतिबंधात्मक CAA की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का इंतजार करना होगा।

सर्किट अइसे मनाएगा पलूशन फ्री दिवाली

नमिता जोशी

दिवाली आने वाली है सर्किट। इस बार क्या प्लान है? अपुन ने सर्किट से पूछा तो स्प्रिंग के माफिक उछल के बोला, अरे भाई, इस बार न अपुन सोच रयेला है दिवाली पे दिल्ली जाने का...बड़ा पटाखा फोड़ेंगे, गजब का मस्त माहौल होगा! बीच में चमन चिरकुट बोला, अबे सर्किट, तेरेकू मालूम नहीं? पटाखे फोड़ने पर तो बैन है भाई, और ऊपर से दिल्ली में तो इतना पलूशन होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है!

सर्किट इस बात को सुन के अइसे हंसने लगा जइसे रामलीला में खराब लाउडस्पीकर से रावण की हंसी सुनाई देती है। बोले तो चमन चिरकुट को पलूशन की चिंता खा रयेली है देखो ना? अक्खा दिन में अकेले 8 पैकेट सिगरेट फूंकने वाला बंदा अपुन को पलूशन के लिए डरा रयेला है। सिगरेट के धुएं ने तेरे फेफड़े के साथ साथ तेरा भेजा भी पत्थर का कर दिया क्या चिरकुट? एक रात के पटाखे तेरे जइसे का क्या बिगाड़ पाएंगे? वइसे भी अपुन तो पटाखे के बिना भी दिवाली मना सकते हैं।

अपुन को सर्किट की इस बात में तो लॉजिक नजर आया। दिल्ली में तो ऑलरेडी पलूशन का रोना शुरू हो गयेला है। सर्किट बोला, भाई रोना धोना एक तरफ, पटाखे सब चलाते हैं, रोने वाले भी और ना रोने वाले भी। तभी तो दिल्ली हर साल दिवाली में पलूशन के नए लेवल पर पहुंच जाती है। कुछ चीजें बोलने में अच्छी लगती हैं, जइसे हम सबको सच बोलना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पन

AI Image

भेजा फ्राई

दिवाली वाले दिन पटाखे नहीं फोड़े तो कइसी दिवाली? कहते हैं ना, जहां नाश, वहां सवा सतयानाश।

अपुन बोला, बात तो सही कह रहा है चमन चिरकुट! अपुन कू मालूम है दिल्ली में अक्खा खेल इच इस बात का है कि दिवाली के दिन किसने सबसे ज्यादा पटाखा फोड़ा और किसने सबसे ज्यादा धुआं किया। इतने धुएं में तू कइसे छाती ठोक के शो ऑफ करेगा। दिल्ली की दिवाली का आयडिया ड्रॉप कर। मुंबई में ही कुछ नया धमाका करते हैं। मुंबई इस्टाइल में। सर्किट बोला, बोले तो, कइसा इस्टाइल भाई? इधर मुंबई में कोई किसी को नहीं पूछता। दिवाली में बम फूट रयेले हैं या सच्ची का एनकाउंटर हो रयेला है या फिल्म की शूटिंग हो रयेली, कुछ समझ नहीं आता तो इदर क्या धमाका करेंगे? सर्किट का रोना सुन के चमन बोला, इस बार अपुन फुल-ऑन टपोरी स्टाइल में सेलिब्रेशन करेंगे! लेकिन बिना पटाखों के क्योंकि पलूशन का बवाल मुंबई में भी कम नहीं है! और वइसे भी अपुन दोनों मिलके एक दर्जन सिगरेट के पैकेट फूंक इच डालते हैं?

सबसे पहले हम अपुन की पूरी गली को लाइटों से अइसा सजा देंगे कि अम्बानी के घर की लाइटिंग फीकी लगेगी! सर्किट, तू अपने सारे इलेक्ट्रिशन वाले जुगाड़ लगा! मगर पटाखे का क्या? दिवाली बिना पटाखे के शोर के अपुन को नहीं जमती। ये सुनके चमन बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए भेजा काइकू फ्राई करता है। इस बार पटाखे की जगह अपुन बजाएंगे, पटाखे की आवाज वाला टेप रिकॉर्डर। और हां, कपड़े भी एकदम मस्त लाइट वाले पहनने हैं। अमिताभ बच्चन के सारा जमाना हसीनों का दिवाना स्टाइल वाली जैकेट पहनने का और अक्खा चॉल में छा जाने का। चाइनीज मार्केट से अपुन लाया था 80 रुपये का एक अइसा लाइट वाला जैकेट। सर्किट का ये आइडिया सुनके चिरकुट बोला, तेरे नन्हे से दिमाग की बत्ती तो एकदम सही जली है, पर ध्यान रहे कि कोई इतनी लाइट वाले कपड़े देख के तेरे कू पटाखा समझ के नीचे से लाइटर न लगा दे।

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesofindia.com** और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

फुस्स हुई प्लानिंग

कभी-कभी एडवांस प्लानिंग के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में एक कार्यक्रम की तैयारी के दौरान हुआ। राजनीतिक कार्यक्रम के लिए प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भारी तैयारी की थी। कार्यक्रम हालिया संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद होने थे। ऐसे में उस कार्यक्रम में एक ऐसे नेता को चीफगेस्ट बना लिया गया, जिनके बारे में पहले से अनुमान लगा लिया गया था कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। दूरगामी सोच के तहत पहले से उनका समय भी ले लिया गया था। सारी तैयारी हो पूरी हो चुकी थी। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया। चुनाव के बाद जिन नेताजी के अच्छे दिन आने का पूरा विश्वास था, उनके साथ उलटा हो गया। न सिर्फ वह सत्ता से दूर हो गए, बल्कि पार्टी नेतृत्व भी उनसे नाराज हुआ। अब बिहार के नेता के सामने बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है कि वह क्या करें? पहले से दिया गया न्योता वापस तो कर नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने बीच का रास्ता चुना। जिस कार्यक्रम को अपनी राजनीति के लिए बड़े पैमाने पर करने की योजना बना रहे थे, परिणाम आने के बाद उसे किसी तरह लो प्रोफाइल तरीके से निपटाया और उनकी कोशिश रही कि इस बारे में कम से कम बात हो।

आबादी बढ़ाओ

ऐसे समय जब केंद्र में सत्तारूढ़ BJP अगले कुछ बरसों में जनसंख्या नियंत्रण को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है और 2029 से पहले संसद में सीटों का परिसीमन भी नए सिरे से करने की कोशिश में है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और BJP के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी को नई उलझन में डाल दिया है। नायडू ने अपने राज्य सहित पूरे दक्षिण भारत में लोगों से जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनसंख्या वृद्धि के लिए वह नया कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा कानून ला सकती है, जिसमें वही स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार बनने के योग्य होंगे, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों। अब इस मसले पर BJP का क्या स्टैंड होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही, जनसंख्या वृद्धि की अपील से अधिक चिंता परिसीमन को लेकर है। दक्षिण के अधिकतर राजनीतिक दल पहले से ही इस बात को लेकर अपनी शंका जाहिर कर चुके हैं कि सिर्फ जनसंख्या के कारण उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। अब नायडू के साफ स्टैंड लेने से BJP की चुनौती बढ़ गई है।

बिहार में सस्पेंस

इन दिनों बिहार में नया सियासी सस्पेंस बना हुआ है। इसका कारण BJP नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बिहार यात्रा है। JDU इस यात्रा को लेकर असहज है। वह इसे नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती मान रही है। वहीं BJP के अंदर भी एक गुट इस बात को लेकर संशय में है कि गिरिराज सिंह की यात्रा पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व की सहमति है या नहीं? अगर यात्रा नेतृत्व की सहमति से होगी तो माना जाएगा कि पार्टी गिरिराज सिंह को राज्य में अपने चेहरे के रूप में प्रॉजेक्ट कर रही है। लेकिन सस्पेंस इसलिए बन गया कि पार्टी नेतृत्व किसी तरह का कोई संकेत नहीं दे रहा है। न तो यात्रा से वह बहुत खुश दिख रहा है और न नाराज। ऐसे में जब तक स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा, तब तक इस यात्रा के इर्द-गिर्द सियासी सस्पेंस बना रहेगा।

विदेश जाने की होड़

इन दिनों देश के सभी मुख्यमंत्रियों में विदेश जाकर निवेश लाने की होड़ सी लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों से किसी न किसी राज्य के सीएम देश से बाहर रह रहे हैं। इनमें BJP के सीएम सबसे आगे हैं। राजस्थान के सीएम तो इतने कम समय में तीन-तीन बार विदेश जा चुके हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों के सीएम पिछले दो महीने के अंदर यूरोप और अमेरिका के टूर कर चुके हैं। चर्चाओं के अनुसार, अब इन तमाम दौरों को लेकर विस्तृत फीडबैक भी तैयार किया जा रहा है कि इससे किसे कितना लाभ हुआ। विदेश जाने में कितना खर्च हुआ, कितना निवेश लेकर मुख्यमंत्री वापस आए। अगले दो महीने में कम से कम पांच और मुख्यमंत्रियों ने भी विदेश जाने के लिए आवेदन दे रखा है। इनका दौरा विदेश मंत्रालय की अनुमति के बाद ही तय होता है।

गुस्से में राहुल गांधी

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहुत गुस्से में बताए जा रहे हैं। समीक्षा मीटिंग में एक नेता ने जब अपनी बात रखी तो राहुल ने उन्हें पूरी रिपोर्ट दिखा दी कि कहां-कहां गड़बड़ी हुई और इसमें उनकी भी गलती रही। इससे असहज हुए नेता ने दांव खेला कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं तो राहुल ने उन्हें तुरंत कह दिया कि वह कोई भी निर्णय ले सकते हैं। नेता तुरंत बैकफुट पर आ गए। उसी तरह जम्मू-कश्मीर में खराब प्रदर्शन के बाद जब सरकार गठन के समय पार्टी के नेताओं ने हिस्सेदारी को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी की, तो राहुल गांधी ने उन्हें रोका। साफ संदेश पहुंचाया कि सिर्फ वही बात करेंगे और बाकी नेता पार्टी को मजबूत करने में जुटें, ताकि आइंदा ऐसी नौबत न आए। वहां भले I.N.D.I.A. की सरकार बनी हो, लेकिन कांग्रेस का अपना प्रदर्शन बहुत खराब रहा। राहुल गांधी ऐसा ही आक्रामक रुख झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान रख रहे हैं और चीजों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, हरियाणा चुनाव के बाद उन पर कुछ अधिक ही नरम होने का आरोप लगा है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ कांटे की टक्कर

यह पत्र 21 अक्टूबर के लेख 'महाराष्ट्र में होगी असली-नकली की लड़ाई' से संबंधित है। जून में हुए संसद के चुनावों में महाविकास अघाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया। विशेषकर शरद पवार की NCP ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से यह साफ हो जाएगा कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौन-से धड़े को जनता ज्यादा पसंद करती है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी का कोई भी घटक दल महाराष्ट्र चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा और अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है।

बाल गोविंद, नोएडा

■ टूटता भरोसा

8 अक्टूबर को 'भेजा-फ्राई' कॉलम में 'नेता लोग के चक्कर में दोस्ती नहीं तोड़ने का' शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ा। चुनाव आते ही नेताओं का दल बदलना आम बात है। वे अपने फायदे के लिए कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी में नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी बदलते ही उनके तेवर बदल जाते हैं। अपनी ही कही बातों को बड़ी सफाई से काटने से परहेज नहीं करते। चिरकुट ने सही बोला है कि पॉलिटिक्स छोड़ो और अपनी दोस्ती पर ध्यान दो, नेता लोग पलटी मारते रहते हैं।

पैंथर तोमर, दिल्ली

■ दोस्ती की ओर

19 अक्टूबर का संपादकीय 'पॉजिटिव संकेत' पढ़ा। पाकिस्तान में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) की शिखर बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जिस कुशल डिप्लोमेसी से सकारात्मक माहौल को जन्म दिया है, वह पाकिस्तान के साथ मधुर संबंधों का सबब भी बन सकता है। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों के लिए पहले भी इच्छा जताई थी। इस समय उन्हीं की पार्टी की सरकार है।

माम चंद सागर, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

यूक्रेन ने भेजे ड्रोन तो रूस ने दागी मिसाइलें - एक खबर

- तो यह हो गई न, नहले पर दहले वाली बात!

पूनम यादव

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

पत्नी की लंबी उम्र के लिए पुरुष भी रखें व्रत

शैलेंद्र पांडेय

हमारे समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच काम का बंटवारा तो कर ही रखा है, साथ में व्रत-उपवास को भी बांट दिया है। ज्यादातर व्रत सिर्फ महिलाओं के जिम्मे हैं। इन्हीं में से है करवा चौथ। हालांकि अब कुछ बदलाव भी आ रहा है। इसकी झलक दिखी इस बार सोशल मीडिया और इंटरनेट पर। गूगल (Google) पर टिप्स ट्रेंड (Trend) किए कि पुरुषों को किस तरह करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। कुछ बरस पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। कुछ पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते भी थे, तो बहुत सकुचाकर, दबे-छिपे, मानो कोई जुर्म कर रहे हों।

कहा जाता है कि गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिये हैं पति और पत्नी। लेकिन, हमारे समाज ने सारा बोझ एक ही पहिये पर डाल रखा है। पति की लंबी आयु और घर-परिवार में सुख-समृद्धि के लिए जितने भी व्रत हैं, उन सबको निभाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही लादी गई है। कुछ पुरुष अगर इस पितृसत्तात्मक (Patriarchy) व्यवस्था को चुनौती दे रहे, तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ट्रोल (Troll) नहीं। लंबी उम्र की जितनी जरूरत पुरुषों को है, उतनी ही महिलाओं को भी। परिवार को दोनों मिलकर चलाते हैं। दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं रहा, तो गाड़ी बेपटरी हो जाएगी। ऐसे में आदमियों का भी फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी के लिए व्रत रखें।

हमारे समाज में महिलाओं को शुरू से पुरुषों की छत्रछाया में रखा गया। उसके अस्तित्व को हमेशा बेटी, बहन, पत्नी के रूप में देखा गया। आज भी कई महिलाओं की पहचान उनके पति के नाम से होती है। उनका खुद का नाम बस कागजों में जिंदा होता है और जिसे पुकारने वाला कोई नहीं होता। अब जिसके स्वतंत्र अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश की जा रही है, उसके योगदान को कैसे महत्व मिलेगा? यहां तो मान लिया गया कि उनके लिए किसी के आश्रय में रहना और किसी के निर्देशन में काम करना ही बेहतर है। उन्हें 'सदा सुहागन रहो' जैसे आशीर्वाद दिए जाते हैं। इसके पीछे प्रकट मनोकामना यह है कि हमेशा सुहागन रहो। लेकिन, अप्रकट भाव को देखिए कि, तुम सुहागन रहते ही इस दुनिया से चली जाओ यानी तुम्हें अपने पति की मौत न देखनी पड़े! यह उसी सोच का नतीजा है, जिसमें महिलाओं के वजूद को किसी पुरुष से जोड़ दिया गया है।

करवा चौथ को रिश्तों में प्रेम दर्शाने वाला व्रत मानते हैं। हालांकि व्रत की कथा का सार यह है कि एक महिला ने गलती से विधान तोड़ा, तो उसके पति की मौत हो गई। फिर उसने अपने पति को वापस पाने के लिए सालभर कड़ी तपस्या की। अब प्रेम के बीच सजा क्यों आ गई? सैकड़ों बरसों से महिलाएं उस गलती से बचने की कोशिश में सख्त उपवास किए जा रही हैं। पानी का एक भी घूंट पिए बिना घर के सारे काम करना और उसी में पूजा- यह तपस्या से कम नहीं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं और न ही कमजोर हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए। उन्हें बस जरूरत है बराबर मौकों और व्यवहार की। करवा चौथ अच्छा मौका है तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करने का।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 212

नीतिगत प्रक्रिया

देश के वित्तीय बाजारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी नीतिगत दरों में कटौती की शुरुआत कब करेगी? खासतौर पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने के बाद से यह सिलसिला चल रहा है। इस महीने के आरंभ में एमपीसी ने तीन नए बाहरी सदस्यों के साथ बैठक की और नीतिगत रीपो दर को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा। यद्यपि समिति ने तेजी से बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में स्वयं को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अपना रुख 'समायोजन को समाप्त करने' से 'तटस्थ' कर लिया। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक के बाद उसके निर्णय और रुख के पीछे के कारणों को अच्छी तरह स्पष्ट किया। उन्होंने गत सप्ताह एक कार्यक्रम में मौद्रिक नीति तथा अन्य मामलों को लेकर रिजर्व बैंक के रुख को आगे और स्पष्ट किया। ये सभी विषय चर्चा के लायक हैं।

मौद्रिक नीति के मामले में दास ने खासतौर पर कहा कि फिलहाल दरों में कटौती करना अपरिपक्वता होगी और यह 'बहुत जोखिम भरा' हो सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर सितंबर में 5.5 फीसदी रही जिसके लिए मोटे तौर पर ऊंची खाद्य कीमतें वजह रहीं। इसके कुछ और समय तक ऊंचे स्तर पर रहने की उम्मीद है। एमपीसी को अनुमान है कि मुद्रास्फीति की दर चालू वित्त वर्ष में 4.5 फीसदी के स्तर पर रह सकती है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इसके 4.3 फीसदी रहने का अनुमान है। ताजा मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक का अनुमान है कि 2025-26 की चौथी तिमाही में यह दर 4.1 फीसदी तक रह सकती है जो रिजर्व बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य के एकदम करीब होगा। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक तब तक प्रतीक्षा करना चाहता है जब तक कि मुद्रास्फीति चार फीसदी के लक्ष्य के आसपास नहीं टिक जाती। यह एक समझदारी भरा नीतिगत रुख है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर कई सालों से लक्ष्य से ऊपर रही है और फिलहाल वृद्धि बड़ी चिंता का विषय नहीं है।

दास ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाया और वह है मुद्रा प्रबंधन। इस समाचार पत्र सहित कई टीकाकारों ने सुझाया है कि मुद्रा बाजार में अस्थिरता बहुत कम है। रिजर्व बैंक का कहना है कि वह किसी स्तर को लक्ष्य नहीं बनाता और अतिरिक्त अस्थिरता को सीमित रखने के लिए ही हस्तक्षेप करता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 700 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया हालांकि गत सप्ताह यह फिर नीचे आ गया। दास ने कहा कि मुद्रा भंडार को मजबूत करने का सबक टैपर टैंट्रम (अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा परिसंपत्ति खरीद की योजना का आकार कम करना) से मिला। रिजर्व बैंक की मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा के कारण ही 2013 में अमेरिका में मुद्रा संकट जैसी स्थिति बन गई थी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करने की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक नहीं चाहता है कि हमारे यहां वैसे हालात बनें।

यही कारण है कि वह मुद्रा भंडार तैयार करने और मुद्रा बाजार में अतिरिक्त अस्थिरता को नियंत्रित करने पर केंद्रित रहा है। रिजर्व बैंक ने अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करके अच्छा काम किया है लेकिन जैसा कि 2022 की समन्वित वैश्विक नीतिगत सख्ती के दौर में देखा गया, उसे हस्तक्षेप में अधिक चयन बरतने की आवश्यकता है। निरंतर हस्तक्षेप का नतीजा रुपये के निरंतर अधिमूल्यन के रूप में नहीं सामने आना चाहिए जिससे देश की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो। यह बात ध्यान देने लायक है कि 40 मुद्राओं के व्यापार भार वाली वास्तविक प्रभावी विनिमय दर ने दिखाया कि अगस्त में रुपया पांच फीसदी अधिमूल्यित था जो जुलाई के सात फीसदी अधिमूल्यन से बेहतर स्थिति थी। रिजर्व बैंक के लिए यह महत्त्वपूर्ण होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अतिरिक्त अस्थिरता को सीमित करने के चलते मौद्रिक नीति में कोई पूर्वग्रह की स्थिति न बने। निरंतर अधिमूल्यन से प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ सकता है जो लंबी अवधि में वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।

भारत की शुल्क नीति पर ट्रंप के एतराज की हकीकत

अमेरिका की व्यापार नीति को देखते हुए इस वक्त भारत को किसी बाहरी दबाव के आगे झुके बगैर अपने महत्त्व की प्राथमिकताओं का पालन करने की जरूरत है। बता रहे हैं अजय श्रीवास्तव

डेट्रॉयट में 11 अक्टूबर को एक जनसभा के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत विदेशी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है। यह पहला मौका नहीं था। पिछले महीने भी उन्होंने भारत को आयात शुल्क का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला बताया था। 2020 में तो उन्होंने भारत को 'टैरिफ किंग' तक कह डाला था। आइए, देखते हैं कि भारत द्वारा अधिक शुल्क या टैरिफ लगाने जाने के ट्रंप के दावे में कितना दम है और भारत के शुल्क क्या वाकई वैश्विक व्यापार के नियम तोड़ रहे हैं तथा भारत-अमेरिका संबंध इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं।

ट्रंप सबसे ज्यादा शुल्क की ही बात करते हैं। भारत का औसत आयात शुल्क 17 प्रतिशत है जो अमेरिका के 3.3 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। लेकिन ट्रंप इसकी बात ही नहीं करते। इसके बजाय वह अधिकतम शुल्क की बात करते हैं, जिस पर लोगों का ध्यान फौरन पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पर 2019 में उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी व्हिस्की पर 150 प्रतिशत शुल्क लगाता है। भारत बेशक व्हिस्की (150 प्रतिशत) और वाहनों (100-125 प्रतिशत) पर ऊंचा शुल्क लगाता है मगर कई देश अपने कुछ खास उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिक शुल्क लगाते हैं और भारत ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है।

अमेरिका ने विभिन्न उत्पाद समूहों पर उच्चतम शुल्क लगाए हैं। इनमें डेरी उत्पाद (188 प्रतिशत), फल एवं सब्जियां (132 प्रतिशत), अनाज एवं खाद्य सामग्री (193 प्रतिशत), तिलहन, वसा और तेल (164 प्रतिशत), पेय पदार्थ एवं तंबाकू (150 प्रतिशत), खनिज एवं धातु (187 प्रतिशत) और कपड़े (135 प्रतिशत) शामिल हैं।

भारत के उच्चतम शुल्कों को देखकर उसे टैरिफ किंग बताने का ट्रंप का दावा सही नहीं है क्योंकि कई दूसरे देशों के शुल्क भारत से ज्यादा हैं। जापान का उच्चतम शुल्क 457 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया का 887 प्रतिशत और अमेरिका का उच्चतम शुल्क 350 फीसदी है जबकि भारत का उच्चतम शुल्क 150 प्रतिशत ही है। उच्चतम शुल्क आम तौर पर संवेदनशील क्षेत्रों को महफूज रखने के लिए लगाया जाता है। मसलन जापान अपने किसानों के हितों की रक्षा के मकसद से चावल पर ऊंचा शुल्क लगाता है। लेकिन ये सर्वोच्च शुल्क अपवाद हैं और उन देशों में ज्यादातर व्यापार इतनी ऊंची दरों पर नहीं होता। देश के आयात शुल्क की सही तस्वीर उसके औसत टैरिफ से ही मिलती है।

भारत का 17 प्रतिशत का औसत टैरिफ अमेरिका के 3.3 प्रतिशत औसत से अधिक है। मगर यह दक्षिण कोरिया के 13.4 प्रतिशत और चीन के 7.5 प्रतिशत के करीब है। औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत का औसत शुल्क 13.5 प्रतिशत है और लेकिन आयातित मूल्य की इकाई के हिसाब से औसत शुल्क या ट्रेड वेटेड एवरेज देखें तो यह 9 प्रतिशत ही पड़ता है।

भारत नहीं अमेरिका तोड़ रहा डब्ल्यूटीओ के नियम: वैश्विक व्यापार के नियम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) तय करता है और भारत उसके शुल्क संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन अमेरिका ऐसा करता है। नियम तोड़े जाएं तो सदस्य देश डब्ल्यूटीओ से हस्तक्षेप करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि अमेरिका अक्सर भारत का नाम लेकर चिंता जताता है मगर उसने भारत के ऊंचे शुल्कों को डब्ल्यूटीओ में चुनौती नहीं दी है क्योंकि वह जानता है कि भारत का शुल्क डब्ल्यूटीओ की सहमति वाली सीमा के भीतर है।

जब 1995 में डब्ल्यूटीओ की शुरुआत हुई तब विभिन्न देशों ने उत्पादों पर अधिकतम शुल्क तय कर दिए जिन्हें 'बाउंड टैरिफ' (बाध्यकारी शुल्क) कहा गया और शुल्क उससे अधिक नहीं बढ़ाने पर भी वे रजामंद हो गए। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों ने कम बाउंड टैरिफ (लगभग 3-4 प्रतिशत) रखा था और भारत जैसे विकासशील देशों को अधिक टैरिफ (40-150 प्रतिशत) की इजाजत दे दी गई। मगर विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए ऐसा लचीला रुख अपनाते समय यह शर्त रख दी कि उन देशों को डब्ल्यूटीओ की वार्ता में बौद्धिक संपदा अधिकार और सेवाओं को भी शामिल करना होगा। कम बाउंड टैरिफ के कारण ही अमेरिका डब्ल्यूटीओ के नियम तोड़े बगैर शुल्क नहीं बढ़ा सकता। मगर भारत स्टील पर टैरिफ 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक कर सकता है और डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा क्योंकि स्टील पर बाउंड टैरिफ 40 प्रतिशत है।

किसी देश के बाउंड टैरिफ और वास्तविक टैरिफ के बीच का अंतर 'वाटर' कहलाता है। अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों का वाटर कम है, जबकि भारत का ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत के पास डब्ल्यूटीओ के नियम तोड़े बगैर शुल्क बढ़ाने की ज्यादा गुंजाइश है। अमेरिका डब्ल्यूटीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद नियमों के सहारे ही शुल्क बढ़ा सकता है। मगर यह दलील गले नहीं उतरेगी कि स्टील और एल्युमीनियम के आयात से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

एफटीए पर हिचक: भारत के ऊंचे शुल्कों की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वे दोबारा चुने गए तब वे भारतीय उत्पादों पर भी उतना ही शुल्क लगा देंगे। लेकिन भारत का शुल्क डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप है, इसलिए ट्रंप के कदम इन नियमों का उल्लंघन होंगे। अमेरिका मुक्त-व्यापार समझौते (एफटीए) के माध्यम से भारतीय बाजारों में बेहतर पैठ बना सकता है क्योंकि भारत पहले ही आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे एफटीए साझेदारों के लिए शुल्क कम कर चुका है। इससे पता चलता है कि व्यापार के लिए उसका रुख कितना उदार है। मगर एफटीए में दोनों पक्षों को शुल्क घटाना पड़ता है और अपने उद्योगों की हिफाजत के फेर में अमेरिका शुल्क कम करने से हिचक रहा है। यह हिचक इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क समझौते में साफ दिख रही है क्योंकि इसमें शुल्क कटौती शामिल नहीं है। इस समझौते में अमेरिका और भारत सहित 14 देश शामिल हैं, जिनका मकसद व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (कर तथा भ्रष्टाचार निरोधक) के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

भारत-अमेरिका संबंध: ट्रंप बार-बार भारत के ऊंचे शुल्कों की बात कर रहे हैं। इनसे उन्हें सुर्खियां तो मिल गईं मगर भारत-अमेरिका संबंध बेअसर रहे। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। उनका द्विपक्षीय कारोबार 2018 में 141.5 अरब डॉलर था, जो 2023 में 34.4 प्रतिशत बढ़कर 190.1 अरब डॉलर हो गया। वस्तु व्यापार 41.6 फीसदी और सेवा व्यापार 22.4 प्रतिशत तक बढ़ा। भारत से अमेरिका को निर्यात 54.4 प्रतिशत तक बढ़ा और अमेरिका से भारत को निर्यात 20.8 प्रतिशत तक बढ़ा।

अमेरिका-भारत साझेदारी का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और क्वाड अलायंस तथा यूएस-इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐंड ट्रेड इनीशिएटिव जैसी पहल के जरिये रक्षा संबंधों को बढ़ाना है। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और इनका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करते हुए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा पर भारत और अमेरिका के सहयोग से भारत को अपने तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।

साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग से डिजिटल सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का नेतृत्व मजबूत होता है, जिससे नवाचार और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। मगर अमेरिका कभी-कभी कारोबारी हितों को नीति से ज्यादा प्राथमिकता देता है। उदाहरण के तौर पर उसने लैपटॉप आयात रोकने की भारत की योजना का विरोध किया क्योंकि इससे ऐपल, डेल और एचपी जैसी अमेरिकी कंपनियां प्रभावित होंगी, जो चीन में लैपटॉप बनाती हैं। पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और लैपटॉप के वैश्विक बाजार का 81 प्रतिशत हिस्सा चीन के नियंत्रण में है और भारत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देते हुए इस पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका भी अपने उद्योगों के संरक्षण के लिए चीन के सेमीकंडक्टर और सोलर सेल जैसे उत्पादों पर शुल्क लगाता है। इससे पता चलता है कि भारत को बाहरी दबाव के आगे झुके बगैर अपनी अहम प्राथमिकताएं पूरी करनी चाहिए।

अंत में ट्रंप के शुल्क मसले का निष्कर्ष यह है कि भारत द्वारा शुल्क का दुरुपयोग किए जाने का उनका दावा सही नहीं है। लेकिन भारत को उत्पाद के स्तर पर शुल्कों में सुधार पर विचार करना चाहिए ताकि किफायती, मूल्यवर्द्धित विनिर्माण एवं व्यापार को बढ़ावा देने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को ज्यादा सहारा मिल सके।

(लेखक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव के संस्थापक हैं)

भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत ढाल

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से रुपया दबाव में आ गया है। पिछले सप्ताह यह अमेरिकी डॉलर की तुलना में 84 के पार चला गया। तनाव बढ़ता ही रहा तो दो कारणों से रुपये की चाल पर अनिश्चितता और बढ़ सकती है। पहला, पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव विदेशी निवेशकों में जोखिम भरे दांव खेलने का जज्बा कम कर सकता है, जिस कारण वे भारत से निवेश निकाल सकते हैं। दूसरा, तनाव से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे इसके दाम और बढ़ जाएंगे। भारत ईंधन की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए दाम बढ़ने से डॉलर की जरूरत भी बढ़ जाएगी। ईंधन के दाम बढ़ना भारत के लिए हमेशा सिरदर्द रहा है।

फिलहाल तेल के दाम नियंत्रण में हैं और भारत को भरोसा है कि वह वैश्विक वित्तीय एवं ऊर्जा बाजार की उठापटक से निपट सकता है। इस भरोसे ही बड़ी वजह भारत का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हाल ही में 700 अरब डॉलर पार कर गया।

विशाल मुद्रा भंडार और भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव काबू मे रहा है। इस वर्ष की शुरुआत से रुपया महज 1 प्रतिशत कमजोर हुआ है। कुछ अर्थशास्त्री तो कह रहे हैं कि यह उठापटक बहुत कम है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के कई कारण हैं और उदारीकरण के बाद भारत कुछ मौकों को छोड़कर लगातार ऐसा करता रहा है। रिजर्व बैंक मुख्य रूप से अनिश्चितता कम करने के लिए ही विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है।

देश के वित्तीय तंत्र से विदेशी रकम अचानक निकलने पर विदेशी मुद्रा भंडार बीमा की तरह काम करता है। भारत दूसरे देशों से और भी ज्यादा जुड़ रहा है, इसलिए वैश्विक स्तर पर होने वाली उठापटक का सामना करने के लिए इसके पास पर्याप्त मुद्रा भंडार होना चाहिए। उथल-पुथल बढ़ने पर मुद्रा बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है और वास्तविक आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के कारण कमोडिटी के दाम एकाएक चढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ गया था तब अत्यधिक उतार-चढ़ाव को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था। इस बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व और उसके बाद कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने जब मौद्रिक सख्ती की तो भारत से रकम निकासी तेज हो गई। विदेशी निवेशकों ने जनवरी और जून 2022 के बीच 30 अरब डॉलर से अधिक के शेयर एवं बॉन्ड बेच डाले। इस दोहरे झटके से निपटने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2022 तक 525 अरब डॉलर रह गया, जो जनवरी में 635 अरब डॉलर था। हालांकि कुछ कमी तो वैश्विक मुद्रा बाजार में जबरदस्त उठापटक के कारण पुनर्मूल्यांकन किए जाने का नतीजा भी रही होगी मगर रिजर्व बैंक रुपये में उतार-चढ़ाव को इसलिए काबू में रख पाया क्योंकि उसके पास डॉलर का विशाल भंडार था और वह उसका इस्तेमाल करने को तैयार था।

अर्थतंत्र
राजेश कुमार

विशाल मुद्रा भंडार देश के वित्तीय तंत्र से पूंजी निकलने पर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सहायक हो सकते हैं। अर्थशास्त्री चेतन घाटे एवं अन्य ने एक नए शोध पत्र में कहा है कि वैश्विक वित्तीय संकट की स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार देश से पूंजी बाहर जाने की रफ्तार कम कर देता है। आंकड़ों का हवाला देते हुए शोधपत्र कहता है कि दरें घटाने बढ़ाने पर डेट पोर्टफोलियो में आने वाली अनिश्चितता भी इससे कम हो जाती है। कुल मिलाकर नतीजे बताते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय बाजार के जोखिमों का असर कम कर देता है।

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र एवं अन्य द्वारा तैयार एक शोध पत्र में कहा गया है कि कोविड महामारी, वैश्विक वित्तीय संकट (अमेरिका के साथ ब्याज दरों के बीच अंतर में कमी) और अनिश्चितता सूचकांक में कमी जैसे हालात में वास्तविक उत्पादन में गिरावट के कारण किसी वर्ष घरेलू सकल उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत के बराबर (लगभग 100 अरब डॉलर) विदेशी पूंजी निकासी की आशंका 5 प्रतिशत तक होती है। जोखिम बहुत ज्यादा हो तो पूंजी निकासी भी काफी अधिक रह सकती है। भारत में चालू खाते का घाटा है (जो इसकी निवेश जरूरतों को देखते हुए सही है) और विदेशी मुद्रा भंडार व्यापार आधिक्य के बल पर नहीं बना है, इसलिए 2022 सरीखे वैश्विक झटकों से निपटने के लिए अधिक मुद्रा भंडार रखना जरूरी हो जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा हो तो नीतिगत निर्णय लेने में भी आसानी होती है। उदाहरण के लिए कोविड महामारी के बाद भारत का सामान्य सरकारी बजट घाटा काफी अधिक हो गया था और सार्वजनिक ऋण भी काफी अधिक हो गया था। 2022 में जब दुनिया में ब्याज दरें तेजी से बढ़ रही थीं तब स्थिति और विकराल हो सकती थी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अधिक बजट घाटा निवेशकों का विश्वास टूटने का एक बड़ा कारण था और 2013 में तो इससे लगभग मुद्रा संकट ही पैदा हो गया था। मुद्रा भंडार मजबूत होने पर रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाते समय भी मुद्रास्फीति एवं वृहद आर्थिक हालात पर आसानी से नजर रख सका। फेडरल रिजर्व ने नीतिगत ब्याज दरें 500 आधार अंक तक बढ़ा दीं लेकिन रिजर्व बैंक ने रीपो दर केवल 250 आधार अंक ही बढ़ाई, जिससे यील्ड में अंतर कम हो गया।

स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार अधिक रहने से उठापटक संभालने और नीति लचीली बनाए रखने में मदद मिली है, इसलिए इस पर भी बहस होनी चाहिए कि रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को कितना बढ़ाए। ऊपर बताए गए एक शोधपत्र में कहा गया है कि भारत का मुद्रा भंडार पर्याप्त एवं बेहतर स्थिति में है। ध्यान रहे कि अधिक मुद्रा भंडार के भी नुकसान हैं। यह नुकसान अमूमन ब्याज का हो सकता है क्योंकि रिजर्व बैंक सरकारी बॉन्ड के बदले विदेशी परिसंपत्तियां (जैसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड) जमा कर रहा है, जिस पर कम यील्ड मिलती है। मगर यह नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है।

अहम सवाल यह है कि अधिक विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा में स्थिरता से देश में पूंजी निवेश बहुत अधिक होने लगे तो? ध्यान रहे कि भारतीय बॉन्ड जाने-माने विदेशी सूचकांकों में शामिल किए जा रहे हैं। निवेशकों में विश्वास बढ़ने और अधिक बॉन्ड जारी होने से वास्तविक निवेश वैश्विक सूचकांकों में भार की तुलना में कहीं अधिक हो सकता है। पूंजी प्रवाह ऊंचे स्तर पर बने रहने और बाजार में रिजर्व बैंक के सक्रिय हस्तक्षेप से मौद्रिक नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियां आ सकती हैं। इससे रुपया चढ़ सकता है और निर्यात में भारत की बढ़त पर असर पड़ सकता है। इस समाचार पत्र में खबर थी कि हालिया गिरावट के बाद भी रुपया अगस्त में 5 प्रतिशत महंगा था। रुपया लंबे समय तक ऊंचा रहे तो आर्थिक वृद्धि और वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा हो सकते हैं। भारत के इतिहास को देखते हुए विशाल मुद्रा भंडार मौजूद रहने पर भी बाह्य क्षेत्र के कुशल प्रबंधन की जरूरत होगी।

आपका पक्ष

दीवाली में प्रदूषण रोकने के लिए उठे कदम

हर साल दीवाली के समय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। वहीं दीवाली के दिन पटाखे जलाने के कारण वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर भी पार कर जाता है। इस साल वायु प्रदूषण से बचने के लिए अभी से कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पिछले कुछ दिनों से पराली जलाने की खबरें आ रही हैं जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। अतः इसपर रोक लगाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने दीवाली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है लेकिन हरित पटाखे पर प्रतिबंध पर संशय है। केंद्र और राज्य सरकार को दीवाली से छठ पर्व तक सभी तरह के पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सोमवार को आईटीओ चौराहे से 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान की शुरुआत की गई

त्योहारों पर मिला जुला रहेगा कारोबार

सभी कारोबार के लिए इस बार का त्योहार मिला-जुला ही रहेगा। अभी भी वैश्विक मंदी का दौर है जिन्हें धन की जरूरत है, उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए खरीदारी नहीं बढ़ पाएगी। फिर भी दोपहिया वाहन, मोबाइल, लैपटॉप, खाद्य पदार्थों की खरीदी के लिए त्योहार महत्त्वपूर्ण रहेगा।

प्रदीप गौतम सुमन, रीवा

त्योहारी कारोबार फीका रहने की संभावना

कारोबार की दृष्टि से इस बार के त्योहार कुछ फीके रहने की संभावना है। अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। खरीफ फसलों की समय पर कटाई नहीं हो पाई है। किसान अपनी उपज बेच नहीं पाए हैं। इस वजह से उनके पास नकदी का अभाव बना हुआ है। माह के अंत में दीवाली का त्योहार होने के कारण नौकरीपेशा वर्ग की भी क्रय शक्ति कम रहेगी।

ललित महालकरी, इंदौर

त्योहारों से कारोबार में आई रौनक

हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीवाली की तैयारी देश में जोर शोर से चल रही है। दीवाली में हर घर में साफ सफाई, रंगाई पुताई, नई चीजों की खरीदारी व नए कपड़े आदि वस्तुओं की खरीदारी से बाजार में रौनक आ जाती है। इस समय देश के सभी बाजारों में बहुत ही भीड़भाड़ चल रही है। ग्राहक अपनी जरूरत व हैसियत से खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही मेक इन इंडिया के कारण अपने देश में बने हुए सामान की ही बिक्री ज्यादा हो रही है। जिससे स्थानीय निर्माण इकाइयों को काम मिल रहा है।

रजनी मंगल, मुरैना

ग्राहकों से गुलजार बाजार

दीवाली का त्योहार हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार माना गया और इस बार अमीर गरीब सभी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। बाजार ग्राहकों से गुलजार है। सभी तरह के व्यापार इलेक्ट्रॉनिक, गृह उपयोगी मशीनों से लेकर सोने चांदी तक लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। बेशक ऑनलाइन व्यापार ने स्थानीय व्यापार पर असर डाला है। मगर कुल मिलाकर सभी व्यापारी इस बार त्योहारी ग्राहकी से बहुत ही खुश हैं।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के 'हॉट स्प्रिंग्स' में 21 अक्टूबर, 1959 को भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 10 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। तब से ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 'पुलिस स्मृति दिवस' मनाया जाता है।